CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.II, Second Session, 2009/1931 (Saka)
No.2, Friday, July 3, 2009/ Asadha 12, 1931 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 21 to 24	3-38
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 25 to 40	39-135
Unstarred Question Nos. 174 to 312	136-437

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 438-454

BUSINESS OF THE HOUSE 455-457

ELECTIONS TO COMMITTEES 458-466

(i) Committee on Estimates 458

(ii) Committee on Public Accounts 459

(iii) Committee on Public Undertakings 460

(iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes 461-462

(v) Rajghat Samadhi Committee 463

(vi) Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee 464

(vii) Central Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 465

(viii) Committee on Official Language 466

RAILWAY BUDGET, 2009-2010 467-505

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
1st Report 506

DISCUSSION UNDER RULE 193
Situation arising out of Rapid spread of swine flu in the country 507-527

Shri Sandeep Dixit 507-515

Shrimati Maneka Gandhi 516-522

Shri Shailendra Kumar 523-525

Dr. Ram Chandra Dome 526-527

PRIVATE MEMBERS' BILLS – INTRODUCED 528-531

(i) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2009
(Amendment of section 11, etc.)

By Shri Francisco Cosme Sardinha 528

(ii) UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL , 2009
By Shri Baijayant Panda 528-529

(iii) PERSONS AFFECTED BY NAXALITE TERRORISM (RELIEF AND REHABILITATION) BILL, 2009
By Shri Baijayant Panda 529

(iv) CITIZENS AFFECTED BY CYCLONE, SUPER CYCLONE OR TSUNAMI IN COASTAL AREAS (COMPENSATION, REHABILITATION AND WELFARE) BILL ,2009
By Shri Baijayant Panda 530

(v) PREVENTION OF UNSOLICITED TELEPHONIC CALLS AND PROTECTION OF PRIVACY BILL, 2009
By Shri Baijayant Panda 531

(vi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 (Amendment of the Eighth Schedule)
By Shri Arjun Ram Meghwal 531

RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF NATIONAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES 532-583

Shri Virender Kashyap 532-542
Shri Satpal Maharaj 543-545
Shri Anurag Singh Thakur 546-548
Shri Vijay Bahuguna 549-551
Dr. Rajan Sushant 552-555
Shri Adhir Chowdhury 556-561
Shri Ramen Deka 562
Shri K.C. Singh ‘Baba’ 563-565
Shri Joseph Toppo 566-567
Shri Pradeep Tamta 568-572
Shri Tathagata Satpathy 573-575

Shri Om Prakash Yadav	576
Shri Prem Das Rai	577-579
Shri Thangso Baite	580-581
Dr. Thokchom Meinya	582-583

ANNEXURE –I

Member-wise Index to Starred Questions	589
Member-wise Index to Unstarred Questions	590-591

ANNEXURE-II

Ministry-wise Index to Starred Questions	592
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	593

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 3, 2009/ Asadha 12, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं0 21, डॉ. विनय कुमार पाण्डेय।

…(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदया, बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर बनी लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया प्रश्न काल होने दीजिए। इसे शाम को ले लेंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: डॉ. विनय कुमार पाण्डेय।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदया, यह तो अतिक्रमण है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) … **

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदया, यह तो सीनियर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। हम जैसे प्रथम बार चुनकर आये लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपना क्वेश्चन नं0 बोलिए।

…(व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदया, आज जब नारी सशक्तीकरण की बात की जा रही है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपना क्वेश्चन नं0 बोलिये।

…(व्यवधान)

(Q. No. 21)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदया, आज नारी सशक्तीकरण की बात कही जा रही है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन में महिला विधेयक लाने की बात कही जा रही है।...(व्यवधान) आज लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन की पीठ पर एक नारी शक्ति आसीन है। यूपीए चेयरपर्सन के रूप में नारी शक्ति मौजूद है। ऐसे समय में महिला उत्पीड़न की जो बातें प्रकाश में आ रही हैं, मैं उन्हें आपके सज्ञान में लाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयाः आप अपना प्रश्न संक्षेप में पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः इनके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदयाः आप संक्षेप में पूछिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदया, आज प्राइवेट आर्गनाइजेशंस और एजेंसियों द्वारा महिलाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट आर्गनाइजेशंस और प्राइवेट एजेंसियों में महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न और शोषण करके उनका कैरियर खराब किया जा रहा है।...(व्यवधान) अभी पिछले दिनों में ही ऐसी घटनाएं प्रकाश में आयी हैं। पिछले सदन में भी यह बात उठी थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप संक्षेप में बोलिये।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : महोदया, मानसिक उत्पीड़न का पंजाब का एक प्रकरण है जो हमारे संज्ञान में आया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः आप संक्षेप में बोलिये।...(व्यवधान)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : उस प्रकरण पर सरकार क्या कर रही है और क्या इस विधेयक को लाकर सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी? क्या सरकार उस प्रकरण को सज्ञान में लेते हुए उत्पीड़न और शोषण को रोकने का प्रयास करेगी? मैं आपके माध्यम से अनुमति चाहूंगा, क्योंकि कुछ पत्र हमारे पास मौजूद हैं, जो मानसिक उत्पीड़न और शोषण के प्रतीक हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके माध्यम से उन्हें सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। महिला आयोग, यूपीए चेयरपर्सन तथा सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले लाकर शोषण को रोकने के प्रयास किये जाएं।

अध्यक्ष महोदयाः आप संक्षेप में बोलिए। इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए। आप बैठ जाइए।

---

* Not recorded

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या सरकार मानसिक उत्पीड़न और शोषण को रोकने का प्रयास करेगी? क्या सरकार ऐसा विधेयक लाकर उसे रोकने का प्रयास करेगी? आदिवासी और पिछड़े इलाकों से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इतना लंबा प्रश्न नहीं करते हैं। आप बैठ जाइए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, वह पंजाब से रिलेटेड है। वह पूछना चाहते हैं कि महिलाओं का जो मानसिक उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, उसको रोका जाएगा या नहीं, मैंने इसके संदर्भ में बहुत डिटेल में टेबल पर कागज रखे हैं। इसके बाद ऐसी शिकायतें आती हैं। आर्गनाइज्ड और अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में ऐसा हुआ है। आर्गनाइज्ड सैक्टर में तो आलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक कमेटी है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except the Question Hour.

(Interruptions) ... *

श्रीमती कृष्णा तीरथ : सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हरेक ऑफिस में एक कमेटी तैयार है जो इस तरह के केसेज़ देखती है। माननीय सदस्य ने जो बात आपके माध्यम से पूछी है, मैं कहना चाहती हूँ कि हम जल्दी ही एक विधेयक लाना चाह रहे हैं। उसके कुछ विषयों पर दूसरे मंत्रालय और विभाग से...(व्यवधान) लॉ मिनिस्ट्री से अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही वह होगा, हम दूसरा विधेयक लाकर इन तमाम आर्गनाइज़्ड और अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में जो कमेटी बनाएँगे, उसमें इस तरह के केसेज़ को देखा जाएगा और उसका पूरा निपटारा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा सप्लीमैंट्री पूछिये।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पिछड़े, आदिवासी और जनजाति बहुल इलाकों से प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा नारियों को घरेलू नौकरानी के रूप में कुछ शातिर दिमाग के लोग ला रहे हैं, उन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है। उन नौकरानियों का शोषण होता है। क्या इसे रोकने के लिए भी इस विधेयक में उचित प्रावधान होंगे, या उन पिछड़े इलाकों से लोगों को लाकर प्राइवेट आर्गनाइज़ेशंस द्वारा नौकरियों में रखा जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था होगी? क्या इस विधेयक में इसका कोई प्रावधान होगा?

---

* Not recorded

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, जैसे मैंने पहले बताया, यह विधेयक लाया जा रहा है। यह अनआर्गनाइज्ड और आर्गनाइज्ड दोनों सैक्टर्स में काम करेगा। जो उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरानियों को रखा जाएगा, उनका भी इसमें प्रावधान रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 22, श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी ।

(Q. No. 22)

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Thank you, hon. Madam Speaker.

Madam, the reply of the hon. Minister is in great detail with statistics. I thank the Minister for taking all the measures to contain the prices of essential commodities, which includes selective ban on exports and future trading in food grains, etc.

I feel that the Government urgently needs to shift the method of calculating inflation. The Ministry knows that there are flaws in the present method of calculating inflation. The Government should adopt methodologies of the developed economies. When we are adopting many things from the West, why can we not adopt the method adopted by them? India is adopting the method of Wholesale Price Index for calculating inflation rate. Most developed countries use their Consumer Price Index to calculate inflation. May I know from the hon. Minister, through you, Madam, whether the Ministry will adopt Consumer Price Index to calculate inflation? This is my first supplementary.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, it is correct that a large number of countries have accepted Consumer Price Index as the standard index, and they have adopted one integrated Consumer Price Index. Their level of development and growth has facilitated them to have a single Consumer Price Index. No country other than India is having one million plus people. Not only India but 24 other countries of the world, according to IMF study, also go by Wholesale Price Index. It is not correct to say that we do not have Consumer Price Index but we have Consumer Price Index because our people are living in different areas – urban and rural. We have four sets of Consumer Price Index. One is meant for the Industrial Workers. The second one is meant for the Agricultural Workers. The third one is meant for those who are living in the urban areas – urban non-manual employees – mainly the Government servants and the mercantile employees. The fourth index is meant for the rural labour apart from the

agricultural labour. Each specific group has different consumption pattern. Unlike the West or unlike the developed countries, the consumption pattern is not the same. Therefore, we have both the systems. We release the figures of the Consumer Price Index at the end of the month; and we release the figures of the Wholesale Price Index at the end of the week.

The rationality of accepting the Wholesale Price Index is that it covers wide range of items. More than 400 plus commodities are being covered, which are being shown in the wholesale market. But keeping that in view with the reforms, it has been decided that the National Statistical Organization should look into it as to whether we can have, at least, these two consumer price indices brought together. So, the Central Statistical Organisation has been mandated to find out whether these rural index and the urban index could be brought together. They are working on it. They would arrive at the final decision, which may take a little longer time to understand the number of people and varieties of consumption patterns.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : There is a dichotomy between the Wholesale Price Index and the Consumer Price Index. The people are wondering as to how the inflation figure is coming to zero whereas the prices of commodities are rising. Even the Chairman of the Prime Minister's Economic Advisory Panel Dr. Suresh Tendulkar had also said that the Wholesale Price Index as a standard measure for calculating inflation figures is unsatisfactory.

Therefore, in order to calculate the figures of inflation, would the Government introduce an All India Consumer Price Index for the rural and urban population and do away with the Wholesale Price Index?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I have already answered the second part of her question that the Central Statistical Organization is looking into this matter of merging these two indices – one for urban areas and the other for rural areas -- and evolving a mechanism. But it would take some time.

It is true, as she rightly said in her first Supplementary, that there has been a divergence between the Wholesale Price Index and the Consumer Price Index. Unfortunately, the year 2008-09 had become a very erratic year. So far as the price behaviour is concerned, the hon. Members would remember that in the first half of the fiscal 2008-09, the House was agitated, and several discussions took place. The Wholesale Price Index Headline Price Inflation was moving up because that was the worst phase all over the world. There were food crises, there were commodity crises. Then, the crude oil prices (energy prices) in August reached as high as 147 dollar per barrel. Then again, from the second half of the year starting from September, 2008, things changed dramatically. I would give you one example. The crude oil prices, which reached as high as 147 dollar per barrel in the middle of the year, came down drastically. My colleague, the hon. Minister of Petroleum also stated yesterday that when the crude oil prices came down to 40 dollar per barrel in January, we reduced the price of petrol, diesel and LPG. In the case of kerosene there was no question of increasing the price, and so there was no reduction. Its price remained as it is. But the prices of petrol, diesel and LPG were reduced.

This year, I do admit. Normally, there is a time lag. But there is a time lag curve of WPI and the curve of the CPI. They merge at the time lag of two months or three months and then they synchronize. Sometimes, it is a little less.

But, unfortunately, this year because of varieties of reasons, it has not happened so. But still it is coming down.

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो ब्यौरा दिया है, यह थोड़ा गुमराह करने वाला दिखाई देता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ऊषा थोरट जी ने कुछ दिन पहले कोलकाता में कहा है कि हम लोग अपने देश में जो स्माल सेविंग्स करते हैं, उसका इंटरस्ट आठ प्रतिशत देते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दस प्रतिशत से ज्यादा जा रहा है। यह डिफरेंस क्यों हैं? हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमने स्माल सेविंग्स करने वाले लोगों की स्थिति का

अध्ययन किया है? हम एफडीआई के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर नेशनल डोमेस्टिक स्माल सेविंग्स के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो इसका क्या परिणाम होगा?...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

श्री अनंत कुमार हेगड़े : अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न ही पूछा है। हम वित्त मंत्री जी से अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि हमारे प्रश्न का क्या उत्तर है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am not misleading the House by giving any other figure. The hon. Member's question is totally different. Here, the Question relates to inflation. If the hon. Member reads the answer, he will find that there are two indices. In fact, as I mentioned earlier, in India we are having five indices. I would not like to repeat them to save the time of the House. Four are Consumer Price Indices and one is WPI. The Question is relating to that. To the question of encouraging small savings and others, I cannot respond to all these issues right now, particularly just on the eve of presenting the Annual Budget. The hon. Member can raise this question on any other occasion and properly formulate it. His question is not even remotely linked with the thrust of the main Question.

SHRI PRABODH PANDA : Madam Speaker, I want to know from the hon. Minister the reasons behind this. In the Question itself, it is there in part (c) and (d), namely "Whether inflation in India is measured by the Wholesale Price Index (WPI) and not the Consumer Price Index; (d) if so, the reasons therefore;" So, I want to know what was the reason behind for not taking into consideration the CPI but taking into consideration the WPI. What was the reason behind it? Why is this method being followed so far?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I have already stated this in the Statement. I have given a very exhaustive statement by explaining the entire area of concern. If the hon. Member takes care to go through the reply, in the Statement itself, in second paragraph 'c' and 'd', he will find the answer for this. As I have stated, "The CPIs are released on a monthly basis, with the composition and the item-wise weights of each index.." because each basket contains different items,

like CPI-for rural labourers, CPI-for industrial workers, CPI-for agricultural labourers, CPI-UNME for urban non-manual employees. The contents of these baskets differ. Therefore, the CPI will also differ. I have already answered as to why we are not going in for one index.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, my question to the Minister is this. Price rise is gradually going at a skyrocketed height at every moment. So, we do not know where to stop. Normally, the hoarders and black-marketeers are one of the main reasons for the price rise index in the whole of the country. The UPA Government at the initial stage issued a circular to all the State Governments that de-hoarding operations are to be launched on priority. I want to know from the hon. Minister whether this de-hoarding operation has been initiated in all the States of the country.

Madam, Part-B of my question is this. I want to know whether the Government of West Bengal, where there is a very unholy nexus in between the Party leaders and the blackmarketeers and hoarders has taken any action. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Please ask only one question. You have asked one question.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, the Question is the same – in A and B parts. I want to know this. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Just ask one question.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, I want to know whether the circular for dehoarding operation has been implemented by all the States of the country and particularly whether there is any nexus between the politicians and the hoarders and blackmarketeers in the State of West Bengal and whether they have not allowed the process or the procedure to launch dehoarding operation at any stage or in any scale. I want to know whether the hon. Minister has any such

information that any dehoarding operation has taken place in West Bengal in particular. … (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA : Madam, how far is this question relevant to the main question? This is on dehoarding. The main question is on inflation. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam Speaker, the reasons for inflation are many. … (*Interruptions*) Let me respond to the question. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : You are not to decide that. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Let me reply. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Hon. Minister is giving the reply. Please sit down. Hon. Minister is giving the reply.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam, I will respond to the question. I say that the reasons for inflation are many. Obviously, the basic economic reason is the imbalance between demand and supply. How does this imbalance come? There are many reasons. One of the reasons is the Consumer Price Index being stepped up because of the fact that we have enhanced substantially the procurement prices of the essential food grain items. If you just compare between the procurement price of wheat and paddy, which was in 2003-2004 and what was in 2008-2009 you will get an idea. The price of wheat has been enhanced by Rs. 350 per quintal and so far as paddy is concerned the price has been enhanced at Rs. 300 per quintal within a campus of four years. This would have its impact on the availability of the prices. Apart from that, there are sometimes shortages. The Government has always a mechanism for this. One mechanism is to restore the balance between demand and supply by augmenting supply if there is a short supply through import.

On the relevant part of the hon. Member's question in respect of the dehoarding operation, it is true. The position was that at one point of time this

power was taken from the States to the Centre. Three years before we asked the States and the power which was taken was reverted to the States and the States were asked to carry on the dehoarding operation. But, Madam Speaker, I have no hesitation to say that it has not been effective. Many of the States have not yet undertaken the dehoarding operation.

SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, may I draw the attention of the hon. Minister to the fact that concern has been repeatedly expressed that the Wholesale Price Index, which is the benchmark of headline inflation, at times does not reflect the true picture of inflation. Does the hon. Minister think that the time has come for us to revisit the manner in which the Wholesale Price Index is structured so that it can start reflecting the true picture of the inflammatory situation in the country?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Madam, I have already answered the question. There is no question of revisiting. We have already taken the decision to revisit. The CSO has been asked. This decision was taken in 2001. But it is not a very easy task to do it and switch it over overnight keeping the size of the various consumption patterns of different interest groups.

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि किसान के गेहूं और धान की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनकी सरकार की रिपोर्ट है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में 900 रुपए खर्च होते हैं। आपकी सरकार की रिपोर्ट है, सरकार द्वारा गठित कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है कि एक हजार रुपया खर्च होता है तो एक क्विंटल धान पैदा होता है। इसके अनुसार क्या आप बताएंगे कि किसान को कितना घाटा हो रहा है? आप कह रहे हैं कि किसान के धान और गेहूं की कीमत बढ़ गई, जबकि कीमत घटी है। आपके कृषि मूल्य आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि लागत खर्चे पर 50 फीसदी ज्यादा मूल्य किसान को मिलना चाहिए। क्या उसके अनुसार आप 1375 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत किसान को देंगे और क्या 1500 रुपये प्रति क्विंटल धान की देंगे, क्योंकि आप द्वारा गठित कृषि मूल्य आयोग ने रिपोर्ट दी है, जो आपके पास है कि किसान को घाटा हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है? आज माननीय नेता सदन ने जवाब दिया है कि किसान की गेहूं और धान की कीमत बढ़ गई है, जबकि वह बढ़ी नहीं है। क्या नेता

सदन यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि 50 फीसदी लागत खर्चे से ज्यादा देंगे, क्या उसके अनुसार 1375 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 1500 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत किसान को देंगे?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, the question is mainly directed to Agriculture Minister. Definitely, it is important.

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने गेहूं और धान की कीमत की बात की है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइये।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is a relevant question, but I will pass on the question to my colleague, Agriculture Minister. On one point, I would like to assure the hon. Member, who is an important leader and had wide experience in administration, that every year before fixing the prices of the agricultural commodities, we take into account the recommendations made by the Agricultural Price Commission and other relevant bodies. Taking into account all of them and the pattern which has been emerged, I would not like to burden the House with statistics, more than often it is found that we have surpassed their recommendations and added to it so that we can retain the interests of the farmers. As we have done it, the last year production of grains was more than 230 million tonnes. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइये। Shri Ananth Kumar.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, the hon. Finance Minister has noted that the Government monitors the price situation by various measures. He has said that the measures taken to contain prices of essential commodities include selective ban on exports and futures trading in food grains, zero import duty on select food items etc. My straight question to the hon. Minister, through you Madam, is this. Recent hike in petroleum and diesel prices, which has been done yesterday, will have a cascading effect on the inflation, especially inflation of CPI, Consumer Price Index. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India will assure the hon. House that they will take note of this, the seriousness of

the situation and the hardships that will be faced by the farmers and *aam admi* in the entire country, and roll back the petroleum prices forthwith. My question is whether they are going to roll back or not. Please let them say because that is one of the main reasons for the CPI inflation.

MADAM SPEAKER: This is a question meant for Petroleum Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, this is not within the purview of my domain.

MADAM SPEAKER: Yes.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: We are proceeding to the next Question. Q. No. 23 – Shri Ganesh Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, he is Leader of the House also. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: He has answered your question. Shri Ganesh Singh.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I am responding to the questions as Finance Minister, which have been addressed to me. When the question of responding as Leader of the House comes on certain occasions, I will do it. But this is not the occasion. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, that is not the question. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. Q.No. 23 – Shri Ganesh Singh.

(Q. No. 23)

श्री गणेश सिंह : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 2008 की तुलना में, जनवरी से लेकर अब तक जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए, उनकी संख्या काफी कम हुयी है। किसी भी देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं की जरूरत होती है, जैसे सुरक्षा। पिछले दिनों विदेशी पर्यटकों की जो संख्या कम हुयी है, उसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा का था, दूसरा एयर कनेक्टिविटी है, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक न होना, वह भी एक बड़ा कारण था, चौथा उनके ठहरने की ठीक ढंग से व्यवस्था का न होना था।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह : अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इस तरह के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उन प्रयासों की गति काफी धीमी है। उदाहरण के तौर पर मैं मध्य प्रदेश के उन पर्यटन स्थलों का नाम बता रहा हूं - खजुराहो, ओरछा, मांडू, सांची, चित्रकूट, मैहर, भोपाल, उज्जैन, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, कान्हा, बौद्धकालीन स्थल भरौत, देउरकुठा, रीवा, गिद्धकोट, रामनगर, आदि ऐसे कई स्थान हैं, जहां विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगातार हो रहा है, लेकिन वहां न ठीक से एयर कनेक्टिविटी है, न ठीक सड़कें है, इस वजह से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे खजुराहो और सतना को पूरे देश की हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम कराएगी?

कुमारी सैलजा : आपने जो बात एयर कनेक्टिविटी की कही है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से यह संबंधित विषय है, उनसे हम समय-समय पर इस बारे में बातचीत करते रहते हैं। केवल सतना की बात नहीं, पूरे देश भर में बहुत से डेस्टिनेशंस ऐसे हैं, जहां हमें एयर कनेक्टिविटी भी चाहिए और सड़कें भी अच्छी चाहिए। एयर कनेक्टिविटी के लिए हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार भी इसमें थोड़ा योगदान दे और सड़कें अच्छी बनाने के लिए वे भी थोड़ा प्रयास करें और हम भी यहां से उनकी जरूर मदद करेंगे। वे हमारे पास प्रपोजल भेजें कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आगे वे और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं। हम उनकी जरूर मदद करेंगे।

श्री गणेश सिंह : महोदया, राज्य सरकारों के सहयोग से जिस गति से नये पर्यटन स्थलों के विकास का काम हो रहा है, मैं मानता हूं कि वह बहुत धीमा है। कई ऐसे स्थान हैं, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनका विकास करने के लिए पूर्व में भी मैंने इस सदन में सुझाव दिया था। खास तौर पर मैं मध्य प्रदेश के उस सर्कल का नाम बताना चाहता हूं - ओरछा से लेकर खजुराहो और वाराणसी के बीच बहुत सारे ऐसे

पर्यटन स्थल हैं, जहां राज्य सरकार के सहयोग से उनको विकसित किया जा सकता था, लेकिन उधर भी ध्यान नहीं दिया गया। आज रेल बजट आएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह : आज रेल बजट आएगा। खजुराहो में रेल लाइन है, क्या दिल्ली से सीधा खजुराहो और सतना को जोड़ने लिए कोई शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए सिफारिश की जाएगी?

कुमारी सैलजा : मेरे ख्याल से हम सब रेलवे बजट का इंतजार करें, थोड़ी देर बाद देखें कि उसमें से क्या निकलता है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam, I would like to ask a Question. With a comprehensive reply, you have said that you will be talking to all the States. Could we have a plan with all the State Governments to tap district-wise and have a detailed mapping as to how each district can promote tourism with the help of the Central Government?

Further, a lot of issues are pending -- like in the State of Maharashtra from where I come -- with the Archaeological Department. Could that also be expedited so that we can use it for the livelihoods of all the locals who live in villages around sea spots, tourism spots, adventure spots, that is, all the spots and sea beaches?

KUMARI SELJA: Madam, I must say that Maharashtra is very forthcoming, as far as tourism destinations are concerned. In the Tenth Plan, we have sanctioned 52 projects worth more than Rs. 8,000 lakh. In the Eleventh Plan, we have already sanctioned eight projects worth more than Rs. 5,000 lakh for the State of Maharashtra. It also includes two Mega Circuits – one in Vidarbha and the other one in Aurangabad. However, if there are any more projects which are coming from the State, I can assure the hon. Member that we would definitely examine them in a very positive way under our scheme. If it is especially from the hon. Member's own constituency, we will definitely examine it under our scheme..

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam, no doubt, we are aware that tourism sector has a great potentiality insofar as employment in our country is concerned. It already contributes nearly six per cent to our GDP and nine per cent of

employment. From the reply, it has been found that the number of foreign tourists' arrival has increased from 4.45 million in the year 2006 to 5.37 million in the year 2008. It is a slight increase, no doubt.

In view of the Commonwealth Games which we are going to host in our country in the year 2010 the number of foreign tourists' arrival is targeted to the tune of 10 million for the year 2010 may I know from the hon. Minister whether the Government is going to revise the foreign tourists' arrival target so that we can have an idea as to whether we are going to make the target a success or not?

KUMARI SELJA: Yes, definitely, we expect many more foreign tourists' arrivals during the Commonwealth Games. There was a slight decline in the number of foreign tourists' arrivals in the first few months of this year, but we have been able to arrest that, and the foreign tourists' arrivals are picking up. I am sure it will go up further, especially during the time of Commonwealth Games, which are to be held in New Delhi. We expect that at least one lakh tourists would be coming to see the Commonwealth Games.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : What about the target and whether the target was revised or not?

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण 26/11 को मुम्बई में आतंकी हमला होना है। यह सवाल पर्यटन मंत्रालय से है। मैं यहां आतंकी हमले के बारे में सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या आपके मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में कोई उपाय किए हैं? यदि किए हैं तो वे क्या हैं?

कुमारी सैलजा: मैडम, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में काफी लम्बा जवाब दिया है। गृह मंत्रालय से हमारी बातचीत हुई है। मुझसे पहले जो मंत्री जी थे, उनकी भी बातचीत हुई थी। हमारा मंत्रालय लगातार गृह मंत्रालय के साथ इस बात पर डिस्कशन करता है। मुम्बई में ब्लास्ट हुआ, केवल उससे फर्क नहीं पड़ा, इकोनॉमिक स्लो-डाउन भी था जिसके कारण फॉरेन टूरिस्ट्स एराइवल में फर्क पड़ा था। हमें दोनों चीजों को देखते हुए अपने देश में टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। उसके अलावा

विदेशों से और टूरिस्ट्स यहां आएं, उसके लिए भी हम जो अनेक कार्य कर रहे हैं, मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने दिखाए हैं। हम चाहेंगे कि हमारे देश में और भी फॉरेन टूरिस्ट्स आएं।

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, in the answer given by the hon. Minister, it has been stated that there is a reflection of the global recession, which was seen in other sectors, in the tourism sector also, and that the Government has taken a number of measures, which have been mentioned in the statement. As far as tourism is concerned, I think, the development of infrastructure is the better way to strengthen the tourism. Kerala is a tourist State. At the same time, tourists face a lot of difficulty as far as infrastructure development and fares are concerned. As is stated earlier, it does not come under this Ministry. I do understand that … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please put your question.

SHRI P. KARUNAKARAN : At the same time, considering the importance of this infrastructure development, may I know from the hon. Minister whether she will take the initiative to have coordination with the other Ministries especially about the States which have got the tourism potential.

KUMARI SELJA: We have done that in the past and we shall continue to do that in the future also.

अध्यक्ष महोदया : श्री लालू प्रसाद यादव।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, हम यादव नहीं प्रसाद हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने अभी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि विदेशी पर्यटक विगत दिनों बहुत कम आ रहे हैं। क्या आपके विभाग ने यह पता लगाया है कि गुजरात दंगों के बाद अमेरिकी शासन ने अपने नागरिकों को भारत आने से मना कर दिया था और स्पेशली कहा था कि गुजरात मत जाओ। उस बंदिश को अपलिफ्ट किया या नहीं, क्या आपने इसे पता करने की कोशिश की है?

कुमारी सैलजा : मैडम, जब हमारे देश में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तब दूसरे देशों से समय-समय पर ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। विदेश मंत्रालय और टूरिस्ट आफिसेज के माध्यम से हम इसे उन देशों के साथ टेकअप करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यह कम हो जाये, ताकि वहां से लोग

ज्यादा आयें लेकिन यह ऑनगोइंग प्रौसेस है। बहुत देशों ने अपनी एडवाइजरी को रिवाइज किया है और यह चलता रहता है। दूसरे देशों में भी दंगे होते हैं या कुछ इंसीडेंट्स होते हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रौसेस है। हमारी निरन्तर कोशिश होती है कि हम उन एडवाइजरीज के खिलाफ आवाज उठायें।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है। आप पता लगाइये कि क्या उस बंदिश को अपलिफ्ट किया गया या नहीं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 24, श्री निशिकांत दुबे ।

(Q. No. 24)

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम जोरों से चल रहा है। मैं गोड्डा क्षेत्र से आता हूं जो झारखंड में है। वहां दलित और आदिवासियों की पापुलेशन सबसे ज्यादा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी वहां बिजली नहीं आयी है। आज वे खुश हैं कि वहां बिजली आने वाली है। लेकिन मुझे आज ही कलैक्टर गोड्डा और कलैक्टर देवघर का एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि गोड्डा में 1577 गांवों में इलैक्ट्रीफिकेशन होना है, लेकिन मात्र 172 गांवों का ही इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। यह टारगेट 31 दिसम्बर 2009 तक पूरा होना था। इसके साथ-साथ कलैक्टर देवघर ने मुझे कहा है कि उनके यहां 2346 गांवों का इलैक्ट्रीफिकेशन होना है, जिसमें अभी तक मात्र 1016 गांवों का ही इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है। उनका टारगेट मार्च 2009 तक पूरा होना था। मैंने मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा था कि आरएसी का प्रौजेक्ट एनटीपीसी इम्प्लीमैंट कर रही है जिसका टारगेट नहीं है। इस संबंध में आपका जवाब भी ठीक नहीं था। अगर आप कहें ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री निशिकांत दुबे : मेरा प्रश्न यह है कि मार्च 2009 और दिसम्बर 2009 का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह टारगेट कब तक पूरा होगा?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदया, झारखण्ड में यह बात सही है कि वहां काम में थोड़ी ढिलाई है क्योंकि वहां दो-तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वहां पर फॉरेस्ट्स हैं जिसकी वजह से वहां पर जगह नहीं मिलती है। हमने वहां के मुख्यमंत्री और उनके ऑफिसर्स से बात की है। दसवीं योजना में जो 13 जिले रह गए हैं, उनको अगस्त, 2009 तक पूरा करने का आश्वासन हमें दिया गया है और जो ग्यारहवीं योजना के हैं, वे मार्च, 2010 तक पूरा करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। अभी तक हमने 2023.54 करोड़ रुपए की राशि झारखण्ड को दी है। वे उसका अच्छी तरह से इंतजाम करें, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। झारखण्ड ही नहीं, पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि वे अपने यहां एक जिला स्तर की कमेटी बनाएं जिसमें एमपीज, एमएलएज एवं जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य हों । इस प्रकार की सूचना हमने सभी को दी है, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कमेटीज नहीं बनी हैं। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कमेटी के बारे में आप भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं झारखण्ड पर पूरा ध्यान दूंगा। झारखण्ड एक ऐसा प्रान्त है, जहां हम विशेष रूप से पैसे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात यह भी है कि हम 33 के.वी. पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण करते हैं, लेकिन वह एक डिफिक्लट टेरेन है, वहां पर मिलिटेंसी भी है, इसकी वजह से 132 के.वी. का प्रपोजल हमारे पास डिस्कशन के लिए आया था

कि केवल 33 के.वी. से काम नहीं होगा, इसके लिए भी जो पैसा चाहिए था, उसके लिए हमने आरईसी से 1,000 करोड़ रूपए की राशि का लोन उनको दे दिया है।

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस समय वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राज्यपाल हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन है, इसलिए वहां कोई एमएलए भी नहीं है और वहां पर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर कोई जिला परिषद अध्यक्ष एवं मुखिया भी नहीं है। मेरे अलावा वहां कोई नहीं है और सरकार आप चला रहे हैं।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सर्कुलर हमने 23 मई, 2008 को भेजा था, उस समय वहां पर राज्य सरकार अस्तित्व में थी।

श्री निशिकांत दुबे : वहां अभी क्या स्थिति है? आपने वर्ष 2010 का टारगेट रखा है।

अध्यक्ष महोदया, बीपीएल के बारे में इन्होंने कहा है कि इसे 1500 से बढ़ाकर 2200 कर दिया है। पहले तो बीपीएल का जो सर्वे हुआ है, उसकी एजेंसी क्या है? आज मेरी कलेक्टर से बात हुई, उसने कहा कि वह सर्वे इतना फेक है कि मुझे खुद ही उसके बारे में जानकारी नहीं है। दोनों जिलों के कलेक्टर्स मुझे यह बता रहे हैं। दूसरे, बीपीएल के लिए आप जो कनेक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बीपीएल के लोग हमेशा बीपीएल ही नहीं रहेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे, वे अमीर भी बनेंगे। लेकिन आज एक बल्ब के अलावा वे दूसरा बल्ब नहीं जला सकते हैं। यदि वे फ्रिज चलाएंगे तो फ्रिज खत्म हो जाएगा। आपने स्कूल में कनेक्शन देने की बात कही है, आपने कहा है कि आंगनवाड़ी में कनेक्शन देंगे, लेकिन वहां स्थिति यह है कि अगर एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन होता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। बीपीएल के मामले में भी मेरा यह कहना है कि जैसे देवघर जिले में एक लाख लोग बीपीएल हैं, गोड्डा जिले में दो लाख बीपीएल हैं, जबकि आप कनेक्शन्स केवल 20,000 या 22,000 लोगों को दे रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि यदि वहां पर बिजली का तार जा रहा है तो आपको कोई लांगटर्म व्यवस्था करनी चाहिए। बीपीएल के लोग एक ही कनेक्शन लें, उसके लिए ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी आप बढ़ाएं, जिससे वह इरीगेशन के परपज में भी काम करे, फ्रिज चलाने का काम हो, जब उनके बच्चे आगे बढ़ जाएं तो वे एसी चला सकें। मैं इसके बारे में मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

श्री सुशीलकुमार शिंदेः महोदया, मैंने सम्मानित सदस्य को बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि जहां आज बिजली नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वहां एक बल्ब तो जले। लेकिन वहां यह डिफिकल्टी है कि 33 के.वी. का ट्रांसफार्मर है, उसके बदले वहां 132 के.वी. के लिए हमने पैसे दिए हैं ताकि वहां ट्रांसफार्मर जल न जाए। इसके लिए हमने उनको स्पेशल सहयोग दिया है।

बीपीएल की लिस्ट के बारे में आपने जो कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि हर पांच साल में बीपीएल की लिस्ट बदलती है, उसके बारे में हम अवश्य ही राज्य सरकार को लिखेंगे।

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any provisions to cover those villages which have been left out of the current RGGVY guidelines due to non-meeting of the population criteria or cost criteria.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Some of the proposals have been coming from different States and they are under consideration.

चौधरी लाल सिंह : मैडम स्पीकर साहिबा, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो स्कीम बनाई, तो जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उस राज्य के लोकल इंजीनीयर्स ने उसे एनएचपीसी को दे दिया। एनएचपीसी ने उसे आगे एल. एंड टी. को सबलेट कर दिया और फिर वह चौथी जगह चली गई। इस कारण लागत बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से जहां दस पोल लगने थे, वहां एक ही लगा। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि वहां जो ट्रांसफारमर्स लगाए गए हैं, एक साल हो गया, अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया, जबकि इतना पैसा खर्च हो चुका है। जहां नहीं लगे और जो रह गए, वह तो रह गए, लेकिन जहां लगे, वहां कनेक्शन नहीं मिला। इसलिए जब योजना बनानी थी, उस वक्त ही क्यों नहीं इन लोगों को इसका जिम्मा सौंपा गया और इतना खर्च क्यों किया गया?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, जब राज्यों से डीपीआर आती है, तब यह कंडीशन लगाई जाती है कि छः से आठ घंटे तक वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत बिजली देंगे। इस प्रकार का उनकी तरफ से जब लिखित आश्वासन दिया जाता है, तब ही यह योजना मंजूर की जाती है। इस तरह की योजना आपके यहां भी मंजूर की गई है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं वहां बिजली मिल रही है। आपने जो कहा है, मैं इसकी जरूर जांच कराऊंगा।

श्री शरद यादव : मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जनता का इतना पैसा इस स्कीम के तहत दिया गया है, आपकी नई सरकार बनी है, यह बहुत कठिन काम है। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी राज्यों के बिजली मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं और इस पर चर्चा करें। हालत बहुत खराब है। मैं भी कई जगहों का दौरा करके आया हूं और मैंने देखा है कि आपकी यह योजना जमीन तक नहीं पहुंची है, जबकि इतना पैसा इसमें लगा हुआ है। इसलिए आप कुछ हलचल तो करें, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आप तत्काल राज्यों के बिजली मंत्रियों की आठ-दस दिन में बैठक बुलाएं और इस पर ध्यान दें। इस पर मंत्री जी का क्या कहना है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने पिछले हफ्ते ही देश के सभी राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उन्हें सूचना दी है तथा काम जारी रखने को कहा है। इतना ही नहीं, केपेसिटी एडिशन में जो कमियां आ रही थीं, उनके बारे में भी बैलेंस आफ प्लांट के आर्डर दे दिए हैं। जुलाई के आखिर तक हमने हर राज्य को बैलेंस आफ प्लांट की सूचना देने के सख्ती से आर्डर दे दिए हैं। हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना के कार्यक्रम को बहुत सख्ती से देख रहे हैं और उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। हमें इस योजना के तहत अभी 28,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत पैसा मिला है। मैं यह भी विनती करना चाहता हूं कि जहां-जहां भी लोकल कमेटीज हैं, वे भी थोड़ा इस पर ध्यान दें, उससे हमें भी फीडबैक मिलेगा और हम भी कार्रवाई करेंगे।

श्री शरद यादव : आप खुद जाकर हालात देखें।

श्री रेवती रमन सिंह : मैडम स्पीकर जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा शरद यादव जी ने कहा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन का आप सर्वे तो करा लें। आप देखेंगे कि इतना घटिया काम हुआ है कि एक आंधी आने पर ही खम्भे और तार गिर गए। लेकिन कागजों में लिख दिया जाता है कि विद्युतीकरण हो गया, जबकि वास्तव में नहीं हुआ। जैसा शरद यादव जी ने कहा है कि एक बार आप सर्वे करा लें और देख लें कि क्या काम हुआ है। मैंने पहले भी कहा था और आपने सदन में

आश्वासन भी दिया था कि तमाम मजरे और पूरबे जो 100 की आबादी के हैं, उनमें हम विद्युतीकरण कराएंगे। आपको इस काम के लिए योजना आयोग से 28,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं, जैसा कि आपने भी अभी बताया है। मंत्री जी इन दोनों बातों को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मज़रे की बात आपने पिछली लोक सभा में की थी। उसके बारे में यह है कि जहां 100 से अधिक लोगों की संख्या होगी, वहां की सभी बस्तियां और मज़रे हमने इस स्कीम में ले लिये हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने कहा है तो हमने वहां खम्बे लगाए हैं, गिराए नहीं हैं। हम सरकार को बार-बार कह रहे हैं कि आप इस काम में जोर लगाइये, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अभी-अभी हमने कहा कि जो मॉनिटरिंग कमेटी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए की......(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : कहीं कोई कमेटी नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : यह तो उन सरकारों का काम है कि वे कमेटी स्थापित करें, मेरा काम निर्देश देना है। हमने 23.5.2008 को सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है, मेरे पास चिट्ठी है। राज्य सरकारें अगर नहीं करती हैं तो उन सरकारों को पकड़ना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री उमाशंकर सिंह : जब रुपया केन्द्र का है तो केन्द्र से डायरेक्शन जानी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में है। इस प्रश्न के भाग (ग) में प्रश्नकर्ता ने आपसे दो जानकारियां चाही थीं। एक तो वे योजनाएं जो इस योजना के तहत स्वीकृत हो चुकी हैं और दूसरा वे प्रस्ताव जो आपके पास लम्बित पड़े हैं। आपने उन स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा तो दिया, लेकिन लम्बित प्रस्तावों के बारे में आपका लिखित उत्तर पूरी तरह से मौन है। इन लम्बित प्रस्तावों के बारे में हमारी जानने की जिज्ञासा थी। महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अनेक प्रस्ताव आपके यहां लम्बित हैं और जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र जिला रायसेन का प्रस्ताव भी शामिल है। वह 116 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जिसमें ज्यादातर वे आदिवासी गांव हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में बसे हैं और जिनमें एक भी बिजली का खम्बा नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप अपनी 11वीं योजना का दूसरा चरण कब प्रारम्भ कर रहे हैं और क्या आप उसमें इस रायसेन के प्रस्ताव को, जो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आपकी मेज पर, आपके हस्ताक्षर की इंतजार कर रहा है, शामिल करेंगे।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया जी, कुल 44 प्रोजैक्टस हैं जो 43 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं और वे 11वें प्लान के फेज (2) के फेज (1) में है । जो गांव , जिले लिये गये हैं, जिनकी मेरे पास लिस्ट भी है, जिसमें केरल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ है। ऐसे 44

प्रोजैक्ट्स हैं जिनमें कोस्ट बहुत ज्यादा है और हम इनके लिए बार-बार बैठके कर रहे हैं। 11वें प्लान के लिए जो फेज (1) में है, उसमें 28000 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है और जो रह गये हैं उनके बारे में भी हम काम को आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ने इसके लिए देश को आश्वासन दिया है और ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 2012 तक एक यूनिट बिजली सब को मिल जाएगी, यह हमारा प्रोमिस है। हम जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम हम 2010 तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

DR. RATNA DE : Madam, I want to know from the hon. Minister as to whether there is any Central Monitoring Committee to look after the electrification of different villages in different States. May I also know whether any report is coming each year from the States about how many villages have been electrified?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: There are three different Committees – one is at the State level, which monitors; the second Committee is REC or at corporation level, and the third Committee is the one that we appoint, which have different NGOs; they also do it and report to us. If the hon. Member wants to have any information about any particular village or district, I will provide it.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be Laid. Shri S. Jaipal Reddy.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Buildings Construction Corporation Limited and the Ministry of Urban Development for the year 2009-10.

(Placed in Library See No. LT 16/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon under sub-section (4) of Section 15 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(Placed in Library See No. LT 17/15/09)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944 :-

(i) The Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 396(E) in Gazette of India dated the 10th June, 2009 together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R. 110(E) published in Gazette of India dated the 23rd February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 22/2003-C.E. dated the 31st March, 2003.

(iii) G.S.R. 392(E) published in Gazette of India dated the 5th June, 2009 together with an explanatory memorandum granting exemption under

Section 11C of the Central Excise Act, 1944 to agricultural grade zinc sulphate for the period from 1.1.2007 to 8.10.2007.

(iv) G.S.R. 119(E) published in Gazette of India dated the 24th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the five notifications mentioned therein.

(v) The Pan Masala Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 155(E) in Gazette of India dated the 5th March, 2009 together with an explanatory memorandum.

(vi) G.S.R. 351(E) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 64/95-C.E. dated the 16th March, 1995.

(vii) G.S.R. 287(E) published in Gazette of India dated the 27th April, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 29/2002-C.E. dated the 13th May, 2002.

(Placed in Library See No. LT 18/15/09)

(3) A copy of the Notification No. G.S.R. 397(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th June, 2009, making certain amendments in the Notification No. 32/2006-C.E. (N.T.) dated the 30th December, 2006 issued under Central Excise Rules, 2002 and CENVAT Credit Rules, 2004, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library See No. LT 19/15/09)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-rule (2) of rule 3 of the Central Excise Rules, 2002:-

(i) G.S.R. 221(E) published in Gazette of India dated the 30th March, 2009 together with an explanatory memorandum making

certain amendments in the Notification No. 14/2002-C.E. (N.T.) dated the 8th March, 2002.

(ii) G.S.R. 256(E) published in Gazette of India dated the 17th April, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 14/2002-C.E. (N.T.) dated the 8th March, 2002.

(iii) G.S.R. 312(E) published in Gazette of India dated the 11th May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 14/2002-C.E. (N.T.) dated the 8th March, 2002.

(Placed in Library See No. LT 20/15/09)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R. 109(E) published in Gazette of India dated the 23rd February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 52/2003-Cus. dated the 31st March, 2003.

(ii) G.S.R. 393(E) published in Gazette of India dated the 9th June, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated the 13th August, 2008.

(iii) G.S.R. 103(E) published in Gazette of India dated the 19th February, 2009 together with an explanatory memorandum permitting the import of certain specified goods against the duty credit scrips issued under the Hi-tech Product Export Promotion Scheme.

(iv) G.S.R. 102(E) published in Gazette of India dated the 19th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the five notifications mentioned therein.

(v) G.S.R. 104(E) published in Gazette of India dated the 19th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 94/2004-Cus., dated the 10th September, 2004.

(vi) G.S.R. 105(E) published in Gazette of India dated the 19th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 40/2006-Cus., dated the 1st May, 2006.

(vii) G.S.R. 111(E) published in Gazette of India dated the 24th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the 21 notifications mentioned therein.

(viii) G.S.R. 147(E) published in Gazette of India dated the 3rd March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 208/1977-Cus. (N.T.), dated the 1st October, 1977 and corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 175(E) dated 17th March, 2009.

(ix) G.S.R. 141(E) published in Gazette of India dated the 2nd March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the two notifications mentioned therein.

(x) G.S.R. 275(E) published in Gazette of India dated the 22nd April, 2009, together with an explanatory memorandum specifying the goods, mentioned therein, as the goods in respect of which special measures for the purpose of checking their illegal export and facilitating the detection of the said goods, which are likely to be illegally exported in India's land border with Myanmar falling within the territories of Nagaland, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.

(xi) G.S.R. 121(E) published in Gazette of India dated the 24th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated the 1st March, 2002.

(xii) G.S.R. 145(E) published in Gazette of India dated the 3rd March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated the 23rd July, 1996.

(xiii) G.S.R. 184(E) published in Gazette of India dated the 20th March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated the 13th August, 2008.

(xiv) G.S.R. 197(E) published in Gazette of India dated the 24th March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated the 1st March, 2002.

(xv) G.S.R. 200(E) published in Gazette of India dated the 26th March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated the 1st March, 2002.

(xvi) G.S.R. 258(E) published in Gazette of India dated the 17th April, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus., dated the 1st March, 2002.

(xvii) G.S.R. 307(E) published in Gazette of India dated the 4th May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 96/2008-Cus., dated the 13th August, 2008.

(xviii) G.S.R. 355(E) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated the 23rd July, 1996.

(xix) G.S.R. 371(E) published in Gazette of India dated the 30th May, 2009 together with an explanatory memorandum seeking to give effect to customs duty concessions on items agreed to by India under the India-MERCOSUR Preferential Trade Agreement which was signed on January 25, 2004.

(xx) S.O. 496(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxi) S.O. 549(E) published in Gazette of India dated the 25th February, 2009 together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxii) S.O. 564(E) published in Gazette of India dated the 27th February, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxiii) S.O. 731(E) published in Gazette of India dated the 13th March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxiv) S.O. 823(E) published in Gazette of India dated the 24th March, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2009-Cus.(N.T.), dated the 25th February, 2009.

(xxv) S.O. 867(E) published in Gazette of India dated the 27th March, 2009 together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxvi) S.O. 889(E) published in Gazette of India dated the 31st March, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxvii) S.O. 1059(E) published in Gazette of India dated the 28th April, 2009, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxviii) The India-Singapore Trade Agreement (Safeguard Measures) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 315(E) in Gazette of India dated the 12th May, 2009, together with an explanatory memorandum.

(xxix) S.O. 1223(E) published in Gazette of India dated the 15th May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxx) S.O. 1358(E) published in Gazette of India dated the 27th May, 2009 together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* for the purpose of assessment of imported and export goods.

(xxxi) S.O. 1381(E) published in Gazette of India dated the 29th May, 2009 together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(xxxii) S.O. 1455(E) published in Gazette of India dated the 15th June, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001.

(6) Seven statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) to (ix) of (5) above.

(Placed in Library See No. LT 21/15/09)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R. 132(E) published in Gazette of India dated the 27th February, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty on Plain Medium Density Fibre Board originating in or exported from China PR, Malaysia, New Zealand, Thailand and Sri Lanka at specified rates.

(ii) G.S.R. 186(E) published in Gazette of India dated the 23rd March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional safeguard duty at the rate of 28 per cent, ad-valorem on imports of Dimethoate Technical imported into India.

(iii) G.S.R. 187(E) published in Gazette of India dated the 23rd March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional safeguard duty at the rate of 21 per cent ad-valorem and 35 per cent ad valorem on all Aluminium Flat Rolled Products and Aluminium Foil respectively imported into India from the People's Republic of China.

(iv) G.S.R. 201(E) published in Gazette of India dated the 26th March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of All Fully

Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yearn of Polyester, originating in, or exported from, the People's Republic of China, Thailand and Vietnam and imported into India.

(v) G.S.R. 202(E) published in Gazette of India dated the 26th March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of Flax fabric, originating in, or exported from the People's Republic of China and Hong Kong and imported into India.

(vi) G.S.R. 215(E) published in Gazette of India dated the 27th March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on Cathode Ray Colour Television Picture Tubes, originating in or exported from Indonesia.

(vii) G.S.R. 216(E) published in Gazette of India dated the 27th March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti-dumping duty, based on recommendation of designated authority in the sunset review findings, on imports of Hexamine, originating in, or exported from, Iran and imported into India.

(viii) G.S.R. 217(E) published in Gazette of India dated the 27th March, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti-dumping duty, based on recommendation of designated authority in the sunset review findings, on imports of Vitamin E all forms excluding natural forms, originating in, or exported from the People's Republic of China and imported into India.

(ix) G.S.R. 223(E) published in Gazette of India dated the 31st March, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 45/2006-Cus. dated the 24th May, 2006.

(x) G.S.R. 248(E) published in Gazette of India dated the 13th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty, based on the recommendation of designated authority in the sunset review findings, on imports of Sodium hydrosulphite, originating in, or exported from, Germany and Korea RP and imported into India.

(xi) G.S.R. 264(E) published in Gazette of India dated the 20th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional safeguard duty at the rate of 20 per cent, ad-valorem on imports of Soda Ash from the People's Republic of China into India.

(xii) G.S.R. 276(E) published in Gazette of India dated the 22nd April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on all imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel, originating in, or exported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA at specified rates.

(xiii) G.S.R. 289(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of Nylon Tyre Cord Fabric, originating in, or exported from, Belarus and imported into India.

(xiv) G.S.R. 290(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of Thionyl Chloride, originating in, or exported from, the European Union and imported into India.

(xv) G.S.R. 291(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to

impose anti-dumping duty, based on recommendation of designated authority in the sunset review findings, on imports of Nylon Tyre Cord Fabrics, originating in or exported from the People's Republic of China and imported into India.

(xvi) G.S.R. 292(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 36/2005-Cus., dated 27th April, 2005.

(xvii) G.S.R. 293(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 72/2008-Cus., dated 2nd June, 2008.

(xviii) G.S.R. 296(E) published in Gazette of India dated the 30th April, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti-dumping duty on imports of Cable Ties, originating in, or exported from the People's Republic of China and Taiwan and imported into India.

(xix) G.S.R. 313(E) published in Gazette of India dated the 11th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to rescind Notification No. 55/2004-Cus., dated 19th April, 2004.

(xx) G.S.R. 316(E) published in Gazette of India dated the 12th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty, on all kinds of plastic processing or injection moulding machines, having clamping force not less than 40 tonnes, originating in or exported from China PR.

(xxi) G.S.R. 320(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti dumping duty, based on recommendation of designated authority in the sunset review findings, on imports of Caustic Soda originating in, or exported from, Indonesia and European Union (excluding France) and imported into India.

(xxii) G.S.R. 336(E) published in Gazette of India dated the 15th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to continue anti-dumping duty on Measuring Tapes, originating in or exported from China PR.

(xxiii) G.S.R. 337(E) published in Gazette of India dated the 15th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on cathode ray colour television picture tubes, originating in, or exported from Malaysia, Thailand, China PR and Korea RP.

(xxiv) G.S.R. 352(E) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 4/2009-Cus., dated 6th January, 2009.

(xxv) G.S.R. 353(E) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009, together with an explanatory memorandum providing that no anti-dumping duty shall be imposed on imports into India of certain tiles from the specified producers and exporters from the People's Republic of China and Hong Kong.

(xxvi) G.S.R. 354(E) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 38/2007-Cus., dated 9th March, 2007.

(xxvii) G.S.R. 360(E) published in Gazette of India dated the 26th May, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on import of Compact Fluorescent Lamps, originating in or exported from, China PR, Sri Lanka and Vietnam.

(xxviii) G.S.R. 370(E) published in Gazette of India dated the 30th May, 2009, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 38/2009-Cus., dated 22nd April, 2009.

(xxix) G.S.R. 391(E) published in Gazette of India dated the 5th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on import of Compact Discs-Recordable originating in, or exported from Iran, Malaysia, Korea ROK, Thailand, United Arab Emirates and Vietnam.

(xxx) G.S.R. 398(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 33/2008-Cus., dated 11th March, 2008.

(xxxi) G.S.R. 399(E) published in Gazette of India dated the 10th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti-dumping duty on imports of Potassium Carbonate, originating in, or exported from, the European Union, the People's Republic of China, Korea RP and Taiwan and imported into India, based on recommendations of the designated authority in the sunset review findings.

(xxxii) G.S.R. 418(E) published in Gazette of India dated the 15th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports into India of the varieties of ceramic glazed tiles, other than vitrified tiles, originating in or exported from the People's Republic of China, pending the final determination.

(xxxiii) G.S.R. 419(E) published in Gazette of India dated the 15th June, 2009, together with an explanatory memorandum providing that no anti-dumping duty shall be imposed on imports of vitrified and porcelain tiles into India from the specified producers and exporters from the People's Republic of China and Singapore.

(xxxiv) G.S.R. 420(E) published in Gazette of India dated the 15th June, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 134/2008-Cus. dated the 22nd December, 2008.

(xxxv) G.S.R. 421(E) published in Gazette of India dated the 15th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles, originating in, or exported from China PR, at specific rates.

(xxxvi) G.S.R. 424(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty levied on imports of 6-Hexanelactam, originating in, or exported from, Japan, European Union, Nigeria and Thailand, upto and inclusive of 20th April, 2010, pending finalization of Sunset review investigations being conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(xxxvii) G.S.R. 425(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose anti-dumping duty on imports of Vitamin C, originating in, or exported from the People’s Republic of China and imported into India, based on recommendations of the designated authority in the sunset review findings.

(xxxviii) G.S.R. 426(E) published in Gazette of India dated the 16th June, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 159/2003-Cus., dated the 24th October, 2003.

(xxxix) The Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Preferential Trade Agreement between the Governments of MERCOSUR Member States comprising the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Republica Oriental del Uruguay and the Republic of India) Rules,

2009 published in Notification No. S.O. 1385(E) in Gazette of India dated the 30th May, 2009, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library See No. LT 22/15/09)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961 :-

(i) The Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 655(E) in Gazette of India dated the 12th March, 2009, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 740(E) in Gazette of India dated the 16th March, 2009, together with an explanatory memorandum.

(iii) The Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 857(E) in Gazette of India dated the 25th March, 2009, together with an explanatory memorandum.

(iv) The Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 858(E) in Gazette of India dated the 25th March, 2009, together with an explanatory memorandum.

(v) The Income-tax (Tenth Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 961(E) in Gazette of India dated the 13th April, 2009, together with an explanatory memorandum.

(vi) The Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 989(E) in Gazette of India dated the 21st April, 2009, together with an explanatory memorandum.

(vii) The Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. S.O 866(E) in Gazette of India dated the 27th March, 2009, together with an explanatory memorandum and corrigendum thereto published in Notification No. S.O. 960(E) dated the 13th April, 2009.

(Placed in Library See No. LT 23/15/09)

(9) A copy of the Notification No. S.O. 1327(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 22nd May, 2009 together with an explanatory memorandum notifying MCX Stock Exchange Limited as a recognized stock exchange for the purpose of the clause (ii) in the Explanation to clause (d) of the proviso to sub-section (5) of section 43 of the Income-tax Act, 1961, issued under Section 43 of the said act.

(Placed in Library See No. LT 24/15/09)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 74 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 :-

(i) The Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authority) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 374(E) in Gazette of India dated the 1st June, 2009, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 375(E) in Gazette of India dated the 1st June, 2009, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library See No. LT 25/15/09)

(11) A copy of the Notification No. G.S.R. 308(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 5th May, 2009 containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 62(E) date the 31st January,

2008, together with an explanatory memorandum issued under Prevention of Money Laundering Act, 2002.

(Placed in Library See No. LT 26/15/09)

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994 :-

(i) G.S.R. 120(E) published in Gazette of India dated the 24th February, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to reduce rate of service tax on taxable services from 12% to 10%.

(ii) G.S.R. 146(E) published in Gazette of India dated the 3rd March, 2009, together with an explanatory memorandum providing exemption from payment of service tax for services provided for the authorized operations of a Special Economic Zones.

(iii) G.S.R. 347(E) published in Gazette of India dated the 20th May, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 9/2009-Service-Tax., dated 3rd March, 2009.

(Placed in Library See No. LT 27/15/09)

(13) A copy of the Coinage of the One Hundred Rupees and Five Rupees coined to commemorate the occasion of "Birth Centenary of Perarignar Anna"

Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 279(E) in Gazette of India dated the 23rd April, 2009 under sub-section (3) of Section 21 of the Coinage Act, 1906.

(Placed in Library See No. LT 28/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Power Finance Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2009-10.

(Placed in Library See No. LT 29/15/09)

(ii) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2009-10.

(Placed in Library See No. LT 30/15/09)

(iii) Memorandum of Understanding between the Power Grid Corporation of India Limited and the Ministry of Power for the year 2009-10.

(Placed in Library See No. LT 31/15/09)

(2) A copy of the Energy Conservation (Manner of holding inquiry) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 25 in Gazette of India dated the 21st March, 2009 under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

(Placed in Library See No. LT 32/15/09)

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 6th of July, 2009, will consist of:-

1. Presentation of Budget (General) for 2009-10 at 11.00 a.m. on Monday, the 6th of July, 2009.
2. Introduction of the Finance (No.2) Bill, 2009.
3. General Discussion on Budget (Railways) for 2009-10
4. General Discussion on Budget (General) for 2009-10.
5. Discussion and Voting on Demands for Excess Grants (General) for 2006-07.
6. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bill relating to the Demands for Excess Grants (General) for 2006-07.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं -

1. महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ में मानसून की देरी से किसानों की बुआई के अभाव में बदहाल स्थिति, क्षेत्र में सिंचाई का अभाव, जलाशयों के सूखने से अकाल की स्थिति को देखते हुए किसानों को इस स्थिति से उबारने तथा इसकी भरपाई के लिए मुफ्त बीज, उर्वरक, बिजली तथा मस्य उत्पादन के लिए मस्य बीजों को तत्काल उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार धनराशि आवंटन के साथ तत्काल कार्रवाई करे।

2. महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित 600 वर्ष पुराने गोंडकालीन प्राचीन किला (परकोट) मरम्मत और देखभाल के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस प्राचीन ऐतिहासिक विरासत को बचाने तथा संरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार पहल करे और इसकी मरम्मत तथा देखभाल हेतु तत्काल कार्रवाई करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं -

1. देश में देरी से आते हुए मानसून एवं खंड वर्षा के संबंध में चर्चा।
2. देश में बजट के पूर्व चीजों के बढ़ते हुए दामों के कारणों पर चर्चा।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित लोकमहत्व के मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में समावेश करने का अनुरोध करता हूं -

1. मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर सहित सभी जिलों के ऐतिहासिक किलों का संरक्षण कर उन्हें पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
2. बुंदेलखंड में बारिश न हो पाने से किसानों के समक्ष जो गंभीर संकट पुनः पैदा हो गया है, एक अध्ययन दल भेजकर क्षेत्र की स्थिति का जायजा एवं किसानों की मदद के लिए कदम उठाए जाएं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर):अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित चार बड़ी रेल लाइनों के निर्माण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बजट में पर्याप्त धनराशि आबंटित करने पर विचार हेतु शामिल करने का अनुरोध करता हूं -

1. भानुपल्ली-बिलासुपर-बैरी रेलवे लाइन
2. घनौली-बद्दी रेलवे लाइन
3. नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन
4. बिलासपुर-मंडी-मनाली-लेह/लद्दाख रेलवे लाइन

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी हूं। मैं आपका ध्यान बुंदेलखंड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जहां लगातार पांच वर्षों से सूखा पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. बुन्देलखंड क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए तथा विशेष पैकेज दिया जाए।

2. जालौन जिले में पचनदा पर बांध का निर्माण तुरंत कराया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, ग्रीष्म कालीन सेवा के नाम पर नई ट्रेनें चलाई जाएं। सियालदह एक्सप्रैस, तूफान एक्सप्रैस, कटिहार एक्सप्रैस तथा मथुरा एक्सप्रैस का ठहराव भरवारी स्टशन जनपद (कौशाम्बी) में अपडाउन ट्रेनों का ठहराव किया जाए।

भरवारी व सिराथू रेलवे स्टेशन जनपद कौशाम्बी को जनपद का जंक्शन स्टेशन बनाया जाए। महानन्दा एक्सप्रैस-मूरी एक्सप्रैस, प्रयागराज एक्सप्रैस, रीवा एक्सप्रैव, दिल्ली हावड़ा एक्सप्रैस ट्रेन्स को अपडाउन में ठहराव उपरोक्त स्टेशनों पर किया जाए।

12.06 hrs.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Committee on Estimates

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the following:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, thirty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, thirty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Estimates for the term ending on the 30th April, 2010."

The motion was adopted.

12.07 hrs.

(ii) Committee on Public Accounts

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the following:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 2010."

The motion was adopted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move the following:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

12.08 hrs.

(iii) Committee on Public Undertakings

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move the following:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 312 B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on the 30th April, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of the Rule 312 B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on the 30th April, 2010."

The motion was adopted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move the following:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on the 30th April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on the 30th April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

12.09 hrs.

Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 2010."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 2010."

The motion was adopted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I beg to move:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on the 30^{th} April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on the 30^{th} April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

____

<u>12.11 hrs.</u>

(v) Rajghat Samadhi Committee

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rajghat Samadhi Committee for the term commencing from the date of notification by the Government, subject to the other provisions of the said Act."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rajghat Samadhi Committee for the term commencing from the date of notification by the Government, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

<u>12.12 hrs.</u>

(vi)Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Act, 1996 read with sub-rule (2) of rule 11 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such a manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee, subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Act, 1996 read with sub-rule (2) of rule 11 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Services) Central Rules, 1998, the members of this House do proceed to elect, in such a manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee, subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder "

The motion was adopted.

12.13 hrs.

(vii) Central Coordination Committee constituted under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of Section 3 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Central Coordination Committee for the period till they cease to be the members of the House, subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of Section 3 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Central Coordination Committee for the period till they cease to be the members of the House, subject to other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.14 hrs.

(viii) Committee on Official Language

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए मैं अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of this House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with section 4(3) of the said Act."

The motion was adopted.

12.15 hrs.

RAILWAY BUDGET, 2009-2010

MADAM SPEAKER: Now, the Railway Budget.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I am on a point of order. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, please sit down. Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I have written a letter to you saying..… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Madam, this is not correct. This is absolutely wrong.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Railway Minister is saying.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded

:

MADAM SPEAKER: Now, Kumari Mamata Banerjee may present the Railway Budget.

THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE):

Madam Speaker, I rise to present the Budget Estimates for the year 200910 for the Indian Railways. I am extremely honoured presenting the first railway budget in the august House presided by the first lady Lok Sabha Speaker of the country.

This is the first Railway budget that I will be presenting as a Minister in the UPA government. I thank our respected Prime Minister, Dr. Manmohan Singh Ji for his valued guidance and support and I am also thankful to our honourable Finance Minister for his kind support. I have presented two Railway Budgets earlier and this will be my third Railway Budget.

Madam, I know how our Hon'ble Members of Parliament representing people from all parts of the country have high expectations from Indian Railways. They want new projects in their states and constituencies. They also want more new lines, more budget provisions and existing projects to be expedited. They want more trains and better services.

Railway is the visible face of the government and we are proud of it. Madam, therefore standing before the august House, please permit me to raise a question as to whether railway projects are to be measured only on the scale of "economic viability" or do we also need to look at the "social viability" of these projects ? Are the fruits of development to be restricted only to a privileged few and not to the teeming populations in remote and backward areas of our country? These projects may be economically unviable but are an economic necessity for the people of those regions who have remained victims of backwardness and poverty. They need these projects even more. I do believe 1 and I am firmly

committed to the visible upliftment of the downtrodden and under privileged which is imperative for holistic socio economic development of the country. These projects that are instrumental in upgradation of the deprived and under privileged, may not meet the so called economic viability criterion but create real economic assets which will be far more beneficial for future development.

हमें आजादी मिले बहुत साल हो गए हैं । जिस प्रकार लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है, उसी तरह विकास का अधिकार भी हम आम इंसान को प्राप्त होना चाहिए । लाखों लोग प्रगति के इंतजार में बैठे हैं । अब वक्त आ गया है कि उनको विकास में अपना हिस्सा मिलना चाहिए ।

I think the time has come when our economists and social philosophers will have to consider, that the upliftment of the poor and down trodden, is the primary task of any welfare government and society and the old mindset of economic viability should be substituted by social viability. As the former Prime Minister Indiraji once stated that "elimination of poverty demands frontal attack on vested interests and causes of poverty".

I believe that by building up major infrastructural facilities like Indian Railways, we will be able to aim at development of the large number of face less poor people. These are at the core of my developmental approach for railways.

Speaker Madam, our hon'ble Prime Minister always emphasises on 'inclusive growth'. The Railways must set an example to promote 'inclusiveness' in their functioning keeping the needs of all sections of our fellow countrymen in our thoughts, decisions and deeds. I have therefore decided to set up an expert committee to advise me on innovative financing and implementation of the so called "economically unviable" but socially desired projects. We will identify those parts that are detached from all infrastructure development and facilities and within a short time I will prepare a blue print of how many such schemes can be implemented in the coming five years.

Madam, we need to strike a right balance. Everyone knows that India is changing and changing rapidly. Indian Railways has been trying to keep pace with this change. Indeed Railways is making its own important contribution to this change. Today the people of India are eager for faster and inclusive economic growth. They want better connectivity, more employment opportunities. People of every region in every state want to see progress in agriculture, industry, trade and business, so that they and their children can live a better life. Indian Railways is a unique umbrella for creation of infrastructure for development and it is our Mission and Vision to expand the network to reach development to every corner of the country.

Madam, here I would like to quote the following words of Gurudev Rabindra Nath Tagore;

" निज हस्ते निर्दय आघात करि पितः
भारतेरे सेइ स्वर्गे करो जागरित"

"Where the mind is led forward by Thee, into ever-widening thought and action Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake."

Service to the Passengers

Madam Speaker, after taking over as Railway Minister just a few days back, I faced many complaints about deterioration in overall passenger services. Therefore my priority areas will be a perceptible improvement in

- Passenger Amenities
- Cleanliness
- Quality of Railway catering
- Safety and Security and
- Punctuality

All Railway zones have been instructed to give priority to provision of good quality food, drinking water and toilet facilities and ensure cleanliness on trains and stations. I have further instructed that availability of Janata Khana should be ensured and we will be introducing national and regional cuisines in our catering. A comprehensive policy including strict monitoring mechanisms would be developed soon for achieving these objectives.

World Class Stations

We have decided to develop about 50 stations as world class stations with international level facilities. These will be developed, through innovative financing and in Public Private Partnership mode. लालू जी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमें इज्जत दीजिए । मैंने आपके बारे में कभी कोट नहीं किया है । (व्यवधान) यह कंटीन्यूइंग प्रोसैस है । आपने कुछ किया, हम उसकी रिस्पैक्ट करते हैं , हम कुछ करेंगे, इस पर हम आपकी मदद चाहते हैं । Some of these stations are ST Mumbai, Pune, Nagpur, Howrah, Sealdah, Bhubaneswar, New Delhi, Lucknow, Varanasi, Amritsar, Kanpur, Guwahati, Jaipur, Chennai Central, Tiruvananthapuram Central, Secunderabad, Tirupati, Bangalore City, Baiyapanahali (Bangalore), Ahmedabad, Bhopal, Habibganj, Gaya Jn., Agra Cantt., Mathura Jn., Chandigarh, Kolkata, New Jalpaiguri, Majerhat, Mangalore, Porbandar, Anand Vihar, Bijwasan, Ajmer Jn. and Puri.

Adarsh Stations

Madam, we will develop Adarsh stations "Adarsh Stations" means other stations with basic facilities such as drinking water, adequate toilets, catering services, waiting rooms and dormitories especially for lady passengers, better signage and other basic facilities are universally available. This year we are taking up 375 stations for inclusion as Adarsh stations. The list of 309 identified stations is as follows:

Abohar, Adi Saptagram, Adra, Agarpara, Ahmadpur Jn, Akra, Alipurduar Jn, Ambika Kalna, Amethi, Amta, Andheri, Andul Jn, Aranghata, Asansol, Ashoknagar Road, Avadi, Azimganj City, Badkulla, Bagbazar, Baghajatin, Bagnan, Baidyabati, Balichak, Ballygunge, Balurghat, Bandel, Bandra, Bankura, Banpur, Bansh Beria, Banspani, Barakar, Baranagar Road, Bargachia, Barrackpore, Baruipara, Baruipur, Basirhat, Bauria Jn, BBD Bag, Begampur, *Belanagar, Belapur, Belerhat, Belgharia, Belur, Belur Math, Berhampur Court, Bhadreswar, Bhandup, Bhasila, Bhayandar, Bidar, Bidhannagar Road, Bihar Sharif, Biman Bandar, Bira, Birati, Birnagar, Bolangir, Bolpur, Bongaon Jn, Borivali, Brace Bridge, Budge Budge, Burdhman, Burrabazar, Canning, Chakda, Chakradharpur, Champahati, Champapukur, Chandannagar, Chandausi Jn, Chandpara, Charni Road, Chembur, Chengel, Chennai Beach Jn, Chennai Chetpat, Chennai Park, Chhindwara Jn, Chinchwad, Chittaranjan, Chittaurgarh Jn, Chittoor, Chromepet, Chuchura, Churchgate, Cooch Behar, Currey Road, Dadar, Dahanu Road, Dakshineswar, Dalkolha, Dankuni Jn, Dausa, Delhi Kishanganj, Deula, Devlali, Dhakuria, Dhaniakhali, Dhapdhapi, Dhupguri, Diamond Harbour, Dockyard Road, Dombivali, Domjur, Dum Dum Cantt, Dum Dum Jn, Durganagar, Durgapur, Duttapukur, Eden Gardens, Farakka, Faridkot, Gangnapur, Garbeta, Garia, Gede, Ghatkopar, Ghutiari Sharif, Gobardanga, Gomoh Jn, Gopalnagar, Goregaon, Guma, Guptipara, Gurdas Pur, Gurgaon, Guskara, Habibpur, Habra, Halisahar, Haripal, Harua Road, Hasnabad, Haur, Hooghly, Ichhapur, Jadabpur, Jagaddal, Jajpur Keonjhar Road, Jalpaiguri, Jamshedpur, Jangipur Road, Jaynagar Majilpur, Jhargram, Jiaganj, Jirat, Kakdwip, Kalikapur, Kalinarayanpur Jn, Kalyani, Kalyani Ghoshpara, Kalyani Silpanchal, Kalyanpur, Kamarkundu Jn, Kanchrapara, Kankinara, Karjat, Kasara, Kashinagar, Katwa Jn, Khadki, Khana, Khardaha, Khopoli, Khurda Road, King's Circle, Kirnahar, Kolaghat, Konnagar,

---

… This part of the speech was laid on the Table

Koraput Jn, Korukkupet, Krishnanagar City Jn, Kulti, Kurla, Lake Gardens, Lakshmikantapur, Lalgarh Jn, Lalgola, Latur, Liluah, Londa Jn, Madanpur, Madhubani, Madhupur Jn, Madhyamgram, Magra Hat, Majhergram, Malad, Malda Town, Mallikpur, Manavur, Mankundu, Marine Lines, Masagram, Masalandapur, Matunga, Mecheda, Memari, Midnapur, Mira Road, Mourigram, Mulund, Mumbai Central (Local), Murshidabad, Nabadwipdham, Nahur, Naigaon, Naihati Jn, Nalgonda, Nalhati Jn, Nalikul, Namkhana, Nanur, Narayan Pakuria Murail, Nasibpur, Netra, New Alipore, New Barrackpore, Nischindapur, Okha, Palpara, Palta, Panskura Jn, Panvel, Parasnath, Parkcircus, Parli Vaijnath, Patipukur, Patna Sahib, Perambur Carriage Works, Phulia, Pilibhit Jn, Plassey, Prayag, Princepghat, Pundooah, Purbasthali, Purulia Jn, Raiganj, Rampurhat, Ranaghat Jn, Rangapara North, Raniganj, Rasulpur, Rayagada, Rishikesh, Rishra, Sagar, Sahibganj, Sainthia Jn, Salempur Jn, Samudragarh, Sangli, Sangrampur, Sanpada, Santacruz, Santoshpur, Saphale, Senji Panambakkam, Sewri, Shaktigarh, Shantipur Jn, Sheoraphuli, Shikohabad Jn, Shivajinagar, Shrirampur, Shyamnagar, Silchar, Siliguri Jn, Simurali, Singur, Sirsa, Sitamarhi, Sitapur Jn, Sitarampur Jn, Sodepur, Sonarpur Jn, Sondalia, St. Thomas Mount, Subhasgram, Subzi Mandi, Sultanganj, Suri, Suryapur, Taki Road, Tala, Tambaram, Tarakeswar, Tarapith Road, Thakurnagar, Tilak Nagar, Tiruninravur, Tiruvalangadu, Tiruvallur, Titagarh, Titlagarh Jn, Tollygunge, Tribeni, Turbhe, Ulhasnagar, Ulubaria, Uttarpara, Vangaon, Vashi and Virar.*

Multi-functional Complexes (MFCs)

I am very happy to announce the construction of Multi-functional Complexes in station premises for providing rail users facilities like shopping, food stalls and restaurants, book stalls, PCO/STD/ISD/Fax booths, medicine & variety stores, budget hotels, underground parking etc. It is proposed to take up development of these Multi-functional Complexes in different parts of the country at 50 railway stations serving places of pilgrimage, industry and tourist interest in

this year. Responsibility for development of these facilities will be entrusted to IRCON and Rail Land Development Authority (RLDA).

A list of 49 identified stations is:
Alipurduar, Allahabad, Anandpur Sahib, Banspani, Bikaner, Bilaspur, Cuttack, Darjeeling, Dehradun, Digha, Durg, Ernakulam, Gandhidham, Ganga Sagar, Ghatsila, Gwalior, Hajur Sahib, Hubli, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jammu Tawi, Jasidih, Jhansi, Jodhpur, Kanniyakumari, Kathgodam, Katra, Khajuraho, Madurai, Manmad, Mysore, Nanded, Nasik, Palakkad, Parasnath, Raebareily, Raipur, Rajgir, Rameshwaram, Ranchi, Shirdi, Silchar, Tarapith, Tiruchirapalli, Udaipur, Ujjain, Vadodara, and Visakhapatnam.

Clean trains and Stations

During current year we will expand On Board House Keeping Scheme (OBHS) to cover 200 additional pairs of trains and also take up **improved linen** management to bring about a significantly improved quality of washing, through modern mechanised automated laundries. Initially, a pilot project will be started at the metropolitan cities, like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram. On its success it will be extended to other cities.

Railways will extend a helping hand to Physically Challenged Persons and aged persons by providing standard ramps, earmarked parking lots, specially designed coaches in each mail and express train, lifts and escalators, in a phased manner.

We will introduce Train Information System with automatic announcements in Kolkata, Chennai and Delhi suburban sections as is already in the process of being installed in Mumbai. Other important stations will be covered in a phased manner.

Doctor on Train

We are exploring possibility to depute at least one doctor in long distance trains. Arrangements will be made to provide Ambulance services for passengers at Chennai, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Mumbai, Kolkata and Bhubaneswar to start with.

Madam, for long distance passengers I am happy to inform that Railways will provide **on-board infotainment services** on Rajdhanis, Shatabdis and important long distance inter- city trains for a pleasurable travel experience.

Field trials are being conducted for introducing **environment friendly green toilets**. We are also planning to conduct trials on vacuum toilets similar to those used in aircraft on a few coaches.

Toilet facilities are not being provided in DEMU and MEMU trains when the travel time is less than 4 hours. This poses difficulties for women, children and aged persons. We are now planning to provide toilet facilities where journey is more than 2 hours. Give us a little time; we will do it as early as possible.

Ticketing and Reservation

Indian Railways Passenger Reservation System (PRS) now covers 800 locations with 6872 terminals. We will cover 200 new towns and cities and a further 800 new locations in cities and towns already having PRS facilities will be covered. **Madam, I invite each member of both houses of Parliament to identify one PRS location of their choice** and inform railways for inclusion in the list of new locations.

For unreserved tickets, the number of **Unreserved Ticketing System (UTS)** terminals is being expanded from 5000 to 8000. **Automatic Vending Machines** would be installed at 200 large and medium sized stations. We are expanding e ticketing for ease of passengers. Cancellation of confirmed e-tickets after preparation of charts is being further simplified. Efforts are on to provide

SMS update on waitlisted tickets and indicate berth numbers on confirmed ticket by the end of the financial year.

"Mushkil Aasaan"

Madam, I think members will be very happy to know that how the facility of UTS can be reached to the **"Maa Maati Manush"**. Under the MoU between Railways and Department of Post, passengers can now buy computerized tickets from nearly 5000 post offices in cities and towns. Madam, this august house would be happy to know that I have decided to introduce mobile ticketing vans **"Mushkil Aasaan"** for issuing reserved and unreserved tickets in both urban and rural areas. Poor people who are unable to go to the stations can now purchase tickets in market places, mohallas and other busy places. In this year, we will introduce 50 such mobile vans in the country.

Air conditioned double decker coaches for inter-city travel

Madam the house will be happy to know that like double decker buses we are taking the novel initiative of introducing high capacity air conditioned double-decker coaches, for intercity travel. These will have superior riding quality and comfort.

Monitoring of Passenger Facilities

For monitoring these various initiatives, the Additional General Managers on each zonal Railway will be responsible for periodic supervision and carrying out surprise inspections and attending to public grievances on this subject. Each Division will have a dedicated officer for field level supervision.

Safety

Safety is our first priority. This includes **timely track renewal, modernization of signals, use of various safety equipment like** digital ultrasonic flaw detecting machines and wheel impact load detectors (WILD). In the first two

years of the plan period, 7843 kms of track renewals has been completed and a target of 3500 km has been kept for 2009-10. Out of 66,565 km of broad gauge track, 57,345 km has been brought under mechanized maintenance.

Road Over Bridges and Road Under Bridges are extremely important from safety point of view. The present mechanism of cost sharing between the Railways and the state governments needs to be reviewed. The time has come to develop a new approach where, with assured funding, turnkey execution of these projects can be done. **We will take up this issue with the Planning Commission for their support.**

Anti Collision Device (ACD) to prevent incidents of train collisions has been made operational on 1736 RKm of North Frontier Railway. Further work for extending this system on 1700 RKm on three railways Southern, South Central and South Western Railways is planned to be completed in two years. I will review the implementation of the project before further extension to other Railways.

All safety related matters will be taken care of by Railway Board who will take responsibility and effective measures to ensure safety.

Security

Security is another priority area of railways. Railways are strengthening their efforts at providing protection to passengers both at stations and on trains. For revamping security systems, an **Integrated Security Scheme** has been drawn up for 140 vulnerable and sensitive railway stations. We are also planning to raise Commando Battalions and will **increase the number of women commandos. Women RPF squads are being deployed for security of women passengers,** particularly in sections where a large number of women travel alone regularly.

Madam, even **though Law and order is a state subject, we will work together with all agencies concerned to give passengers a safe** journey.

Staff Welfare

We are proud of our 14 lakh employees. They are the leader and our engine of growth

- A thrust will be given under the Corporate Welfare Plan for improvement of staff quarters & colonies. During 2009-10, **6560 staff quarters** are proposed to be **constructed**.

- To promote **sports, cultural** and extra-curricular activities, **indoor stadia** will be developed in major railway divisions and zones including **Bongaon at the Indo- Bangladesh border.**

- I propose to **increase the contribution to Staff Benefit Fund** to Rs 350/- per employee by one year with the proviso that out of this contribution, the sum of Rs 100 per employee will be exclusively for activities relating to women empowerment and training for developing vocational and occupational skills of physically and mentally challenged wards of railway employees **especially girl child and higher education for girls.**

- I propose to set up **Scholarships for higher education of girl children** of group D staff for promoting their economic independence.

- It is proposed to **open seven Nursing Colleges on Railway** land at Delhi,Kolkata, Mumbai (Kalyan), Chennai, Secunderabad, Lucknow and Jabalpur on Public Private Partnership model so as to **facilitate the wards of the Railway employees in finding a good vocational avenue.**

- **Medical colleges are planned to be established attached** to existing railway hospitals through PPP, to give higher education facilities to new generation of railway children. The locations would be Chennai, Hyderabad, Bilaspur, Lucknow, Barasat, Bhubaneswar, Mysore, Kharagpur, Guwahati, Dibrugarh, Jodhpur, Gardenreach, Nagpur, Ahmedabad, B. R. Singh Hospital, Bhopal, Jammu and Trivandrum.

- We will provide **dormitories for ladies and gents who accompany the patients** at 16 hospitals having 150 beds and above

- For special **medical treatment** of railway persons, **General Managers** will be **empowered to sanction cases up to Rs 4 lakhs.**

- The Metro Railway Hospital at Tollygunge is proposed to be **upgraded** to **75 bedded hospital.**

- **Burn Units** will be provided **on major Railway Hospitals** of Delhi, Mumbai, Chennai, Secunderabad, Bangalore and /B.R. Singh Hospital,

- I have received some observations from different people about the functioning of Railway Recruitment Boards. Therefore recruitment policy and **RRBs will be reviewed shortly.**

- Special Recruitment Drive will be launched to wipe out backlog in filling up the vacancies of Scheduled Caste/Scheduled Tribes.

- It is proposed to develop a scheme to give **better representation** to minorities, women and economically back ward classes of the society **in railway recruitments.**

- A **Special Recruitment Drive** will be launched for filling up of vacancies against **Physically Handicapped Quota.**

- We want to promote **sports and cultural activities** among the Railway persons. I appreciate all railway sports persons who participated in national and international events. Sports persons will get their share in recruitment.

Optic Fibre Cable

Madam, I had announced in 2001-02 Railway Budget laying of **Optic Fibre Cable network** along Railway track for commercial utilization. After 8 years, I find little progress. Hence Madam, I propose to **constitute an expert committee,** headed by Shri Sam Pitroda, the key person behind the telecommunication revolution in our country. Madam Speaker, Shri Rajiv Gandhi was the key person for telecom revolution in our country. At that time, Dr. Sam Pitroda was also a key person behind that revolution. I remember that the Committee will suggest further innovations, to utilize the optic fiber cables network of the railway and take **information technology to the door steps in remote areas.**

Wagons

During the year 2009-10 Railways have planned to acquire 18,000 wagons under rolling stock programme as against 11,000 wagons in 2008-09. There is an increase of 7000. There is a growing demand of wagons in Railways. We propose to initiate the process for **taking over wagon units of Burn Standard and Braithwaite**. A dialogue has already been started with concerned Ministries for waiver of accumulated liabilities. Efforts will be made to complete all action at the earliest as the units are PSUs under the Ministry of Heavy Industries.

Madam, shall I read all or can I cut short into small matters?

MADAM SPEAKER: It is all right. You can cut it short.

KUMARI MAMATA BANERJEE: Madam, with your kind permission, I would like to mention here that my speech is a detailed one to capture people's expectations. Since Railways is a vast system and touches all people, I cut short my speech in some places……..*(Interruptions)*. But the entire printed speech may kindly be treated as read.

Production Units

The Production Units of Indian Railways have performed well in 2008-09, with many units setting new records of production and productivity.

- *** Rail Coach Factory/Kapurthala** manufactured 1558 coaches including 121 stainless steel coaches of new LHB design. The target for 2009-10 is 1562 coaches.

- **Integral Coach Factory/Chennai** turned out 1337 coaches. The target for 2009-10 is 1433 coaches.

- **Diesel Locomotive Works/Varanasi** manufactured 257 locomotives in 2008-09. The target for 2009-10 is 250 locomotives with a substantial increase in the number of high horse power locomotives to 150.

- **Chittaranjan Locomotive Works** manufactured 220 locomotives, the highest ever, including 54 3-phase high horse power locomotives. The target for 2009-10 is 250 locomotives.

- **Rail Wheel Factory/Bangalore** achieved a quantum jump in wheel production of 35% over 2007-08 by producing 1,96,261 wheels in the year 2008-09. The production target for 2009-10 is 2,00,000 wheels.

… This part of the speech was laid on the Table

- **Diesel Modernization Works (DMW)** is upgrading the existing fleet of Diesel Locomotives from existing 2600 HP to 3100 HP and 3300 HP Diesel locomotives. *

Railway Workshops to be reorganised on business lines

A business plan will be drawn up **to improve overall efficiency and reduction in unit costs of our workshops.** This will be initiated at Golden Rock, Parel, Ajmer and Kharagpur workshops.

Railway Printing Presses

Madam, the Printing Presses of the Railways have long been neglected and have been deemed to be a non-productive asset. It is my belief that if we take up a few major presses like Mumbai (Byculla), Delhi (Shakurbasti), Kolkata (Howrah) and Chennai, for upgradation and modernization, it would not only be cost effective but may also release surplus space for ancillary development and commercial purposes. I have asked for review of the policy in this regard. I am also aware of heritage institutions like **Basumati Sahitya Mandir,** which unfortunately, is lying unutilized for the last two years. If the State Government agrees, they can hand over this unit to us and we will be happy to take over this. This great institution played a vital role in our freedom movement and is associated with eminent and historic personalities like the father of the nation Mahatma Gandhi, Rabindra Nath Tagore, Rishi Aurobindo, Netaji Subhash Chander Bose, Sri Sri Ramakrishna and Vivekananda. I would be happy to takeover this institution if the State Government hands it over to the Railways.

Public Sector Undertakings- our PSUs are doing well.

During the year 2007-08 all the ten Public Sector Undertakings under the administrative control of Ministry of Railways have performed well and achieved

a **combined turnover of Rs. 11,880 crore** and earned a **net profit of Rs.1,950 crore.** A total dividend payment of Rs. 261 crores has been made to Railways.

Freight Business

Several measures are being taken to improve the proportion of freight traffic moving on Railways.

- Besides improving the loading of coal, iron ore, cement, fertilizers and food grains, Railways are seeking to **increase their share in new traffic streams** like automobiles, fly ash etc.

- Permission to access **private sidings** will be given to containers which will help in attracting piecemeal traffic presently not being carried by Railways.

- A premium service for container movement with assured transit time is being considered for time sensitive cargo.

- Private ownership of special purpose rolling stock for commodities and private operation of freight terminals will be encouraged.

- A new policy would be unveiled to allow construction and operation of private **freight terminals and multi-modal logistic parks.**

- Railways are also in the process of bringing together state governments and major logistics players to set up **logistics parks** co-habited by multiple players through participative funding.

- **Mega logistics hubs** are being planned alongside the proposed **Eastern and Western Dedicated Freight Corridors.**

Kisan-Vision project

Madam, you may be aware that our country at present suffers an **unacceptable loss of about Rs. 35-40,000 crore** every year towards **wastage of fruits and vegetables**. Our farmers will be very happy. I am happy to **inform the House** about the contribution Railways proposes to make to **the second green revolution** by introducing special trains to carry perishable products like fruits and vegetables, fish etc from identified production clusters to consumer centres, by way of maintaining quality and freshness of perishable produce. **Railways will encourage creation of facilities of setting up cold storage and temperature controlled perishable cargo centres** and its transportation through public private partnership mode. For this purpose, Railways will associate professional agency to identify locations and designing proper services.

On similar lines, to promote small industries sector, we will facilitate movement of **village handicraft, cottage industry and textile products from production clusters** like Tirupur, Dhanekhali, Shantipur etc **to consumption centres.** This will greatly increase their outreach and access to new markets. They can create a good market.

Super Fast Parcel Express Trains

I am happy to announce the launch of a premium parcel service named "Faster Parcel Services" on a pilot basis on 3 routes between:

Tughalakabad (Delhi) and Royapuram (Chennai)

Tughalakabad (Delhi) and Vapi (near Mumbai)

Tughalakabad (Delhi) and Howrah

This is envisaged as a time-tabled service from dedicated terminals with guaranteed transit time and web-based bookings.

Dedicated Freight Corridors

The Dedicated Freight Corridor project on the Western and Eastern routes is a **landmark project** which will **adorn the country like a necklace.** Madam, I am talking about the necklace which women generally wear on some special occasion.

DR. MURLI MANOYHAR JOSHI (VARANASI): Will Shri Laluji accept this?…. (Interruptions)

KUMARI MAMATA BANERJEE: But if you want we can make it as diamond also……..*(Interruptions)*

In view of its importance for creating infrastructure in the country and generating employment I would like to declare it as the **"Diamond Rail Corridors"** project of the Indian Railways. The **Western corridor** passes through Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. Thank you very much for reposing confidence in the Railways………*(Interruptions)* यह वैस्टर्न कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है । इससे बहुत स्टेटों को फायदा होगा The **Eastern Corridor** will run from Ludhiana to Kolkata via Dankuni, covering the states of Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Prefeasibility studies for the other trunk routes viz; **North-South, East-West, East-South** and **Southern (Chennai-Goa) corridors** have been conducted and Ministry of Railways will take steps for further action in this regard.

The Government have approved the extension of the **Eastern corridor** up to Dankuni. To expedite the project execution in a time bound and cost effective manner, I will be setting up an expert committee who will look into all aspects and develop a **robust business plan**.

Delhi Mumbai Industrial Corridor is being developed in the area of influence of the Western Dedicated Freight corridor comprising industrial hubs,

rail port connectivity, logistic parks and mega power plants which will be executed in **public private partnership mode**.

I visualise an Eastern Industrial Corridor developing alongside the Eastern Dedicated Freight Corridor, similar to the Delhi Mumbai Industrial corridor. I propose to **put Railways land banks to productive use**. The hon. Prime Minister, Shrimati Sonia Gandhi and all the Leaders and all the hon. Members of Parliament of this House will be very happy with this. We are going to set up our land banks which will be utilized for industrial and national purpose……*(Interruptions).* It will not be done forcefully. We will identify them……..*(Interruptions).* This will also avoid increase in cost and will help in early start of industrial projects. In order to **catalyze industrial development in this corridor** I have included investments in rolling stock production and assembly facilities and coach rehabilitation at Dankuni, Majerhat and Naopara in this region. These will lay the foundation for a **rail based industrial cluster** in the Eastern Industrial corridor, drawing upon inherent advantages of proximity to coal and ore mines, large strength of labour force and India's largest metal works market.

Madam, there is a very **high demand for EMU/MEMUs and Metro coaches in the country** and capacity addition is an immediate requirement. We will speed it up in Raebareli and in other places. I **am happy to announce the setting up of a new coach factory** with state-of-art facilities exclusively to manufacture about 500 such coaches per annum in the **Kanchrapara-Halisahar Railway complex where Railway land is available.** This unit will be set up in **Joint Venture /Public Private Partnership mode.**

The Railways has already taken the initiative of setting up a power plant in collaboration with National Thermal Power Corporation at Nabi Nagar, which is expected to yield considerable saving in cost of electricity to the Railways. After

discussions with the Ministry of Power we **propose to set up a 1000 MW power plant at Adra** to avail traction supply at economical tariff. Madam as I had mentioned in my opening remarks, this project is of great importance as it would be located in an under developed tribal area, and will help in providing employment and **bringing the tribal people in to the mainstream.** As you know Lalgarh is on the border of Jharkhand and Bengal. It will cover Lalgarh, Purulia and Bankura which are tribal areas.

Training for employment.

हमें एक -दो करना है । आपने कितना किया है ?

श्री लालू प्रसाद (सारण) : मैडम मैं कोई टोका -टाकी नहीं कर रहा हूं । आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदयाः मैडम आप पढ़िये । आप लोक डिस्टर्ब मत कीजिए । श्री लालू प्रसाद जी कृपया आप बैठ जाइए ।

KUMARI MAMATA BANERJEE : India has one of **the world's largest populations of young people.** Development and upgradation of the skill sets of our youth is critical for their **economic empowerment** and a **better tomorrow.** Contributing to the National Skill Development Mission, we will strengthen our apprentices training facilities and the new facilities proposed at Dankuni will impart state of the art training to young artisans and supervisors. This would be a significant contribution to the national talent pool and would be another key input in making the Eastern Industrial corridor a key to the future development of the nation. That is why Dankuni will be the place where the Eastern corridor will be going. Everything has been mentioned in my speech.

Performance in 2008-09

Madam, despite the economic slowdown in the last financial year, the Railways loaded 833 MT of **freight cargo** which is a **5% growth over the**

previous year. Traffic Receipts grew by 11.4% to reach Rs 79862 cr. **A saving of Rs 676 cr** was achieved in expenditure, through stringent economy measures. Even after having disbursed **Rs. 13,600 cr. towards implementation of 6th Pay Commission recommendations** the Railways were successful in generating a **cash surplus before dividend of Rs. 17,400 cr.** and after fulfilling their **full dividend liability of Rs 4,717 cr** were able to maintain **internal generation** for investment at **Rs. 12,681 cr.** The **plan expenditure** for 2008-09 was about **Rs. 36,336 cr** as against the revised target of Rs. 36,773 cr. Budget Estimates 2009-10

Madam, I shall now deal with the Budget Estimates for 2009-10.

Madam, I am presenting the Budget Estimates for 2009-10 in the back drop of the shortfall in performance of the Railways in 2008-09. **Freight loading fell short** of the target of **850 MT** by 17 MT. Similarly, revenues expected from commercial utilization of surplus Railway lands also did not materialize. The primary cause for these shortfalls appears to have been the **economic slowdown.**

This has forced me to review the targets set for 2009-10 in the interim budget. Based on the review, it is very clear that the **unrealistically high targets set in the interim budget** are not sustainable and warrant a mid course correction. **I have now set more realistic targets for 2009-10** in the main budget based on the continuing trend of recession in the manufacturing sector and exports. However, I am **confident that with the combined determination of the 14 lakh strong railway family** we will come back to the house with an even better performance.

The freight traffic target for year 2009-10 has been fixed at **882 MT.** This will give an incremental loading of 49 MT over 2008-09, whereas incremental loading in 2008-09 was only 39 MT. This **ambitious target is being kept** in light of the special measures being taken by a government to give an economic stimulus as a counter recession measure and keeping in view the special efforts that the

Railways will make to attract more bulk traffic and new traffic streams. Efforts are also on to **capture long lead traffic.**

Madam, as I said earlier, I will cut short my speech.

With all these measures, goods earnings are projected at Rs 58,525 cr, which is Rs 5,092 cr more than performance of 2008-09. ***Passenger earnings are projected at Rs 24,309 cr. A growth of 10.8% has been provided** in keeping with the long term trend of growth.

The target for other **coaching earnings** is being kept at **Rs. 2,750 cr** which would imply **a growth of 40% of the performance in 2008-09.** I am of the firm view that proper marketing of our SLRs and running of premium parcel services will certainly help us realize this difficult target.*

Madam, the Railways has a vast potential for revenue generation from non-traditional sources. In **my previous tenure as Railway Minister,** I had initiated several measures in this regard. Enough efforts have not been made to realize this potential. **I will now develop new innovative ideas for land and air space utilization for commercial purposes through PPP mode**. Such business plans would be monitored closely to achieve substantial revenues over the next three years. The target for sundry earnings is being pegged at Rs 2,760 cr, but once these initiatives take shape I am confident that not only will we improve on this but will be able to do wonders.

Clearance from traffic suspense has been kept at Rs 75 cr as against the performance of Rs 25 cr achieved in 2008-09. Based on the forgoing projections, **Gross Traffic Receipts** have been projected at **Rs 88,419 cr** reflecting **an increase of Rs 8,557 cr on the actuals of 2008-09.**

…. This part of the Speech was laid on the Table.

I propose to retain the **Ordinary Working Expenses** at **Rs 62,900 cr**, to ensure that adequate provision is made for disbursement of 60 percent arrears in salary, due in 2009-10 on account of implementation of the 6th Pay Commission and for maintenance expenditure. However, I am simultaneously pursuing **stringent economy measures** to target a substantial saving in working expenses. **Total Working Expenses** are projected at **Rs 81,665 cr**, which include **Rs 5,325 cr** as appropriation to **Depreciation Reserve Fund** (DRF) and **Rs 13,440 cr** as appropriation to **Pension Fund.**

Even after having **absorbed the impact of 6th Pay Commission, to the extent of about Rs 14,600 cr in 2009-10**, the **cash surplus before dividend** of the Railways works out to **Rs 14,201 cr, Net Revenue** Rs 8,121 cr. and **Operating Ratio 92.5%.**

Madam I am proud that despite the combined impact of increase in Working Expenses due to the 6th Pay Commission and sluggishness in earnings due to the economic slowdown in the economy, Railways paid their full dividend liability of Rs 4,717 cr in 2008-09 and will **pay an even higher Dividend of Rs 5,479 cr in 2009-10.**

Based on above projections the Excess of the Railways for 2009-10 will be **Rs 2,642 cr,** which will be appropriated to Railways Funds.

Concessions

इज्जत

महोदया, हर आदमी इज्जत से जीना चाहता है । जिंदगी का सफर तो इज्जत से ही शुरू होता है । रेल का सफर भी एक जिंदगी का सफर है । मैं चाहती हूं कि हर आदमी हमारी रेल पर इज्जत से सफर करे । इसलिए गरीब से गरीब को भी इज्जत से सफर करने के लिए एक तोहफा देना चाहती हूं ।

I, therefore, announce a **new scheme called 'Izzat'.** Under this scheme, a uniformally priced **monthly season ticket of Rs. 25** would be available free of all surcharges for travel up to 100 kms for members of the unorganized sector with

monthly income not exceeding Rs. 1500/-. This will give lakhs of people in our country a chance to travel on rail with dignity. This scheme will be implemented with the cooperation of Members of Parliament. So, you have got a good work. It will be routed through all the MPs and Ministers. The Central Ministers as well as the District Magistrate can also recommened. This will be the administrative work. We will work it out. We want to involve all the MPs. If they recommend, then their ears will be covered. All the people will come to you and you will reach the grass root. I would now like to read a couplet.

'Bhanwar se lado,
Tum lehron se uljho,
Kahan tak chaloge
Kinare kinare '

Concessions to Press Correspondents

Now I come to the Press. **Instead of giving coupons**, it is now proposed to issue **photo identification cum credit card based** on the certification by the Press Information Bureau and other competent State and local authorities. On production of this card the Press Correspondents would be able to get reservation done and also tickets issued from the PRS/UTS counters through this card. Facilities would also be provided to get compact accommodation for both the Press Correspondents and their family members who are not availing this concession. In addition, **concession of 30% will be increased to 50% for Press Correspondents** अभी कंसेशन है । देखिए आप लोग काम करते हैं लेकिन बीबी को लेकर तो नहीं घूमते हैं । So permission **to travel with spouse at 50% concession will be given for once** a year.

Madam, student concession is already there up to 12th Class in general in the railways. The only thing is that Madrasa, high Madrasa and senior Madrasas should also be included in respect of the student concessions because student means all. It may be that some regional institutions and some Madrasa schools are

there. So, everybody will be included. The student concession is there up to 12th Class. The Madrasa, high Madrasa and senior Madrasa will be included.

Madam, the Indian Railway is having only one Metro Rail and that is Kolkata Metro Rail and there is no other Metro Rail. We are giving 60 per cent concessions on the metro fare to our students who are studying up to class 12th . I am happy to announce extension of concessional monthly season tickets available for students attending school up to Class XII, Madrasa, high Madrasa and senior Madrasa in Metro Rail, Kolkata. This would imply concession of 60 per cent for students on the metro fare. Students attending recognized vocational institutions will also enjoy this concession on the metro fare. I would request all over the country to give this concessions to the people in the metro rail because the Indian Railway is having only one metro. That is why we are giving 60 per cent concessions for students on the metro fare. So I will request other metro railways to provide these concessions. We will be grateful for this………*(Interruptions)*

Only Ladies Special

श्री लालू प्रसादः लेडीज स्पेशल ट्रेनें मुम्बई में है ।

कुमारी ममता बनर्जी : मैडम किसने चलायी हैं क्या हमने चलायीं हैं ? मैडम पीक आवर्स में लेडीज को बहुत दिककत होती है । इसी तरह अभी मुम्बई में जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें हम कोलकात्ता चेन्नई और दिल्ली में चलाएंगे । It will be only Ladies Special during the peak hours.

Madam, the number of working women in our country is on the increase. They face considerable difficulties in travelling for work. I therefore, announce the introduction of 'Only Ladies' EMU train services in Delhi, Chennai and Kolkata suburban on the pattern of Mumbai suburban. These services will run for the convenience of women passengers during office hours.

Train services

Yuva Trains: Madam, the young generation is our asset and we are proud of them. Due to economic difficulties poor youth are not able to travel on our trains. I will run **"Yuva Trains" dedicated specially for the young generation.** These trains will be introduced between major cities to ensure that the youth and low income groups can travel at low rates between these cities. The new low-priced fast train service will be started to connect youth in rural hinterlands to major metros/cities. The train will provide **air conditioned seated accommodation** and will run from point to point for distances ranging from 1000 km to 2500 km. The fare will be Rs 299 for distances up to 1500 km and Rs 399 for distances up to 2500 km.

A weekly service will be introduced as a pilot service within three months in the following sections-

a) Mumbai to Delhi

b) Delhi to Kolkata

If successful it will be extended to other areas of the country.

After Izzat, Student and Press concessions, ladies special and yuva trains, I now come to a new train service called Duronto: A new train service by the name **'Duronto'** with **AC and non-AC sleeper** will be introduced for **non-stop point to point** services between select cities throughout the country. This is a non-stop service from point to point. जल्दी पहुंचो कही रूकेगी नहीं । रूकावट के लिए खेद है।

For the first time in our history we will introduce nonstop trains.

AC and non-AC sleeper will be introduced for non-stop point to point services between select cities. I am giving it for the first time in the History…..*(Interruptions)*

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Is it a 'Duronto' train?

कुमारी ममता बनर्जीः बंग्ला में दुरंतो और हिन्दी में तुरन्त ।...... (व्यवधान)

Duronto Train services

There are some words from Bengali and Hindi mixed up.

जैसे इज्जत शब्द है । औधिकार हम बंग्ला में बोलते हैं और हिन्दी-उर्दू में उसको इज्जत बोलते हैं । तो ऐसा हो जाता है First time in history. हमने एक दर्जन दिया है । बाद में फिर रैक मिलेगा तो फिर देंगे । एक दर्जन नॉन स्टाप गाड़ियां होंगी जो रूकेंगी नहीं । स्टार्ट होंगी और पहुंचेंगी ।

1. New Delhi-JammuTawi Non stop (Tri-weekly)
2. Howrah- Mumbai (AC) Non stop (Bi-weekly)
3. Mumbai-Ahmedabad (AC) Non stop (Tri-weekly)
4. Chennai- Delhi Non stop (Bi-weekly)
5. New Delhi -Lucknow Non stop (Tri-weekly)
6. Delhi-Pune (AC) Non stop (Bi-weekly)
7. Howarh - Delhi Non stop (Bi-Weekly)
8. New Delhi -Allahabad Non stop (Tri- weekly)
9. Sealdah-New Delhi Non stop (Bi-Weekly)
10. Kolkata-Amritsar Non stop (Bi-weekly)
11. Bhubaneswar - Delhi Non Stop (Weekly)
12. Ernakulam - Delhi Non Stop (Weekly)

I am giving the names of a new trains because the time is very short. Only, within a month, it is very difficult to come up with this..*(Interruptions)*.--- अरे दिया है । आप देखिए तो पहले I am only giving the names of very few trains. It is not possible to do much within one month's Budget preparation. I will read it now.

सुनिये अच्छे से । ....(व्यवधान) अरे भाई सुनिये नहीं तो भूल जाएंगे तो कोई पॉइंट छूट जाएगा । ....(व्यवधान) गोहाटी है । आप देखिए ।

Other New Train Services

In view of the increasing demand of the passengers, I also propose to introduce the following train services. I am only giving a few trains as was possible in one month’s budget preparation.

a) **New Introductions**

1. Vishakhapatnam – Secunderabad -Mumbai Superfast (Bi-weekly)
2. Sriganga Nagar- Delhi- Nanded Superfast(Weekly)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISMUTHIARY (KOKRAJHAR): What about introduction of new trains from Murkongselek to New Delhi via the Bodoland?…*(Interrutpions)*

KUMARI MAMATA BANERJEE: All right, I promise that I will give you one.

3. New Jalpaiguri – Sealdah Superfast (Tri-weekly)
4. Bangalore- Hubli –Solapur Superfast (Tri-weekly)
5. Howrah – Bangalore Superfast (Weekly)
6. Pune- Daund- Solapur Superfast (Daily)
7. Ranchi –Howrah (3 days via Ghatshila- Kharagpur and 3 days via Asansol) Intercity (6 days a week)
8. Kamakhya – Puri Express (Weekly) यह भी नार्थ इस्ट है।
9. Jabalpur –Ambikapur Express (Tri- weekly)
10. Gandhidham- Howrah Superfast (Weekly)
11. Delhi – Sadulpur Express (Tri-weekly)
12. Ajmer-Bhopal Express (by integration of 9655/56 Ajmer- Ratlam and 9303/04 Ratlam – Bhopal express trains) (Daily)
13. Bilaspur – Tirunelveli Jn. (Thiruvananthapuram) Superfast (Weekly)
14. Mumbai – Karwar Superfast (Tri-weekly)
15. Durg- Jaipur Express (Weekly)
16. Dibrugarh Town – Chandigarh Express (Weekly) This is again concerning the North-East.
17. Delhi - Farakka Express (Bi-weekly)
18. Hazrat Nizammudin –Bangalore Rajdhani Express (Tri-weekly) via Kacheguda
19. New Jalpaiguri – Delhi Express (Bi-weekly) via Barauni
20. Mumbai-Varanasi Superfast (Daily)
21. Mysore- Yesvantpur Express (Daily)
22. Koraput – Rourkela Express (Daily) via Rayagada
23. Agra – Ajmer Intercity Superfast (Daily)
24. Mumbai – Jodhpur – Bikaner Superfast (Bi –weekly)
25. Agra- Lucknow Junction Intercity (Daily)
26. Hapa – Tirunelveli Jn. Superfast (Bi-weekly) via Thiruvananthapuram
27. Gwalior- Bhopal Intercity Express (5 days a week) via Guna
28. Kanyakumari – Rameshwaram Express (Tri-weekly) via Madurai
29. Howrah – Haridwar Superfast (5 days a week)

30. Varanasi- Jammu Tawi Superfast (Daily)
31. Gorakhpur – Mumbai Superfast (Daily)
32. New Delhi – Guwahati Rajdhani Express (Weekly) via Muzaffarpur

तीन हो गया । ....(व्यवधान)

श्री उमाशंकर सिंहः बिहार का नाम नहीं है । ....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जीः अरे भई क्या है ?

33. Veraval – Mumbai Link Service (Daily)
34. Ranchi-Patna Jan Shatabadi Express (Daily) क्या दिया नहीं है ?
35. Jhansi – Chhindwara Express (Bi-weekly) via Bina - Bhopal
36. Mumbai – Jodhpur Express (Weekly)
37. Jamalpur- Gaya Passenger (Daily) यह किसका है - बिहार का है ?
38. Jhajha- Patna MEMU (Daily)
39. Kanpur- New Delhi Shatabdi Express (6 days a week)
40. Bhopal – Lucknow – Pratapgarh Superfast (Weekly)
41. Lucknow- Rae Bareli –Bangalore Superfast (Weekly)
42. Shimoga- Bangalore Intercity Express (Daily)
43. Madurai – Chennai Express (Bi- Weekly)
44. Guwahati – New Cooch Behar Express Intercity (Daily) , again north-east
45. Balurghat – New Jalpaiguri Express (Daily) via Kishanganj
46. Alipurduar – New Jalpaiguri Express Intercity (Daily) via Siliguri
47. Dharmanagar- Agartala Fast Passenger (Daily)
48. Rewari – Phulera Passenger (Daily) via Ringus
49. Shoranur – Nilambur Road Passenger (Daily)
50. Coimbatore- Shoranur Passenger (Daily)
51. Mathura – Kasganj Passenger (Daily)
52. Farakka- Katwa – Azimganj – Nawadwip DhamExpress (Daily)
53. Bangalore – Kochuveli Superfast (Weekly)
54. Kolkata-Rampurhat Express (Daily)
55. New Jalpaiguri-Digha Express (Weekly)
56. Purulia-Howrah Express (Bi-weekly)
57. Kolkata-Bikaner Express (Weekly) via Nagore

Madam, in addition to this, I will announce the following trains: (a) Mangalore-Thiruvananthapuram (b) Eranakulam-Goa (c) Puri Bhubaneswar- Lok Manya Tilak (d) Puri to Surat via Sambalpur and (d) Bhunabewsar- Rourkela.

b) Extension of Trains

1 6517/6518 Bangalore-Mangalore to Kannur (Daily)

2 329/330 Andal- Sainthia to Rampur haat (Daily)

3 1105/06 Jhansi-Barrackpore to Kolkata (Weekly)

4 6787/6788 Madurai-Jammu Tawi to Tirunelveli (Weekly)

5 7013/7014 Hyderabad-Usmanabad to Pune (Tri- weekly)

6 2075/2076 Thiruvananthapuram – Ernakulam to Kozhikode (Daily)

7 213/214 Mysore-Tirupati to Chamraj Nagar (Daily)

8 2329/2330 Sealdah - New Delhi to Amritsar (Weekly)

9 5761/5762 Ranchi- Alipurduar to Guwahati (Bi-weekly)

10 9269/9270 Porbandar –Bapudham Motihari to Muzaffarpur (Bi-weekly)

11 1471/1472 Jabalpur – Bhopal Express to Indore (Daily)

12 6885/6886 Ernakulam – Tiruchchirappalli to Nagore (Daily)

13 2177/2178 Howrah- Agra Cantt Chambal Express Mathura (Weekly)

14 3113/3114 Kolkata – Murshidabad Hazarduari Express to Lalgola (Daily)

15 2993/2994 Mumbai- Jaipur Express to Delhi (Tri-weekly)

16 2555/2556 Gorakhpur- Bhiwani to Hissar (Daily)

17 2685/2686 Mangalore- Chennai to Puducherry (Weekly)

18 2143/2144 Nagpur – Gaya Deekshabhoomi Express to Chhatarpati Sahuji Maharaj terminal Kolhapur on one side and to Dhanbad on the other side (Weekly)

19 2725/2726 Banglore – Hubli Intercity to Dharwar (Daily)

20 8425/8426 Raipur – Bhubaneswar to Puri (Daily)

21 8413/8414 Paradeep – Bhubaneswar to Puri (Daily)

22 8415/8416 Puri – Kendujhargarh to Barbil (Daily)

23 2173/2174 Mumbai –Kanpur Udyog Nagari Express to Pratapgarh (Bi-Weekly)

24 1PR/2PR Pratapgarh –Rae Bareli Passenger to Lucknow (Daily)

25 2821/2822 Howrah-Bhubaneswar Dhauli Express to Puri (Daily)

26 4227/4228 Varanasi – Lucknow to Kanpur (Daily)

27 2985/2986 Sealdah – Jaipur to Ajmer (Daily)

Madam, in addition to extension, I will give one new train in the Jharsukuda-Gauwahati- Dibruagarh sector. कितना हुआ ....(व्यवधान)

c) Increase in Frequency

1 2685/2686 Chennai- Mangalore from 3 days to daily

2 2423/2424 New Delhi- Guwahati Rajdhani Express from 5 days to 6 days

3 2443/2444 New Delhi- Bhubaneswar Rajdhani Express from 2 days to 4 days

4 7091/7092 Secunderabad –Patna from 2 days to daily

5 2739/2740 Secunderabad – Vishakapatnam Express from 4 days to daily

6 2111/2112 Amravati-Mumbai Express from 3 days to daily

7 2957/2958 Ahmedabad – New Delhi Rajdhani Express from 6 days to daily

8 2149/2150 Pune – Patna Express from 4 days to daily

9 2487/2488 Jogbani- Delhi Express from 5 days to daily

10 2823/2824 Nizammudin-Durg Chhatisgarh Sampark Kranti from 2 days to 3 days

11 2985/2986 Sealdah- Jaipur Express from 2 days to daily

12 2905/2906 Porbander – Howrah (via Hapa) from 2 days to 3 days

13 4207/4208 Delhi – Pratapgarh Padmavat Express from 3 days to daily

International Co-operation

Both India and Bangladesh, on account of their shared history, have the advantage of vast and strategically linked rail network. Apart from interchange of freight trains, a passenger train called Maitree Express is also running between Kolkata and Dhaka since April 2008. In view of demand of passengers it has been agreed between two countries to reduce travel time and change the days of running. India

and Bangladesh are also in the process of enhancing cooperation in the railway sector including development of railway infrastructure in Bangladesh.

Annual Plan 2009-10

Madam, I took up the matter with the Finance Minister. After taking over the charge, I took up the issue with the Finance Minister. I am happy to say this. I am really grateful to the hon. Prime Minister, to the UPA Government and to our Finance Minister that we have received an increase of Rs. 5000 crore as budgetary support, over and above the Rs. 10,800 crore committed in the Interim Budget. Madam, the annual plan outlays of the Railways are a harbinger of economic stimulus for the country, the crying need of the hour. Reviewing the interim budget projection of Rs 37,905 cr for the Annual Plan 2009-10, within a few days of my taking charge, **I was surprised to find that there was a provision of Rs 3400 cr for resource mobilization through PPP, of which Rs 3300 cr would just not materialize.** This would imply a straight reduction in the Annual Plan to a level below the actual expenditure in 2008-09. I also learnt that the Railways had received less than their proportionate share of Gross Budgetary Support (GBS), as per the XI plan provisions. I immediately took up the matter **with the Finance Minister and am happy to say that we received an increase of Rs 5000 cr as budgetary support, over and above the Rs 10,800 cr committed in the interim budget.** This has enabled the Railways to step up the plan allocation to Rs 40,745 cr even after non inclusion of the provision of Rs 3300 cr for PPP on account of projects like station modernization, new locomotive plants as joint venture etc.

I am happy to inform the house that against all challenges and odds, the Railways will be able to deploy **internal resources at Rs 15,675 cr.** Market borrowing has been stepped up to Rs 9170 cr to support the higher requirement of rolling stock. The house will also be happy to know that **Finance Ministry has**

approved issue of tax free bonds by IRFC, for the first time, after a gap of several years.

I would like to share with the House a few important highlights of the plan allocations. In support of the numerous demands I receive from my colleagues in the Parliament and States, I have **increased the allocation** for New Lines from Rs 1100 cr in the interim budget to **Rs 2921 cr.** The provision for **Gauge Conversion is Rs 1750 cr, an increase of 24% over the interim budget.** In view of the pressure on internal resources, all Gauge Conversion, Doubling and Railway Electrification works have been trnsferred to Capital.

The interim budget provision for **Passenger Amenities was only Rs 502 cr,** after excluding the provision for Public Private Partnership. I am **extremely happy to inform** that the outlay **has now been increased to Rs 1102 cr, excluding PPP, which is an increase of 119%.** डबल हो गया ।

Madam, Railway men and women toil round the clock, facing a multitude of adversities to serve this nation and run nearly 17,800 trains every day. We need to address their basic needs. I am **increasing the allocation for Staff Quarters to Rs 335 cr, an increase of 49%** on the interim budget. Allocation for **Staff Amenities** is being increased to **Rs 424 cr** an **increase of 79%** on the interim budget.

Additional Funds to the tune of **Rs 1949 cr have been sought** from Ministry of Finance for National Projects of Udhampur-Srinagar-Baramulla, Jiribam-Imphal Road, Dimapur-Kohima, Azra-Byrnihat, Kumarghat-Agartala, Bhairabi-Sairong, Agartala – Sabrum and Sivok – Rangpo new lines, Bogibeel Rail-cum Road Bridge, Lumding-Silchar-Jiribam and Rangia-Murkongselek gauge conversion.

Urban Transport Services

Thane-Turbhe-Nerul-Vashi: With the completion of Turbhe-Nerul section (4.80 km), Thane-Turbhe-Nerul-Vashi project stands completed, facilitating running of direct trains between Thane and Nerul.

Mumbai Urban Transport Project (MUTP) Phase-II: MUTP Phase-II sanctioned in the Budget 2008-09 at a cost of Rs.5300 crore is under implementation. Pre-feasibility study for Mumbai Elevated Rail Corridor (Churchgate -Virar) to supplement the densely loaded and intensively utilized existing suburban system for Mumbai, is in progress.

The **Rail based suburban services** i.e. Metro Railway, Circular Railway and EMU services are the life line of the cities of Mumbai, Kolkata, and Chennai. Even after augmenting the capacity of the existing EMU trains by way of additional coaches and introduction of additional services, the rail based suburban system will not be able to meet the demand of the ever increasing population and do not provide rail based transport from origin to destination to the commuters. There is a perceived need to provide an energy efficient rail based system as a feeder route connectivity to the existing Metro/Circular Railway/EMU suburban system in these cities. Therefore, I am happy to announce a feasibility study for **introduction of energy efficient rail based system for providing connectivity to existing suburban system in the most efficient economic way in Kolkata, Mumbai and Chennai.**

Now, I come to the Kolkata Metro. It is the only Metro with us. That is why to expand the project we have decided to undertake the following works:

Kolkata has a **unique distinction of having a circular railway and metro under the Indian Railways**. Howrah having been declared as a world class station, there is a need to segregate the suburban services to accommodate upgraded facilities. In this context, decongestion of Howrah by shifting suburban

services to Saltgola will also be undertaken. For better integration, we plan to undertake the following works:

a) Dakshineshwar - Dum Dum – Barrackpore metro extenstion
b) Development of terminal at Majerhat
c) Majerhat-Diamond harbour via Joka
d) Majerhat to Diamond Harbour including Khidirpur- Garden Reach-Budge Budge. This is about my constituency. It is only a small one.
e) Dumdum to Garia via Rajarhat
f) Dumdum to Barasat metro extension
g) Park Circus to Bantala

Madam, the new rail line from Anantnag to Baramulla in Kashmir Valley has already been completed. Further, a national project like the **Quazigund-Anantnag line will be completed in Jammu and Kashmir by August 09 and will be inaugurated soon**. The work on the J&K project has got a setback as difficulties have been faced on part of the line from Udhampur to Katra and Katra to Quazigund.

The alignment on Katra-Quazigund section has been under review and an Expert Committee appointed to study the issues involved has recently submitted its report. Madam, **my foremost concern is the safety of the passengers. Therefore the decision in this project has to be made very carefully.** I will review the matter soon and **see how quickly this section of the national project can be taken up** for completion.

Madam, the Northeast region is very sensitive and its projects are in progress for providing connectivity to state capitals of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. In recognition of this, ten rail projects in this region have been declared as National projects, including projects like Bogibeel

rail cum road bridge and gauge conversion of Lumding-Silchar-Jiribam, Rangia-Murkongselek. The construction of national project in Sikkim from Sivok to Rangpo is proposed to be entrusted to IRCON for time bound completion. The surveys for new lines connecting Gangtok and Shillong have been completed and the proposals would be further processed for necessary clearances. A proposal for creation of **Northeast Region Rail Development Fund** has already been initiated to ensure necessary funds for timely completion of National Projects in the region.

The work of **Lumding-Silchar gauge conversion** is getting adversely affected due to adverse law and order conditions in the area. The matter has been taken up with the concerned authorities for providing necessary security so that the work could progress smoothly.

I am going to entrust responsibility for monitoring all national projects to a senior officer so that there is strict adherence to time schedules for completion. He will be accountable for this.

New Lines

Madam, target of 250 km has been fixed for construction of new lines in 2009-2010. Some prominent sections are as follows:

1. Ghoramara-Dumka of Deogarh-Dumka
2. Bishnupur-Gokulnagar of Tarakeshwar-Bishnupur
3. Lanjigarh-Bhawanipatna of Lanjigarh-Junagarh
4. Quazigund-Anantnag of Udhampur-Baramulla
5. Rewari-Jhajjar of Rewari-Rohtak
6. Kottur-Harihar
7. Churaru Takrala-Amb Andaura of Nangal Dam-Talwara

Gauge Conversion

During 2009-2010, a target of completion of gauge conversion of about 1300 km has been fixed including the following sections:

1. Pandharpur-Miraj of Miraj-Latur
2. Saharsa-Dauram Madhepura of Mansi-Saharsa- Purnea
3. Sitamarhi-Bairgania of Jaynagar-Narkatiaganj
4. Parlakimidi-Gunupur of Naupada-Gunupur
5. Mathura-Achnera
6. Aunrihar-Jaunpur
7. Fakiragram-Dhubri
8. Ratangarh-Degana of Sadulpur-Bikaner-Degana

This time, within a short time, we came with this. Within a short time, it is not possible to get all the projects cleared from the Planning Commission. After this Budget is passed, we will go through this and then we will take care of them.

9. Madanapalle Road -Dharamavaram of Dharmavaram-Pakala
10. Quilon-Punnalur
11. Baripada-Bangriposi of Rupsa-Bangriposi
12. Daboi-Chhota Udepur of Pratapnagar-Chhota Udepur
13. Wansjaliya-Jetalsar
14. Ajmer-Phulera
15. Bhildi-Samdari
16. Haibargaon-Mairabari
17. Vellore-Villupuram

देखा ना, हम लोगों का एक भी नहीं है ।

<u>13.00 hrs.</u>

Doubling

During 2008-09, 363 km of doublings were constructed whereas for 2009-10, target for doubling of 700 km has been fixed. इसमें होगा The work of doublings

of Phaphamau-Allahabad, Mansa-Bhatinda, Ghutiarisharif-Canning, Dakshin Barasat-Lakshmikantapur, Lohta-Badhoi, Jirat-Ambika Kalna, Magrahat-Diamond Harbour, Yesvantpur-Yelahanka, Yelahanka-Chennasandra, Brundamal-Jharsuguda Flyover, Gandhidham-Adipur, Gandhidham-Kandla Port and Nalikul-Tarakeshwar have been proposed in the Budget.

However, the House will appreciate that small is beautiful. I cannot do it everywhere. Wherever Railway is there, I can do small projects.

Madam, in this budget time for preparation has been very short. **Being an election year, expectations are very high.** There has not been enough time to process cases for approvals of Planning Commission. However, we will shortly be sending the major projects for necessary approvals. However, the House will appreciate that "Small is Beautiful". Therefore, in order to continue the pace of creation of infrastructure, I propose to process the following rail connectivity proposals.

a) New Lines:

1. Shahganj-Unchahar via Sultanpur, Amethi, Salon
2. Bongaon-Bagdaha
3. Banspani-Bimalgarh-Barsuan
4. Dankuni-Jorgalpara-Furfura Sharif-Jangipara-Bargachia
5. Chikballapur-Sri Satya Sai Prashanthi Nilayam
6. Balurghat-Hilly
7. Alamatti-Koppal
8. Salboni-Jhargram via Lalgarh, Belpahari. If this area is connected, I think the tribal people will get the development.
9. Bolangir-Nawapara Road
10. Digha-Jaleswar-Puri
11. Yadgir-Shahapur-Shorapur-Muddebihal-Alamatti
12. Bishnupur-Mukutmonipur
13. Gadag-Haveri
14. Samsi-Dalkhola
15. Krishnanagar-Beharampore via Chapra, Karimpur
16. Gadag-Wadi
17. Tarakeshwar-Magra restoration
18. Shimoga-Harihar

19. Kaliyaganj-Buniadpur
20. Madhuban-Giridih
21. Panskura-Ghatal-Chandrakona and Ghatal-Arambagh
22. Anekal Road-Bidadi
23. Namkhana-Bakkhali
24. Pune-Nasik
25. Joynagar-Raidigi
26. Rajkharswan-Ranchi
27. Hasnabad-Samshernagar
28. Medak-Akkanapet
29. Arambagh-Khana
30. Dantewara-Malkangiri
31. Canning-Gosaba via Basanti
32. Vishnupuram-Venukonda
33. Kakdweep-Sagar-Kapilmuni
34. Dullabcherra-Cheraji
35. Mandir Bazar-Ramganga
36. Sambalpur-Behrampur
37. Chalsha-Jhaldhaka
38. Madurai-Ernakulam (Cochin)
39. Ghatakpukur-Minakhan
40. Bilara-Bar
41. Baruipara-Furfura Sharif-Arambagh
42. Ratlam-Banswara-Dungarpur
43. Krishnanagar-Nabadwipghat extension to BB loop
44. Ramnagar - Chaukhutiya
45. Machhlandpur-Swarupnagar
46. Erumeli-Pathanamthitta-Punalur-Thiruvananthapuram
47. Ajmer-Sawaimadhopur via Tonk

48. Sainthia-Chowrigacha via Kandi
49. Yamuna Nagar-Chandigarh via Sadhaura, Naraingarh
50. Nanded-Bidar
51. Singur-Nandigram
52. Dabwali-Kalanwali via Sirsa
53. Mirik-Gangtok

b) Gauge Conversion

1. Chhindwara-Nainpur-Mandla Fort
2. Ahmedpur-Katwa
3. Nagbhir-Nagpur

c) Doubling

1. Tala-Princepghat-Majerhat
2. Secunderabad-Mahboobnagar
3. Sahibganj-Bhagalpur
4. Mokama-Ara
5. Rampurhat-Ghumani 3rd Line
6. Rewari-Hissar
7. Dankuni-Bally 3rd line
8. Bibinagar-Nallapadu
9. Krishnanagar-Lalgola
10. Rajkot-Viramgam
11. Bandel-Saktigarh 3rd line
12. Jhansi-Kanpur

Railway Electrification

The target for electrification during XI Plan is 3500 Route Kilometers with an outlay of Rs.3500 crores. In the first two years of XI Plan, 1299 RKMs has been electrified. Survey for electrification will be carried out for

1. Jaipur – Sawaimadhopur
2. Khana – Farakka Phase I upto Rampurhat
3. Guntakal – Guty - Bangalore

थोड़ा पानी पी सकती हूं ?

MADAM SPEAKER: Please.

कुमारी ममता बनर्जी : इतना बोला ना इसलिए

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): We are deprived of a train from Balurghat to Kolkata. There is no passenger train…..(Interruptions) So also, there is no passenger train from Balurghat to Malda; there is no passenger or express train from Balurghat to New Jalpaiguri. This is an underdeveloped area……..*(Interruptions)*

KUMARI MAMATA BANERJEE: You do not give me lessons. For thirty-three years, I know what you have done. Do not ask me this question right now. Let the Budget be completed. Balurghat project is there. You do not know that.

There have been demands from various quarters for making the **Tatkal Scheme** more user-friendly. I have decided to do just that. The period of advance booking under the Tatkal Scheme will be reduced from 5 days to 2 days, Tatkal tickets will be made available destination-wise instead of from end to end thereby reducing the financial burden on passengers. Madam, there are some complaints. Tatkal charges will now be levied as a percentage of the fare subject to a minimum of Rs. 100 instead of minimum of Rs. 150 at present. जो पहले ज्यादा लेते थे उसको कम कर दिया है ?

Madam, **there are considerable delays in project execution and implementation by the Railways.** All the initiatives indicated in the Budget and the projects taken in hand would have to be strictly monitored for implementation in line with fixed target dates. **I propose to develop a project monitoring mechanism** by setting up a project monitoring committee, so that time lines are strictly adhered to and there is no slippage in project delivery. With this, I hope to achieve substantial savings in cost associated with faulty planning and time over runs.

Madam, I am deeply conscious of the need to bring about a perceptible improvement in the travel experience of our passengers. Through this Budget, I am committed to several initiatives which I hope will bring highest satisfaction to the travelling public. I am also aware that the recession in the economy has caused much economic burden among the poorer section of our society also. That is why, **I do not propose any increase in the passenger fares of any class or category of trains. Similarly, I do not intend to increase the freight tariffs.**

Before I conclude, I would humbly submit to the House that I have had an extremely short time to prepare and present this Budget, in view of the election year. Therefore in the limited time, I have tried my best to cover the major facets of Railways. However I would like to inform the House that I will frame a suitable strategy and road map for the coming years. I propose to take **concrete steps to make Indian Railways a strong, responsive and vibrant organization, with higher levels of capability and effectiveness.** I would like to assure the House that Railways will come out with a **'White Paper'** indicating its present organizational, operational and financial status based on its performance in the last 5 years and develop a **Vision 2020** along with short **terms and long terms strategy and plan of action to realise it.**

I draw strength from these words of Gurudev;

**"And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions,
Knowing it is thy power gives me strength to act"**

Madam, everyone likes to live life in a humane manner. The Railways is an organization with twin responsibilities - commercial and social. It **will be** our **endeavour to render all commercial services with a human face.** Here I would like to quote a couplet.

**Roshni chaand se hoti hai sitaron se nahin,
Kamyabi manviyta se hoti hai, zulm se nahin"**

Madam, with these words I commend the Railway Budget 2009-10 to the House.

(Placed in Library, See No. LT – 33/15/09)

13.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

____

<u>14.32 hrs.</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-Two minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
Ist Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I beg to present the first Report of the Business Advisory Committee.

____

14.33 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation arising out of rapid spread of swine flu in the country

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.18, discussion under Rule 193.

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें जो आज नियम 193 के अंतर्गत स्वाइन फ्लू पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज 15वीं लोक सभा में पहली बार हमें बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वाइन फ्लू है, जिसे आज हम लोग आम चर्चा में स्वाइन फ्लू कहते हैं और तकनीकी भाषा में इनफ्लुएंजा ए, एच-वन, एन-वन वायरस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले दो-तीन महीने से इसने भारतदेश को ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिया है। कई तरह के आंकड़े आए हैं - कोई कहता है कि शायद लाख-डेढ़ लाख लोग पूरे विश्व में इससे प्रभावित हुए हैं और कुछ आंकड़े बताते हैं कि उससे ज्यादा भी शायद इसकी संभावित स्थिति हो सकती है। जब तीन-चार महीने पहले मैक्सिको में पहली बार इनफ्लुएंजा के एक म्युटेटेड वायरस का पता चला, तब से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन इस पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं और तमाम देशों के तमाम स्वास्थ्य संगठन भी इस पर नज़र रखे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें निरंतर खबरें मिल रही हैं कि किस तरीके से कुछ प्रदेशों से, राष्ट्रों से शुरू होकर, जिनमें मैक्सिको और अमेरिका शायद प्रमुख थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे यात्री, चाहे पर्यटन के रूप से अन्य देशों में गए हों या व्यावसायिक रूप से अन्य देशों में गए हों। जब वे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो इसके ज़र्म्स उनमें से कुछ लोगों के अंदर से अलग-अलग देशों को प्रभावित करते चले जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार 76 देशों में इसका असर पाया गया है और हिन्दुस्तान में भी अगर आज की संख्या ली जाए, तो शायद 118 या 120 के करीब लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आज सबेरे के अखबार में मैंने यह भी पढ़ा कि दुर्भाग्य से इस एच-1, एन-1 वायरस के असर से एक व्यक्ति की मृत्यु भी केरल प्रदेश में हो गई है। इनफ्लूएंजा वायरस के बारे में जहां तक तकनीकी जानकारी मिली है, उसके अनुसार इन्फ्लूएंजा के जो चार नोन वायरस थे, उनमें से एक सूअरों या स्वाइन्स में पाए जाते थे, जिससे इसका एक कॉमन नाम स्वाइन फ्लू रखा गया है, उसमें से और दो और तरीके के वायरस के मिल कर, दो और वायरस को आपस में म्यूटेट कर के एक नया वायरस बना है। इन्फ्लूएंजा हर साल होता है। विशेषकर जब सर्दियों का मौसम आता है, तो बहुत लोग इसकी चपेट

में आते हैं। शायद आधे प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत के बीच में इसका फर्टीलिटी रेश्यो भी माना जाता है। यह जो म्यूटेटेड वर्जन इसका आया है और जिन कारणों से इसके लिए चिन्ता, न केवल हिन्दुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व के लोगों में हो रही है, उसमें कुछ प्रमुख बिन्दु हैं, जिनका मैं पहले उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, पहले तो यह कि पुराने आंकड़ों की बनिस्बत, जिस दर से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, शायद इसका जो इन्फैक्शन रेट है, पुराने इन्फ्लूएंजा वायरस से ज्यादा तेज माना जा रहा है। दूसरे ज्यादातर यह देखा जाता था कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं या शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं या वे और बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन 60-65 साल के व्यक्तियों पर पुराने इन्फ्लूएंजा वायरस का ज्यादा असर होता था, जबकि इस स्वाइन फ्लू के वायरस का असर कम उम्र के लोगों, जवानों और नौजवानों को ज्यादा हो रहा है। मैंने एक जगह यह भी पढ़ा कि 17-18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के लोगों में इस वायरस का असर ज्यादा हो रहा है। यह भी देखा गया है कि पूरे विश्व में एक वर्ष में अमूमन पहले 30 से 35 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाया करती थी, लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर पुराने इन्फैक्शन के रेट माने जाएं, तो यह मृत्यु दर 45 से 60 हजार तक भी पहुंच सकती है। इन दो-तीन विषयों के कारण हम इसे चिन्ता के रूप में देख रहे हैं।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यू. एच.ओ. ने यह भी एक वॉर्निंग दी है कि इसका कुछ संबंध या इसके कुछ लक्षण, शायद 1968 में जो इन्फ्लूएंजा का एक वायरस पूरे विश्व में आया था, जिसमें अनुमानित रूप से पूरे विश्व में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे इसका संबंध दिखाया जा रहा है। इन कारणों से वे देश, विशेषकर हमारे जैसे देश, जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां साफ-सफाई के तौर-तरीके इतने अच्छे नहीं हैं, जहां हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी सुदृढ़ नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए यह विशेष चिन्ता का विषय बन जाता है।

महोदय, मैं एक बात के लिए जरूर भारत सरकार का स्वागत करूंगा और इनका अभिनन्दन करूंगा कि जैसे ही इसकी वॉर्निंग, जैसे ही इसके खतरे के संकेत हमें मिले, टूरिज्म विभाग से मिलकर, एयरलाइन से मिलकर, एयरपोर्ट से मिलकर, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो लीडरशिप दिखाई, उससे लोगों के बीच में बहुत आशा बंधी है और आश्वासन आया है कि इस बारे में हमारी सरकार सजग है। आज जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, उनमें आंकड़ों के हिसाब से ढाई से तीन लाख लोग हैं, फिर चाहे वे अमरीका से आ रहे हैं, साउथ अमरीका से आ रहे हैं या आस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उन्हें जांचा जाता है। सात या आठ जगहों पर ऐसी मशीनें भी लगाई गई हैं जिनसे होकर जो भी यात्री गुजरे, अगर उनका बॉडी टैम्परेचर सामान्य टैम्परेचर से ज्यादा होता है, तो वहां घंटी बज जाती है। उस व्यक्ति को जांचने के लिए तुरन्त डॉक्टर आते हैं और अगर उनमें इस वायरस के लक्षण मिलते हैं, तो उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में

अलग भर्ती कर लिया जाता है या एक वॉर्निंग देकर छोड़ दिया जाता है कि अगर ये सिमटम्स आगे बढ़ते हैं, तो वे स्वास्थ्य सेवाओं को इस बारे में बता दें या इसकी जानकारी दे दें। इस तरह की सुविधाएं बनाई गई हैं।

महोदय, 117-118 केस हिन्दुस्तान में पाए गए हैं। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के कारगर कदम भारत सरकार द्वारा न उठाए गए होते, तो शायद यह जो नम्बर अभी हमें छोटा लग रहा है, अभी हमें कंट्रोल में लग रहा है, यह शायद और ज्यादा होता, लेकिन इस बात से हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते कि इस समय इसकी फिडेलिटी, इस केस का जो रेट है, वह हमारे यहां कम है।

महोदय, आज सबेरे ही मैंने देखा कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी गति और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। अब बरसात का मौसम आ रहा है। हिन्दुस्तान में वैसे भी बरसात के मौसम में इस प्रकार के इन्फैक्शन और विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद सरदी का मौसम आएगा। उसमें इन्फ्लूएंजा या इससे जुड़ी हुई बीमारियां सरदी में और तेज होंगी। यहां स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनके एम.ओ.एस. साहब भी बैठे हुए हैं। इस समस्या को अभी तक तो उन्होंने बहुत कारगर रूप से संभालकर रखा है, लेकिन इसी कारगर तरीके से, इसी मुस्तैदी से वे इस बीमारी पर अपनी पैनी नजर रखें और एयरपोर्ट्स के द्वारा और स्वास्थ्य संगठनों के डाक्टरों के द्वारा इस पर जितने तगड़े तरीके से हो सके, इस पर ये कंट्रोल रखें।

एक और चीज़ है, मैंने यह भी देखा है कि हिन्दुस्तान में इसके प्रिवेंशन और बीमारी लगने के बाद जो दवाइयों की आवश्यकता होती है, उसका भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोड़-तोड़ कर लिया है। कहीं लिखा गया है कि शायद 15 लाख दवाइयां मंगा ली गई हैं, कहीं लिखा है कि नहीं, एक बिलियन के करीब दवाइयां मंगा ली गई हैं। अगर सही में यह एक एपीडेमिक का रूप लेती है तो हमारे पास सक्षम रूप से इतनी दवाइयों की संख्या हो जाएगी कि हम अपने नागरिकों को इस बीमारी से बचा पाएंगे।

कुछ यह बात भी चल रही है कि इसके वैक्सीनेशन पर अमेरिका में भी काम चल रहा है और मैंने बीच में देखा कि हिन्दुस्तान में इंडियन काउंसिल ऑफ मैडीकल रिसर्च के डॉक्टरों ने भी इस बात को कहा है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि इसके वैक्सीन को वे बना सकें और सितम्बर या अक्टूबर के महीने तक शायद यह वैक्सीन बन जाये। वह बने या न बने, यह तो वैज्ञानिक चीज़ है। मुझे मालूम नहीं है कि कितना आई.सी.एम.आर. के डॉक्टर्स हमें सही रूप में इस बात का आश्वासन दे पाएंगे या नहीं, वैक्सीन बने या न बने, लेकिन उन दवाइयों को तैयार रखने में जो तैयारियां की जा रही हैं, इस चीज़ को सरकार अपनी तरफ

से देखे कि तमाम अस्पतालों में ये दवाइयां पहुंचें, खासकर वहां, जहां हमारे हवाई अड्डे हैं, जहां बाहर से ज्यादा लोग उड़कर हिन्दुस्तान में आते हैं। वहां इन दवाइयों की, उपचार की व्यवस्थाएं की जायें।

एक और चीज़, जो कभी-कभी चिन्ता पैदा करती है, कई बार अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कई ऐसे नागरिक, जिन पर इस बीमारी के लक्षण पाये जाते हैं, जब वे एयरपोर्ट पर आते हैं और उन पर लक्षण देखे जाते हैं या उनसे कहा जाता है कि या तो आप कोरण्टीन में कुछ समय के लिए रहिये या अस्पताल में रहिये या डॉक्टरों के बराबर सम्पर्क में रहिये तो या तो किसी डर से या अन्य किसी कारण से कई मरीज ऐसे हैं, जो सुरक्षा चक्र से बाहर निकल गये हैं। वहां थोड़े बहुत सरकार को जरूर अपनी तरफ से कठोर कदम लेने पड़ेंगे, ताकि नागरिकों को यह पता रहे कि सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध की गई हैं, यह न केवल उनके लिए, बल्कि बाकी व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक हैं और ऐसे घेरे से बाहर जो मरीज निकलते हैं, उनको संवेदनशीलता से क्रिमिनल नहीं माना जाये। मैं यह नहीं कह रहा कि उनके ऊपर किसी रूप में कठोर कार्रवाई की जाये, लेकिन फिर भी कठोर रूप में उन पर एक अंकुश रखा जाये कि उनके द्वारा सामान्य जनता में यह बीमारी न फैल पाये।

इसको जिस तरह से डब्लू.एच.ओ. ने और हिन्दुस्तानी संगठनों ने कहा है कि इसमें एक पोटेंशियल है कि यह एक एपीडेमिक बन सकती है। उससे हम इस चीज़ को रोक पायें। स्वाइन फ्लू की जहां तक यह बात है, कुछ और सवाल भी इस पर उठाये जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके पीछे बहुत तथ्य है या नहीं हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि इसके पीछे कोई ठोस सबूत हैं या नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो कुछ ऐसे सवाल उठाये जा रहे हैं, उन पर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए।

एक बात हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में देखी है कि स्वास्थ्य से ज्यादा आज दवाइयों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि हमारे डॉक्टर्स स्वास्थ्य बेचते हैं या दवाइयां बेचते हैं। मैं सम्पूर्ण मैडीकल फर्टिनिटी की तरफ इज्ज़त से देखता हूं। मैं किसी एक पर आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन कभी-कभी मन में एक संदेह जरूर पैदा होता है और कुछ लोगों ने न केवल हिन्दुस्तान में, बल्कि बाहर भी इस स्वाइन फ्लू का उदाहरण लेकर, मैं फिर से यह नहीं कह रहा कि इस स्वाइन फ्लू के पीछे यह बात है या नहीं है, लेकिन इस बात को भी मन में रखना पड़ेगा कि कभी-कभी ऐसी बीमारियों को, जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आती हैं तो इसके पीछे फार्मास्यूटिकल कम्पनीज़ जिस मुस्तैदी से दवाइयां सामने ले आती हैं, एक वैक्सीन दो या तीन महीने के अन्दर उत्पादित हो जाती हैं और उस बात से कभी ऐसा लगता है कि जितने आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों से जिस तरह का उसके पीछे खौफ फैलाया जाता है, उससे उनका सम्बन्ध नहीं बनता है। उसके ऊपर एक नज़र जरूर सरकार को रखनी चाहिए,

क्योंकि जो कुछ बीमारियों में, कुछ केसों में हम लोग देखते हैं, विशेषकर फार्मास्यूटिकल कम्पनीज़ का जो रूप रहता है, वह बहुत ज्यादा जनहित में नहीं रहता है।

हमारी आज जो सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली है, जिसको हम पब्लिक हैल्थ सिस्टम कहते हैं, वह तो जरूर चरमरा गई है। आज हमारे सब हैल्थ सैण्टर्स हों या प्राइमरी हैल्थ सैण्टर्स हों या कम्युनिटी हैल्थ सैण्टर्स हों, मुझे मालूम है कि पिछले 5-7 सालों में जो हमारे हैल्थ मिशन के अन्दर हमने अपने सी.एच.सीज़. को, जी.एच.सीज़. को, एच.एस.ईज़. को सुदृढ़ किया है, उससे कुछ सकारात्मक असर कुछ प्रदेशों में पड़ा है। कुछ जगहों में राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता समझी है और उस पर कारगर कदम उठाये हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो चरमराता हुआ पब्लिक हैल्थ सिस्टम है, जिस कारण से भी हो, लेकिन क्योंकि यहां इनको संतोषजनक सुविधाएं नहीं मिलती हैं या इस कारण से कि एक प्रणाली ऐसी बन गई है कि जब तक आप प्राइवेट हैल्थ सिस्टम में नहीं जाएंगे, आपको वही स्वास्थ्य सेवाएं, जो मिल सकती थीं, नहीं मिलेंगी।

मुझे लगता है कि थोड़ी-बहुत साजिश के रूप में हमारी आज स्वास्थ्य प्रणाली भी इस देश में चल रही है। एक तरफ आप नियमित सुनियोजित तरीके से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बदनाम करते चले जाएं और बार-बार कोशिश करें कि इसमें वांछित लोगों को सेवायें न मिलें। जब व्यक्ति बीमार होता है, खासकर जब बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो वह सरकार की डिलेवरी के लिए इंतजार नहीं करेगा। उसको अगर सरकारी अस्पताल में संतोषजनक उपचार नहीं मिलेगा, तो वह अपने आप किसी अस्पताल में चला जाएगा, जो संभवतः प्राइवेट अस्पताल होगा। उस चक्र के अंदर हमने देखा है कि प्राइवेट सैक्टर धीरे-धीरे अपने पंजे हर जगह बढ़ा रहा है, उससे भी हमें थोड़ा-बहुत खतरा दिखता है। उससे हम सब को सजग होने की आवश्यकता है।

यहां बहुत से संसद सदस्य बैठे हुए हैं, सब जानते होंगे कि अगर हमारे पास दिन में 10, 25 या 50 व्यक्ति मिलने आते हैं, हमसे मदद लेने आते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार से किसी तरह से उनको मदद मिले, तो शायद 25-30 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे, जो स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी दिक्कत के कारण हमारे पास आते हैं। उनको या तो सुविधायें नहीं मिल रही हैं या खासकर जो हमारे शहर के सांसद होंगे, वे इस बात से मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि इस चीज से वे बेचारे डर जाते हैं कि उनके पिता जी को कोई छोटी सी बीमारी थी, उसको लेकर वे किसी अस्पताल में गए। उन्हें पता भी नहीं चला और तीन-चार दिन के अंदर उनके हाथ में पांच लाख का बिल थमा दिया गया। एक तरफ बीमार बाप है, दूसरी तरफ पांच लाख का बिल है। पांच लाख का बिल दें, तो बर्बाद हो जाए और अगर पिता जी का उपचार करायें, तो

परिवार पर कोई न कोई संकट आ जाए। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सबके सामने आज सबसे बड़ा कोई संकट है, तो वह हेल्थ के बिल का संकट है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज से 7-8 दिन पहले की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था। कुछ मित्र लोग भी हमारे साथ बैठे थे। जितने मित्र लोग वहां थे, वे संभवतः हिंदुस्तान के अच्छे समृद्ध परिवारों से आते हैं, अच्छी-अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। उनमें से कुछ इतनी तरख्वाहें पा रहे हैं कि शायद हम सब अपनी तनख्वाह मिला लें, तो भी उतनी तनख्वाह न पाएं। वे लोग जब मुझसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि उनके मन में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कोई ऐसी बीमारी न हो जाए कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर वे फंस जाएं। जब हिंदुस्तान के समृद्ध और संभ्रांत परिवारों के लोग भी हेल्थ बिल से डरते हैं, तो बाकी हिंदुस्तान का क्या हाल होगा, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

महोदय, स्वाइन फ्लू से मैं इसे सिर्फ इसलिए कनेक्शन देना चाहता हूं क्योंकि मुझे कभी-कभी संदेह होता है कि इन कई बीमारियों के पीछे या इन कई प्रणालियों के पीछे कहीं कोई और बड़ी ऐसी साजिश तो नहीं है, साजिश हमें मारने या बीमार करने की नहीं, बल्कि साजिश अपनी व्यावसायिक जरूरतों को आगे बढ़ाने की है, इसमें मुझे जरूर संदेह दिखता है। आज हम अपनी प्रणालियों को भी देखें।

महोदय, यहां स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनसे दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। मैंने भी देखा है कि सरकारी प्रणालियों में हम एक आसान रास्ता लेने लगे हैं। जो नयी-नयी स्कीम्स आती हैं, उन सब में हेल्थ इंश्योरेंस मुझे दिखता है। हेल्थ इंश्योरेंस का बड़े-बड़े देशों में क्या असर रहता है, अमेरिका जैसे देश में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर लोगों की क्या टिप्पणी है, यह सबको मालूम है। आज बार-बार यह कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उन अस्पतालों के नंबर इसमें हों। हम सांसद लोग भी कई बार डर जाते हैं और हम भी चाहते हैं कि अपने यहां के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सीजीएचएस स्कीम में उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएं या वहां सेवाओं में उसके नंबर आ जाएं, जहां हमारे गरीब जाकर किसी न किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर उसमें अपना उपचार करा सकें।

हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सभी को मालूम है। कुछ लोग यहां जरूर होंगे, जिनके परिवारों एवं मित्रों ने, सहयोगियों ने हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा निकालने की कोशिश की होगी। मेरे ख्याल से एलआईसी से पैसा निकालना ज्यादा आसान है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा निकालना दूसरी बीमारी की जड़ हो जाता है। अगर आप एक बीमारी से निकलेंगे, तो जब तक हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, तब तक शायद आदमी टेंशन से अलग परेशान हो जाए। यह छोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

महोदय, वर्ष 1945 में जब कांग्रेस के अंदर नए आने वाले हिंदुस्तान के संविधान के बारे में टिप्पणियां की जा रही थीं, तो हिंदुस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली को इतने सच्चे और सुदृढ़ रूप से लिखा गया

था, जो दुनिया में अपने लिए मिसाल हैं। उसके बाद वोहरा कमेटी रिपोर्ट के अंदर जिस तरह से हमने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को बनाया था, जिसे दुनिया में हर किसी ने सराहा कि हिंदुस्तान सही में असली कदम पर चल रहा है। उसका जब क्रियान्वयन किया गया, जब जगह-जगह ये सेंटर्स बने, तब देखा गया कि इस देश के गांव में जहां शायद कुछ भी नहीं था, हमारे दो-तीन सौ साल की गुलामी के अंदर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली कहीं नहीं फैली थी। हमें एक विश्वास हुआ कि हमारे डाक्टर्स, हमारी सरकारें जगह-जगह हमें स्वास्थ्य की सुविधायें देंगी। लेकिन 15-20 सालों में इसमें बिल्कुल एक विपरीत प्रभाव दिख रहा है। हम सब उसमें एक जगह शामिल हो जाते हैं। उन सब में हम सब कहीं न कहीं अपने आपको कमजोर पाते हैं। आज हम लोगों ने भी आसान रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, तो प्राइवेट में चले जाते हैं। मैंने खुद एक स्कीम को देखा, जिसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक सरकार इसी प्रदेश में है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके यहां अपने इम्प्लाइज़ का पहले से एक सिस्टम चल रहा था जहां सरकारी अस्पतालों में लोगों का उपचार होता था। किसी कारणवश उसने तय किया कि इसी चीज को हम प्राइवेट सैक्टर में दे देंगे और उनके बिल्स को रीएम्बर्स कर देंगे। छः महीने के अंदर-अंदर उसी राज्य सरकार को उस प्रोवीजन को वापिस लेना पड़ा क्योंकि केवल छः महीने के अंदर-अंदर उसका हैल्थ एक्सपेंडीचर चौदह गुना हो गया था। अगर साल में एक लाख रुपये खर्च होते थे तो चौदह लाख रुपये का बिल आने लगा, अगर एक करोड़ रुपये खर्च होता था तो चौदह करोड़ रुपये हो गए और अगर सौ करोड़ रुपये होते थे तो चौदह सौ करोड़ रुपये हो गए। यह बात हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम बार-बार कहते हैं कि हमें अपने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी हैं, तो क्यों न हम एक दूसरे हैल्थ सिस्टम की तरफ फिर से सोचना शुरू करें। आज हमारे सामने एक उदाहरण है जब हमने आज से करीब चालीस साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज बहुत से लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वे सेवाएं नहीं दीं जो शायद प्राइवेट सैक्टर बैंक दे सकते थे। लेकिन वे भूलते हैं कि आज के राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंकों में वे भले ही आपस में कमपैरीज़न कर सकते हैं। अगर हमें चालीस साल पहले नेशनलाइज़्ड बैंक प्रणाली नहीं मिली होती तो शायद उन तमाम कारीगरों या छोटे-छोटे व्यवसायों को, जो बैंक के लोन से चलते थे, पिछले चालीस साल में लोन न मिलते। आज हम जो आर्थिक रूप से सशक्त हिन्दुस्तान देख रहे हैं, उसमें नेशनलाइज़्ड बैंक प्रणाली का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपनी हैल्थ प्रणाली को नेशनलाइज़ कर सकें? मुझे मालूम नहीं है, यह एक बहुत ऊंची पॉलिसी का डिसीजन है, लेकिन इसे देखना पड़ेगा। हमें हर बार विदेशों की सफल प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता है। इंग्लैंड भी एक सफल देश है, कनाडा भी एक सफल देश है,

उनकी स्वास्थ्य प्रणालियां हमसे अलग हैं। वहां टोटली नेशनलाइज़्ड स्वास्थ्य सिस्टम है। क्या हम उसकी तरफ देख सकते हैं?

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से एक छोटा सा आग्रह और करूंगा। अगर आपको आज की वित्तीय स्थिति की व्यवस्था से लगता है कि हम सम्पूर्ण रूप से नेशनलाइज़्ड सिस्टम नहीं कर सकते, तो उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए हम फ्री हैल्थ सिस्टम की बात करें। जब मैं फ्री की बात करता हूं तो पूरे रूप से फ्री की बात करता हूं, उसमें ऑप्शनल नहीं रखना चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार यह कहे कि हमने हैल्थ सिस्टम दे दिया, फिर किसी का मन हो तो वह प्राइवेट अस्पताल में चला जाए क्योंकि उपाध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि अगर मेरी बाहों में मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं उस समय उसे अपने हिसाब से उस अस्पताल में लेकर जाऊंगा, मैं यह नहीं देखूंगा कि कोई सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है। अगर मेरा बच्चा मेरी बाहों में बीमार होगा तो मुझे शहर में जो सबसे अच्छा अस्पताल लगेगा, मैं उसे वहां लेकर जाऊंगा। इसलिए मेरे सामने वह विकल्प नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छे डाक्टर उसी अस्पताल में मिलने चाहिए जिस अस्पताल की सेवाओं के लिए सरकार कहती है कि मिलेंगी। अगर आप सब उम्र के लोगों के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चों के लिए करें। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस सरकार को आने वाले समय में पांच साल हैं। पिछली बार भी इस सरकार ने कई क्रान्तिकारी कदम उठाए। जब NREGA की बात आई थी तब बहुत से विशेषज्ञों ने कहा था कि आप एक ऐसे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो कभी क्रियान्वित नहीं होगा। कुछ आर्थिक लोगों ने यह भी बताया था कि आप ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिससे सरकार की पूरी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, NREGA में ही सारा पैसा लुट जाएगा। हमें जितनी वार्निंग्स मिली थीं, वे कोई भी सही साबित नहीं हुईं, क्योंकि सरकार ने हिम्मत की, जनहित में एक ऐसा कदम रखा जो जनहित के लिए आवश्यक था और आज हमें उसकी नतीजे मिले। आज दिखता है, आज हमारी लेबर भी कम माइग्रेट कर रही है, जगह-जगह रेट्स भी बढ़े हैं। खैर वह अलग बात है। मैं कहना चाहता हूं कि मौका है और हम ऐसे कदम लें जिससे जनता को लगे कि सरकार ने उनके हित में कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं। अगर हमें अपना स्वास्थ्य सिस्टम बदलना है तो बदलें और स्वास्थ्य सरविलैंस प्रणाली बदलनी है तो बदलें। मैंने स्वाइन फ्लू से बोलने का मौका इसलिए लिया है कि क्योंकि आने वाले समय में बजट आएगा, उसके बाद हमें तीन-चार महीने के लिए संसद में बात करने का समय नहीं मिलेगा, फिर विंटर सैशन हो जाएगा तो और प्रणालियां चलेंगी।

इस समय सरकार कई चीजों को सौ दिन में देखना चाहती है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना मत रखने का यहां एक मौका भी था।

मैं आज फिर से संसद के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके डिप्टी साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कोशिश की है और एयरपोर्ट्स में न केवल कोशिश दिखती है, बहुगुणा जी हमारे बहुत सम्मानित कुलीग हैं, वे अभी बता रहे थे कि वे कुछ दिन पहले विदेश यात्रा से आए। वे आए तो उन्हें पहला दृश्य जरूर डरावना दिखा जब उन्हें यह दिखा कि कस्टम के सारे अधिकारी अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन वे बताते हैं कि उन्हें उससे एक संतोष भी हुआ, उन्हें दिल में दिलासा मिली कि इसका मतलब है कि यह प्रणाली मेरी सेवा करने के लिए, मुझे ठीक रखने के लिए, मेरे हिन्दुस्तान को इस वायरस से बचाने के लिए आज सजग है। मेरी बेटी कुछ दिनों पहले बाहर से आयी थी। जब उसे हम एयरपोर्ट से लेने गये तब हमें संतोष हुआ कि एयरपोर्ट पर हमारे अधिकारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं कि कोई भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति वहां से न निकल सके। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग्स दी हैं और उन वार्निंग के पीछे तथ्य है, तो उस पर हमें कन्टीन्युअसली पैनी नजर रखनी पड़ेगी।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो दो छोटी-छोटी बातें कहीं--एक यह कि इसके पीछे स्वाइन फ्लू में वह डर है, जो डब्ल्यूएचओ कहता है, तो उस पर हमारा स्वास्थ्य विभाग एक नजर जरूर रखे। दूसरा, हमारा चरमराता हुआ जो पब्लिक हैल्थ सर्विस सिस्टम है, उसे सुदृढ़ करना। आज हमें प्राइवेटाइज हैल्थ से जो चैलेंज मिल रहा है, मैं उसे केवल स्वास्थ्य बांटना नहीं कहूंगा, जो अपने आप में स्वास्थ्य द्वारा मुनाफा कमाने की बात करता है, उस पर अंकुश लगाना है। हमें ये विकल्प भी मिलें कि अच्छे डाक्टर्स, अच्छी दवाइयां हमें अपने अस्पतालों में मिले, अपने प्राइवेट हैल्थ सैंटर्स में मिले, अपने सीजीएचएस में मिले, अपने सब हैल्थ सैंटर्स में मिले। इन तीन बातों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और एमओएस साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात सुनी।

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Mr . Deputy-Speaker, Sir, before I begin my speech, I would like to compliment the hon. Minister of Health and Family Welfare – well, not compliment but I would like to appreciate the fact that after five years of 'drought' in the Health Ministry, we have the promise of rain. I know that the hon. Minister and the hon. Minister of State are both good administrators and reasonable people. I have a great deal of expectation for the first time from this Department.

Sir, I have no doubt that the reason I have been asked to speak on Swine Flu by my Party is because it has the word 'swine' in it. The pig is a much maligned animal. It is an extremely useful member of our world. It acts as scavenger in areas where there are no humans to clean up the messes that humans create. However, this speech is not a paean to the pig as we know it. It is about the recent so-called Swine Flu epidemic.

Why is it called Swine Flu? It is because the virus is supposed to have originated in 1918 at a pig fair where humans and pigs got sick together. It later emerged, as it has now, that pigs catch the flu from humans and not humans from pigs. That is the only relationship it has with that poor animal. Actually, it is a simple type, it is a simple influenza strain of which there are hundreds. The H1N1 form of flu is one of the descendents of the strain that caused the 1918 flu pandemic in humans. It was not a pandemic then. But it was even then touted as a pandemic. As well as persisting in pigs, the descendents of the 1918 virus have also circulated in humans throughout the 20^{th} century without causing any epidemic much less, pandemic, except now in the media and have contributed to the normal seasonal epidemics of influenza.

Again, I am going to go back. Before I take on Swine Flu or H1N1, I want to talk about Swine Flu in pigs and the reason why I come back to pigs, even though this Swine Flu has nothing to do with them, is because most of the viruses that we stand in danger of getting may originate in the pig. Animals that are reared in inhuman, cooped up, filthy factory farms, fed badly on bad food, often eating

their own neighbours are the victims of many diseases of which the strains of flu as in Avian Flu are the most common.

It will come as a surprise to nobody in this House that sixty per cent of all the antibiotics produced in the world are fed to animals in these factories in which they are reared for meat and milk. Since the meat carries the residues of the antibiotic, it explains why humans are becoming increasingly resistant. The H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 and H2N3 are swine influenza strains that are common in pigs in all countries from the Americas to Asia. However, these do not transmit to humans as yet. Even if exposure to them by workers in pig farms takes place, all that happens is that antibodies build up in the body. There has been no transmission from human to human either. But pigs die from flu all the time.

15.00 hrs.

Indian factory farms have extremely unhealthy, flu and other disease ridden pigs all the time and yet people eat their meat. However, to come back to today's subject, the 2009 swine flu outbreak in human-beings is due to influenza A virus sub-type H1N1 that contains genes which are related to the 1918 influenza, as I said before. But the origin of this new strain is unknown and it has not been isolated in any animal. It is simply transmitted from human to human, and causes the normal symptoms of influenza.

In humans, the symptoms of H1N1 or swine flu are similar to those of normal influenza and of influenza-like illnesses - chills, fever, sore throat, muscle pain, severe headache, coughing, weakness and general discomfort. But flu, for a long time now, has been an ideal reason for panic-mongering and this has happened so many times that one gets cynical about the reasons and assumes that they are commercial with panics being created by medicine-sellers.

Let us look at the history of H1N1. In February, 1976, an Army recruit in Fort Dix, America, died after showing symptoms of flu - tiredness and weakness. Two weeks later, American health officials announced that he had died of swine flu. Immediately the country decided that it was in the middle of a pandemic – as

you know, a pandemic means a disease that is spreading all over the world - and President Ford ordered every American to be vaccinated against swine flu. He was vaccinated on television himself and so were 40 million people or 24 per cent of the population. While nobody else got or contracted this flu from February to October, 1976, three people died of the vaccinations, more than 500 people became paralysed because of the vaccinations and after that, 25 people died after being paralysed. In December, it was called off. While the swine flu was said to become a pandemic, the vaccinations were the actual villains. The programme was called off and swine flu H1N1 was never heard of again.

Now in 2009, we come to the same sub-type H1N1 and again it was called swine flu because it originated supposedly in people in Mexico who blamed it on pigs, but it was the pigs who got it from the human-beings. Then immediately, the United States declared it a pandemic. Most countries have again been set off on a wrong track and have wasted money and time by killing pigs as they have in Egypt. In fact, they have killed more pigs in Egypt while they have not had a single case so far of Swine Flu, than, they have spent on the entire health budget.

We, in India, are quick to go completely crazy with every alert sounded by the West. Unfortunately, our scientists do not probe deeply into so called pandemics. The avian flu is one case. We killed crores of birds, mainly belonging to the tribals and poor people. We did not kill a single bird in multi-crore farm factories in Pune, for instance, that keep chickens in much worse conditions than the villagers do. But this is a scandal that needs an enquiry by itself. The previous Health Minister bought hundreds of crores worth of so called avian flu medicines, none of which was ever used or will ever be. That is another scandal that needs an inquiry. What our scientists should realise before adopting western panics as their own is that the swine flu has been compared by WHO itself to all other similar types of influenza virus in terms of mortality. This is what the WHO says. “In the US, for every 1,000 people who get infected with any strain of flu, 40 people need admission to hospitals and one person dies.” This is even a higher ratio than what

we claim for swine flu. India has no central records of checking who dies of what and in which hospital, and we are not even working towards central record keeping.

Therefore, we have no idea of how many people die of an average flu, and we resort to knee-jerk reactions prompted by scaremongers in other countries.

We have spent so much media space and money on detecting people with the so-called flu symptoms. We have isolated people; given press conferences; and gone after people who have supposedly run away from isolation units and recaptured them only to find that we have no cases of swine flu. Have we applied the same vigilance to cases of polio, which crop up regularly? Do we catch those people who refuse to get polio shots? No, we do not. Have we applied it to malaria or to that increasingly dangerous killer, namely, tuberculosis ?

In my Constituency, just last week, I was called-up by an anxious father whose son of five years had been diagnosed with TB. He was told by the Central District Hospital that the medicines would reach his house on the 23rd of June as is the system in Uttar Pradesh. The system is that people will come to you with the medicine, but you cannot pick it up yourself. The deliverer never arrived, and he called me. I spoke to the CMO and it turned out that the man who was supposed to give him the medicines had instead gone to attend a wedding. Should we not put more time and media space into stopping the diseases that we already have, and improving the delivery systems of medicines instead of adopting new and fanciful completely artificial diseases? Flu is normal, and all its strains are normal including Swine Flu H1NI.

In humans, the symptoms of the 2009 H1N1 virus are similar to those of influenza in general. It cannot be spread by eating pork products since the virus is not transmitted through food. All we need is the standard prevention against spreading of the flu virus from human to human, which is frequent washing of hands with soap and water, especially, after being out in public, and disinfecting surfaces, especially, household ones as it is important. Influenza can spread by

cough and sneezes, but an increasing body of evidence shows small droplets containing the virus can remain on tabletops, telephones and other surfaces in which case an alcohol-based gel or foam or hand sanitizers work well to destroy the viruses and bacteria. Anyone with flu-like symptoms such as fever, cough or muscle aches should stay away from work or public transportation. That is all. We are over reacting. We are spending crores of rupees for something where only these two things work.

Please do not spend public money again scandalously by buying newly-invented commercial foreign vaccines or spend our scientists' time in inventing vaccines for a flu that will not be here by next year because it would have mutated into HIN10 or whatever. The normal flu vaccine that has been in the market for several years now has been proven ineffective in every single form of flu that it was supposed to inoculate us against, and a new vaccine will again be more dangerous than helpful. We are told that America is at work on a vaccine for the new strain, but it would have gone and mutated long before we are ready.

Tamiflu is what you will choose as the answer because you have already stockpiled Tamiflu in crores for Avian Flu. You do not know what to do with it since Avian Flu has disappeared instead of being the pandemic that killed one billion people. You have said that now we will use Tamiflu for Swine Flu and not for Avian Flu. This is not the answer. It has never been -- not even to the predecessor Avian flu and not now also. Have the crores worth of Tamiflu bought by the Health Ministry in the last five years ever been released into the market? Even the antibiotics bought for the so-called plague 20 years ago were lying at the Customs till last year.

The truth of the matter is that normal antiviral drugs make the flu milder and the patient feels better faster. Palliative care, at home or in hospital, focuses on controlling fever and maintaining fluid balance for the treatment of flu viruses. The adage that applies to all flus applies to this one as well, which is that with medicine it takes a week and without medicine it takes seven days. The majority

of people infected with the virus make a full recovery without requiring even medical attention or antiviral drugs.

This is just another type of flu virus or our typical seasonal flu symptoms. So far, even if you see swine flu cases increase on a swine flu map, experts do not know till today whether this influenza A (H1N1) virus will become a pandemic or even a nuisance. We could just continue to see sporadic cases for a few weeks or months till it stops.

SARS, if you remember, was touted as the killer of millions. Does anybody even remember what SARS stands for or whether it actually killed a single human being? However, I would like to say that the global pharma companies like Roche, Gilead, and Glaxo SmithKline are making a killing through the sales of antivirals like Tamiflu and Relaxin. The US Administration has already opened an emergency window in its authorisation system to allow Tamiflu and Relaxin to be used more widely on flu sufferers across the world. Even the small vaccine producers like Biocryst and Novavax are hiving for profit. India has bought Tamiflu, but has not authorised its retail sales. Strangely enough, the reason that your Ministry has given for not giving Tamiflu to the public in spite of giving the scare that swine flu exists is, "Indiscriminate use of this drug by the public could result in the virus developing resistance to this only known treatment of the H1N1 influenza". This is what your Government has officially said. You keep buying it, but you never give it to us. You never allow anybody to use it because if we use it, we might get immune to it. We buy an imaginary medicine for an imaginary disease, and who gets to live happily ever after – the companies, the Ministry, the Government, the sellers, the buyers?.

I would like to say that perhaps we should downplay our great insistence on and the amount of money we are spending on swine flu, and divert it back to our original diseases. Before I finish, I would like to go back again to the word 'swine' and 'pigs' because it is really important. Pigs are unusual as they can be infected with influenza strains that usually infect three different species: pigs, birds and

humans and it can go anywhere. This makes pigs a host where influenza viruses might exchange genes, producing new and dangerous strains. Therefore, I would suggest that the Health Ministry should also start looking at the way we farm pigs. GIGO (Garbage In, Garbage Out) is a standard principle. Come to the basis of what is spreading Tuberculosis or what is spreading malaria or what is spreading diseases. It all comes back to what we eat and how we treat them. I would urge the Members of Parliament to do checks on all factory farms in their areas and see the hideous conditions in which animals are grown for meat because this has become the norm. All the diseases in the last five years that we have spent our money on have been a result of the way that we have brought up chickens, pigs, goats, and cattle Tuberculosis comes from factory farming of cows and buffaloes. This is the lesson that we can learn from H1N1.

If we want a healthy happy world, we must understand that all species in it have to be healthy, or we will live in constant danger.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अंतर्गत स्वाइन-फ्लू पर भाई संदीप दीक्षित जी और पबन सिंह घाटोवार जी ने जो चर्चा सदन में कराई, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली बार हम लोग शुन्यकाल में स्वाइन-फ्लू पर अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन हमें इसके लिए मौका नहीं मिल सका। अभी भाई संदीप जी ने और आदरणीय मेनका गांधी जी ने स्वाइन-फ्लू के बारे में बड़े विस्तार से बातें बताईं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद बहुत योग्य और वरिष्ठ मंत्री हैं। स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा आज से नहीं बल्कि मार्च 2009 से बहुत जोरों से है। यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 1998 में जब पहली बार उत्तरी केरोलिना में स्वाइन फ्लू फैला, उसका वायरस ट्रिप्पल हाई ब्रीड था। वह आदमियों में भी था, पक्षियों में भी था और जानवरों में भी था। इस बारे में तरह-तरह की भ्रांतियां हैं, हम लोग लेख भी पढ़ते हैं और बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी इस खोज में लगे हैं कि यह स्वाइन फ्लू क्या है, यह कैसे जनरेट हुआ और कहां से आया, यह अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। दुनिया के समाचार पत्रों में आंकड़ों के बारे में समय-समय पर लिखा जाता है कि 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है और 2371 लोग अभी तक मर चुके हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): दुनिया के 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जी हां, दुनिया के 116 देशों में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है और इससे 2371 मौतें हो चुकी हैं। जैसा संदीप दीक्षित जी ने कहा और हमने समाचार पत्र में भी पढ़ा कि हिंदुस्तान में भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो चिंता का विषय है।

SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, I may not get an opportunity to reply today because hardly ten to fifteen minutes are left and I shall have to reply on Monday only. It has been reported in newspapers and it has appeared in one of the channels also that one patient has died in Kerala. I would like to make it clear that he has not died of Influenza A H1N1 because the State Government had sent the sample for testing to Delhi and the report was found negative.

श्री शैलेन्द्र कुमार : जैसा मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है, यह बहुत अच्छी बात है।

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): While I deeply appreciate the measures that you may have taken at airports etc., and perhaps we congratulate ourselves that the measures that have been taken at airports have prevented the

swine flu. But all the countries that have taken no measures at airports have also found no swine flu.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I will reply that on Monday. But at this time, since it has already appeared in the Press that one person has died so far, I would say that let us keep our fingers crossed that not a single person has died of swine flu.

श्री शैलेन्द्र कुमार : मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, यह बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की बीमारी न फैले और किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक इस बीमारी की दवाई की खोज करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लोगों का सही ढंग से टीकाकरण हो और लोगों में यह बीमारी न फैले, इस बारे में डाक्टर्स को सफलता नहीं मिली है। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि मैक्सिको के अंजान शहर लागलोरिया में यह फ्लू पैदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमने लेख पढ़ा है कि यह सुअर से, पक्षियों से या जानवरों से या कचरे से या फैक्ट्रियों से या केमिकल से या खाद्य सामग्री से फैला, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। इस बारे में जानने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं। जहां तक हमारे देश की बात है, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा, टेलीविजन में भी हम देख रहे हैं कि विदेशों से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उन पर निगरानी रखी जाए। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे बड़े शहर, जहां विदेशों से फ्लाइट्स आती हैं, वहां विशेष तौर से इस बीमारी के लिए लोगों का चैक-अप होना चाहिए। मैंने देखा कि लोग बाहर के देशों से यह बीमारी लेकर अपने देश में आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिन्हें लेकर इस बीमारी को कुछ घंटे तक दबाया जा सकता है लेकिन जैसे ही इन दवाओं का असर खत्म होता है स्वाइन फ्लू का मरीज अपने असली रूप में आ जाता है। यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने और साथ उठने-बैठने से भी यह बीमारी फैल रही है। हमें इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। इस बीमारी से निपटने की जानकारी की व्यवस्था केवल एयरपोर्ट्स में ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी होनी चाहिए। लोग हवाई जहाज, रेल और पानी वाले जहाजों में भी यात्रा करते हैं इसलिए तमाम बंदरगाहों पर भी इसका इंतजाम होना चाहिए। इन सभी जगहों पर जांच के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर बैठने चाहिए जो विशेष तौर पर इसकी निगरानी करें ताकि एक जगह से दूसरी जगह यह बीमारी न फैल पाए।

जहां तक भारतीय डॉक्टरों की बात है, बाहर के देशों से बहुत से मरीज हमारे देश में आए हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के डॉक्टर स्वाइन फ्लू को डाइग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि रोज न्यूज पेपर में पढ़ने को मिल जाता है कि इक्का-दुक्का मरीज यहां पाया गया है। इस तरह के समाचार पढ़ने को

मिलते हैं। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी, हैल्थ सैंटरों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि बहुत से मरीज डर कर शहर में ही न रहें और कहीं पलायन कर जाएं इसलिए हमें विशेष तौर पर निगरानी करनी पड़ेगी।

महोदय, दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी और सीएचसी के संबंध में चाहे सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्ता करने की जरूरत पड़े, वह कीजिए। इसके साथ यह भी बात की जाए कि यह बीमारी जो महामारी के रूप में फैल रही है, इस पर कैसे कंट्रोल करें। इससे पहले चेचक उन्मूलन के लिए वैक्सीन मंगाए गए और यह जड़ से खत्म हुआ। अब पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो ड्राप्स पिला रहे हैं। अभी हमारे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में सैंकड़ों चेचक के मरीज देखने को मिले। पिछले कुछ वर्षों में चेचक खत्म हो गया था लेकिन इस क्षेत्र में छोटे दाने से लेकर बड़ी चेचक के रोगी पाए गए हैं। हमें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि यह तो देश से खत्म हो गया था लेकिन इस जगह चेचक उभार पर है। अब जरूरत इस बात की है कि जो पुरानी बीमारियां हैं, उसे देखें क्योंकि यह कहा जाता है कि स्वाइन फ्लू मलेरिया का ही बिगड़ा स्वरूप हो सकता है। इससे पहले इसी सदन में तमाम बातें उठाई गई हैं, खास तौर से बांग्ला देश और सीमा से लगे देशों के जिलों में बाढ़ या सूखे के समय तमाम बीमारियां शीघ्रता से मानव के ऊपर असर करती हैं इसलिए इन पर कंट्रोल करना आवश्यक है। आप बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, आप चाहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का एक सम्मेलन आयोजित करें ताकि स्वाइन फ्लू का जो खतरा हमारे देश में बढ़ रहा है इसे कंट्रोल किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप इसे रोकने के लिए कार्य योजना बनाएंगे और रोकने की पूरी कोशिश करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to take part in this short duration discussion on rapid spread of swine flu in the country. I thank Mr. Sandeep Dikshit my esteemed colleague and my good friend Mr. Paban Singh Ghatowar for bringing forward this motion for discussion in the House.

We have hardly discussed, particularly the debate put forward by Shri Dixit, who has deliberated here several aspects of this sort of problem in our country in great detail. My other esteemed colleague, Shrimati Maneka ji, deliberated in detail this issue, the pros and cons of this problem, in her speech. I am entirely in agreement with her views on this problem because with such types of problems panic is created. Many times, the real cause is unfounded and this problem is creating panic among the people. Many times such type of diseases cause epidemic or pandemic health problem. These days, panic has been created mainly on this sort of problem by the vested interests.

Sir, on this particular problem, recently, I have gone through a journal – The New England Journal of Medicine – which surprisingly revealed that a particular virus is responsible for this sort of infection in the human beings, which is called, Swine Flu. I am in agreement with Madam Gandhi that basically the swine is not creating this problem but they are the victims of this infection mainly from the human source. The cause of recent pandemic, according to the new studies, scientists investigating the genetic make up of Flu Virus have concluded that there is a high probability that the H1N1 strain of Influenza A behind the current pandemic might never have been reintroduced in the human population, were it not for an accidental leak from a laboratory working on the same strain in 1977.

The New England Journal of Medicine comments that the re-emergence was probably an accidental release from a laboratory source. Two famous scientists working in this area - Shanta Zimmer and Donald Burke from the University of Pittsburgh in Pennsylvania - said that frozen samples of the virus stored in the laboratory since 1950s, and most laboratories doing research on Influenza would have the 1950s strain and one cannot pinpoint actually a particular laboratory is responsible for its accidental release but the re-emergence of H1N1 in 1977 made it potentially a man-made pandemic.

Therefore, it is also reminded that we need to be continually vigilant in terms of laboratory procedures.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब इसका समय समाप्त हो गया है, साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरु होगा। नैक्स्ट टाइम जब यह आयेगा, तब आप इस पर बोलेंगे।

डॉ. रामचन्द्र डोम : ठीक है सर।

15.30 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED

(i) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2009*
(Amendment of section 11, etc.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Private Members' Business. Item No. 19, Shri Francisco Sardinha.

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960."

The motion was adopted.

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India in Extraordinary Part-II, Section-2 dated 03.07.09

15.31 hrs.

(ii) UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2009*

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous central Authority to ensure rapid, accelerated and overall development of poor, underdeveloped and backward areas and regions of the country which lag behind in matters of development of infrastructure in economic, social, educational, technical and industrial fields and assure their speedy development in a planned manner and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous central Authority to ensure rapid, accelerated and overall development of poor, underdeveloped and backward areas and regions of the country which lag behind in matters of development of infrastructure in economic, social, educational, technical and industrial fields and assure their speedy development in a planned manner and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I introduce* the Bill.

---

* Published in the Gazette of India in Extraordinary Part-II, Section-2 dated 03.07.09
* *Introduced with the recommendations of the President

15.32 hrs.

(iii) PERSONS AFFECTED BY NAXALITE TERRORISM (RELIEF AND REHABILITATION) BILL, 2009*

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for relief, compensation and rehabilitation measures through employment and other means for the persons affected by naxalites or maoist terrorism in various parts of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for relief, compensation and rehabilitation measures through employment and other means for the persons affected by naxalites or maoist terrorism in various parts of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India in Extraordinary Part-II, Section-2 dated 03.07.09

15.33 hrs.

(iv) CITIZENS AFFECTED BY CYCLONE, SUPER CYCLONE OR TSUNAMI IN COASTAL AREAS (COMPENSATION, REHABILITATION AND WELFARE) BILL, 2009*

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of citizens living in coastal areas affected by cyclone or super cyclone or tsunami or any other natural calamity in the coastal areas of the country by providing adequate compensation, rehabilitation and welfare measures and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of citizens living in coastal areas affected by cyclone or super cyclone or tsunami or any other natural calamity in the coastal areas of the country by providing adequate compensation, rehabilitation and welfare measures and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2 dated 03.07.09

15.33½ hrs.

(v) PREVENTION OF UNSOLICITED TELEPHONIC CALLS AND PROTECTION OF PRIVACY BILL, 2009*

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit unsolicited telephone calls by business promoters or individuals to persons not desirous of receiving such calls and for the protection of individual privacy of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit unsolicited telephone calls by business promoters or individuals to persons not desirous of receiving such calls and for the protection of individual privacy of citizens and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

15.34 hrs.

(vi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009* (Amendment of the Eighth Schedule)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No. 25. Shri Yogi Adityanath – Not present.

---

* Published in theGazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2, dated 03.07.09

15.35 hrs.

RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF NATIONAL BOARD FOR THE DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Shri Virender Kashyap to move his Private Members' Resolution regarding Constitution of National Board for the Development of Himalayan States, time for Discussion of this Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for its discussion!

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं **:**

> "हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जिसके कारण भू-स्खलन, बादल फटना, भूकंप, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल का भारी नुकसान होता है और साथ ही उत्तुंग पहाड़ियों के कारण वहां सड़कों, भवनों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण की उच्च लागत और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह संघ सरकार की पूरी वित्तीय सहायता से-
> (1) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के चहुंमुखी और तीव्र विकास के लिए;
> (2) इन राज्यों में विद्यमान केन्द्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग के लिए; और
> (3) उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय सुझाने के लिए
> 'राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड' का गठन किया जाए।"

15.36 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय महत्व के इस ज्वलंत विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार इस माननीय सदन का सदस्य बनकर आया हूं।

महोदय, देश में कुल ग्यारह हिमालयी राज्य हैं जिनमें असम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम हैं। इन राज्यों की कुल आबादी छह करोड़ पैंतीस लाख से ज्यादा है तथा कुल क्षेत्रफल लगभग पांच लाख तिरानवें हजार किलोमीटर है। मैदानी भागों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य विकास कार्यों पर जितना व्यय होता है उसका कई गुणा ज्यादा व्यय पहाड़ी राज्यों में होता है। उदाहरणस्वरूप एक किलोमीटर मैदानी भाग

में सड़क बनाने में जो लागत आती है, पहाड़ी राज्यों के कई कठिन स्थानों पर यह लागत कई गुणा अधिक आती है। मैं समझता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहां की हमारी उत्तुंग श्रृंखलाओं में जो लोग फंसे हैं और हिमाचल प्रदेश के हिमालयी अंचल में बसे होने के कारण वहां कुछ भाग ऐसे हैं जहां वर्ष में केवल चार महीने ही सामान्य जीवन चलता है और शेष समय में बर्फ जमी रहती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां गर्मियों में ऊना एवं उसके साथ लगते क्षेत्रों में भयंकर गर्मी और लू की तपिश महसूस की जा सकती है और वहीं दूसरी ओर हिमाचल के ही जिला लाहौल-स्फीति और किनौर के कुछ भागों में भयंकर बर्फबारी के कारण सर्दी की ठिठुरन महसूस की जा सकती है। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थिति में अपना गुजारा करते हैं क्योंकि हम लोग जंगलों से घिरे हुए हैं। देश की 62 वर्ष की आजादी में पहाड़ी राज्यों के लिए जितनी भी योजनाएं बनीं उनका फायदा पहाड़ी राज्यों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस कारण से इन राज्यों के लोग विकास के लिए अभी भी तरस रहे हैं।   इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र सरकार जो भी योजनाएँ बनाती है, वह वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, सोशियो-इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाती। भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा में दक्षिण से समुद्र और उत्तरी संभाग में हिमालय को देश की सुरक्षा का प्राचीर कहा जाता है। केन्द्र सरकार ने दक्षिण और तटवर्ती राज्यों में अरब सागर और हिन्द महासागर से टकराते राज्यों में एक महासागर मंत्रालय बनाने की मांग की जिसकी देख-रेख में इन तटीय राज्यों की समस्याओं को इस मंत्रालय के माध्यम से सुलझाया जा सके। केन्द्र में महासागर मंत्रालय बन जाने के पश्चात् देश के तटवर्ती राज्य अनेक लाभ उठा रहे हैं लेकिन लोक सभा में देश के उत्तरी संभाग के हिमालय राज्यों के सदस्यों की कम संख्या और आपस में तालमेल न होने के कारण केन्द्र में महासागर मंत्रालय की तरह हिमालय विकास मंत्रालय स्थापित नहीं हो सका। आज हिमालय पूरे देश के ऋतु-चक्र के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए केन्द्र को हिमालय राज्यों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हिमालय विकास मंत्रालय या हिमालय विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज तक जो भी हमारे प्रधान मंत्री बने, उन्होंने हमेशा ही इस तरह की एजेन्सीज़ की वकालत की है और गत दिनों जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधान मंत्री थे और वे हिमाचल प्रदेश आए थे, तो उन्होंने भी इस प्रकार की एजेन्सी बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। मैं सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के ट्रांस हिमालयन विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करने के लिए बहुत सी इंटर मिनिस्ट्री टास्क फोर्स की बात भी 2004 में हुई थी परंतु उसकी कोई बैठक नहीं हो सकी और जिस कारण से हमें इस प्रकार के बोर्ड के गठन का लाभ नहीं हुआ या जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसका लाभ नहीं मिल सका।

महोदय, हिमालय क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए पूर्व में विभिन्न स्तरों पर केन्द्र सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। इन राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रधान मंत्री की देखरेख में महासागर विकास की तरह हिमालय विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाए जिससे हिमालय के पर्यावरणीय संरक्षण और उसमें स्थित हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के साथ साथ क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुल सकें। महोदय, इन हिमालयी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में भूटान, चीन, नेपाल, बंग्लादेश और म्यांमार से लगती है जिसके कारण भारतीय गणतंत्र की सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से इन हिमालयी राज्यों का विशेष सामरिक और आर्थिक महत्व हो जाता है। एक ओर जहां पाकिस्तान, बंग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ और आतंकवाद का सदैव खतरा बना रहता है, वहीं नेपाल से माओवादियों का खतरा रहता है और चीन की नज़र सदैव सिक्किम पर रहती है। भारत के इन्हीं हिमालय क्षेत्र से होकर चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि नदियाँ बहती हैं जो क्रमशः पश्चिम दिशा में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मानसून में इन नदियों में आने वाली भीषण बाढ़ से अपार वन संपदा की हानि के अलावा भूस्खलन, बादल फटने और दैवीय आपदाओं से अपार जान-माल की हानि होती है जिससे प्रति वर्ष केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों को बाढ़ राहत कार्यों एवं बाढ़ नियंत्रण पर अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी हिमालयी राज्यों की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना लगभग एक समान है और यह इतनी विकट है कि समग्र दृष्टि से इसके आर्थिक विकास और विकास प्रबंधन की ओर ध्यान दिये जाने की प्रबल आवश्यकता है। इसी के अनुरूप केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण और विकास विभाग का गठन आवश्यक हो गया है, जिससे केन्द्रीय स्तर पर हिमालय संरक्षण व विकास की नीति बन सके। इस नीति में हिमालय की पर्यावरण संरक्षण प्रणाली, भू-पारिस्थितिकी और मानव संसाधन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं विकास की नई वैज्ञानिक सोच रेखांकित की जानी चाहिए और जिसका हिमालयी क्षेत्र के उपरोक्त सभी राज्य अनुसरण करें। ये राज्य आर्थिक रूप से अक्षम, केन्द्रीय सहायता पर निर्भर होने के कारण अपना युक्तियुक्त विकास नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, एन.डी.ए. की सरकार के समय जो ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान व केन्द्र की ओर से अन्य योजनाएं बनीं उनके माध्यम से देश के मैदानी भागों में विकास देखने को मिला, लेकिन इन योजनाओं का यदि हम विश्लेषण करें, तो पहाड़ी राज्यों को मात्रात्मक रूप में जितना धन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला और उसके अनुसार पहाड़ी राज्यों का विकास भी कम हुआ। यू.पी.ए. सरकार के समय में तो इन योजनाओं की गति अत्यन्त धीमी हो गई है।

महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर जो भी योजनाएं बनती हैं, वे हिमालयी राज्यों की विकट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बननी चाहिए। उदाहरण के तौर पर केन्द्र की इन्दिरा आवास योजना में एक कमरा बनाने के लिए 28500 रूपया दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, वहां सड़कें भी नहीं हैं, जिससे हेडलोड पड़ता है। इससे इस छोटी सी राशि से एक कमरे का चौथाई काम भी नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार की जो भी केन्द्रीय योजनाएं बनें, वे वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बननी चाहिए और उसी प्रकार से वहां के लिए धन आवांटित होना चाहिए।

महोदय, भारतीय उप महाद्वीप की एक अद्वितीय भौगोलिक विविधता है। एक तरफ हमारे पास अंतः ज्वालामुखी पठार सहित एक लम्बी उपजाऊ तट रेखा है और दूसरी ओर ऊंचे और शक्तिशाली हिमालय की सीमा वाले विस्तृत कच्छ के मैदान हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वयं की जातीय जैव विविधता और अद्‌भुत जन सांख्यिकी से समृद्ध हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, ताकत, समस्याएं, आकांक्षाएं हैं और स्वयं ही उनके समाधान की अद्‌भुत प्रवृत्ति है। प्रत्येक क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोई सीधा समाधान नहीं है। तथापि इन सभी जैव-विविधताओं में एक सामान्य डिनोमीनेटर है, जो इनमें से कुछ क्षेत्रों को एक अद्वितीय सब-सैट में बांधता है। ऐसे प्रत्येक सब-सैट की अपनी अद्वितीयता परिभाषित है और एक सामान्य सूत्र से जुड़े हुए हैं।

हालांकि सभी तटीय प्रदेश एक समान नहीं हैं, बल्कि वे स्पट रूप से भिन्न हैं। जैसे कच्छ के मैदान या हिमालयी प्रदेश। ऊपरी तौर पर कुछ सामान्य पहलू हो सकते हैं, लेकिन वह समानता ठीक उसी तरह से है जैसे चाक और पनीर। विस्तार से कहा जाए, तो भिन्नता गणनात्मक हो सकती है और वह क्षेत्र विशेष के विशिष्ट मुद्दों के पूरे गैमट (Gamut) को सम्मिलित कर सकती है। भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में जहां यह कहा जाता है कि **"कोस-कोस पै बदले पानी, नौ कोस पै बानी"** और यह सब तब और अधिक जटिल और दुरूह हो जाता है जब न केवल योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए जाते हैं बल्कि वास्तव में जब उन्हें हकीकत में लागू करने की बात की जाती है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अलग-अलग जरूरतें होती हैं। लोगों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। समस्याएं अनन्य हैं और सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है। अतः जब हम उत्थान एवं विकास के लिए प्रगतिशील उपायों की बात करते हैं तब हम वास्तव में विभिन्न आवश्यकताओं के बीच अद्वितीय तालमेल बनाने के लिए एक मुख्य (मूल) समाधान चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसे लागू करने में इतनी ज्यादा बाधाएं आती हैं कि अंतिम परिणाम हमारी साधारण

अपेक्षाओं से बहुत दूर होता है। तब इसका समाधान क्या है? क्या हर स्थिति का एक अलग समाधान है? क्या यह एक गोल छिद्र में चौकोर खूंटी फंसाने का प्रयास करना है अथवा क्या सब मामलों का अलग-अलग अध्ययन होना चाहिए?

महोदय, विशेषकर पहाड़ी राज्यों की अपनी कई अनोखी विशिष्टताएं होती हैं और मुद्दों को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि संतोषजनक से असाधारण अंतिम परिणाम प्राप्त हो सकें। हमें अपनी दूसरी अन्य दूसरी सीमाओं को भी समझना होगा। ज़मीनी सच्चाई को जांचने के लिए और सबसे अधिक संसाधनों की कमी है, जिसकी प्रत्येक क्षेत्र विशेष से, मुद्दों से हमें गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। सभी की जरूरतों को एकसाथ लेकर ही इनसे पार पाया जा सकता है। जैसे कि कहावत है - "The birds of same feather flock together". हमें अपने सभी प्रदेशों को कुछ समान समानताओं को श्रेणीगत करने की जरूरत है - चाहे वे भौगोलिक हों या जनसांख्यिकीय। समूह में उड़ने वाले पक्षियों में विवेक होता है, क्योंकि समूह में उड़ते हुए उनकी एक मंजिल, इच्छा, आवश्यकता और यहां तक कि स्वप्न भी एक जैसे होते हैं।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद् की 50वीं बैठक में हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के शब्दों में अगर हम कहें तो पता चलता है कि आज इसकी बहुत आवश्यकता है कि पहाड़ी राज्यों के लिए इस प्रकार का बोर्ड गठित करना आवश्यक है, क्योंकि इन पहाड़ी राज्यों के विकास में मैं समझता हूं कि आज जितना धन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। उन्होंने 21 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की 50वीं बैठक में जो कहा, उसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं - "विकेन्द्रीकरण और निष्पक्षता विशेष रूप से विशिष्ट राज्यों की श्रेणी के संदर्भ में सामान्यत: हमारे देश की योजना प्रक्रिया अत्यधिक गहरी है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की पूरी संकल्पना वर्टीकल के साथ-साथ क्षितिज के सिद्धान्त पर आधारित है। इस परिकल्पना के विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि किसी राज्य को विशिष्ट श्रेणी के राज्य के आधार पर स्वीकृति मिलना उसके अपने अन्तर्निष्ठ विकासात्मक प्रतिकूल परिस्थिति और उत्पादन क्षमता के पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है।" यह 2002 की बात थी और आज 2009 में भी हम इस पर सोच रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं जरूरत इस बात की समझता हूं कि पहाड़ी राज्यों में विकास के लिए हमें केन्द्र से जितना धन उपलब्ध होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। वहां कानून बने हैं। खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फोरेस्ट्स हैं। मैं समझता हूं कि उन राज्यों में मिनरल्स भी हैं। वहां या तो पानी है या जंगल हैं।

सभापति महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की वन सम्पदा है। मैं सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि इन पहाड़ी राज्यों में चारों तरफ वन थे और हम उन पर डिपेंड करते थे। वे वन के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाते थे, परन्तु जब से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, उसके बाद से आज वहां पर एक भी पत्ता, एक भी लकड़ी की टहनी काटने नहीं दी जाती है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर इतने सारे वन हैं, उनकी वजह से मैं समझता हूं कि आज वे हमारे देश के लंग्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उन पेड़ों को काटने पर पूरा प्रतिबंध है। मैं हिमाचल प्रदेश की ही बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब से यह कानून लागू हुआ है, वहां जितने भी विकास के कार्य हैं, वे सब रुक गए थे, क्योंकि वहां चारों तरफ जंगल हैं और जब जंगल हैं तो उसमें से सड़कें नहीं बन सकती हैं। अगर हमें स्कूल, होस्पिटल, सीएफसी, पीएफसी बनानी है या वहां से आईपीएच की स्कीम से नाली बनानी है तो उसके लिए भी हमें परमीशन लेनी पड़ती है। कहने का मकसद यह है कि आज इन जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी पहाड़ी इलाकों के जितने भी राज्य हैं, उन्होंने उस पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगाया है और हिमाचल प्रदेश में टी.डी. राइट्स होते थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्हें पेड़ काटने और घर बनाने की जब जरूरत होती थी तो उन्हें जंगलों से पेड़ मिला करते थे। उस पर भी पूरी तरह से बैन लग गया है। स्थिति यह थी है कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो वह जंगल से लकड़ी काट कर अंत्येष्टि किया करते थे। आज हमारे पहाड़ी इलाकों में यह स्थिति आ गई है कि वहां हम सूखी लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक जो बहुत ही उल्टा असर पड़ा है वह यह है कि अभी पिछले दिनों लगभग आठ महीनों से बर्सातें नहीं हुईं। इसके कारण पहाड़ों में सूखा पड़ा हुआ है। वहां जो पत्ते गिरते हैं, खासकर जो चील (चीड़) के जंगल हैं, उनमें चील के पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं, वे एक प्रकार से दारू का काम करते हैं और जब उनमें आग लगती है, तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वे उस आग को बुझाने के लिए नहीं आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जंगलों के साथ वहां के लोगों की अटैचमेंट नहीं है। पहले वे फॉरैस्ट को प्रोटैक्ट करते थे, परन्तु जब से उनकी इस प्रकार की दुर्दशा कर दी गई है कि उनके किसी प्रिय की मौत होने के बाद भी उसकी अन्त्येष्टि के लिए उन्हें वहां से लकड़ी नहीं लेने दी जाती है। तब से उनके मन में यह भावना आ गई है कि हम इन जंगलों को बचाकर क्या करेंगे। इस प्रकार के स्टिंजेंट एक्ट और ऐसे कठोर अधिनियम बनाकर वहां के लोगों को उनकी जरूरत का सामान भी जंगलों से नहीं लिए जाने दिया जा रहा है। इसलिए उनका जंगलों के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा है।

महोदय, यह ठीक है कि जंगलों को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिनियम बनने चाहिए और इस अधिनियम के बनने के बाद जंगल बच रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि जंगल बचने चाहिए और देश के

वातावरण का संरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसके साथ-साथ मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हिमाचल प्रदेश के जंगलों में है, परन्तु उसके काटे जाने पर अब कम्पलीट और ब्लैंकेट बैन है, इसलिए वे काटे नहीं जा सकते हैं और हमारे पहाड़ी राज्यों की जो अलग-अलग सरकारें हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से इस बात को माना है कि फॉरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के अनुसार ही काम किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों ने सबसे पहले देश को मान्यता दी है। देश के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ज्यादा सोच रखी है। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि जो हमारे वन थे, जो हमारी आय के साधन थे, उनकी एवज में, उसे कंपैनसेट करने के लिए इतनी धनराशि दी जाए, जिससे पहाड़ी राज्य अपने विकास को सुचारू रूप से कर सकें। जो अन्य राज्य हैं, वहां अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के अयस्क (ओर) पाए जाते हैं, चाहे वे लोहे के हैं या तेल के, उनके एवज में कुछ प्रदेशों को रॉयल्टी दी जाती है। हम समझते हैं कि इन पहाड़ी राज्यों के जो जंगल हैं या जो पानी है, वे हमारे एक प्रकार से मिनरल ही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें उनकी एवज में केन्द्र सरकार की ओर से रॉयल्टी दी जानी चाहिए, ताकि हम अपना समग्र, संतुलित एवं ठीक प्रकार से विकास कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम ग्लोबल वॉर्मिंग की बड़ी बात कर रहे हैं। इस ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से जो हमारा ऋतु चक्र था, वह पूरी तरह से असफल और विफल हो गया है। समय पर बारिशें नहीं होती हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि आज इन हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पैकेज मिलना चाहिए, ताकि फॉरैस्ट कवर ज्यादा से ज्यादा हो सके। उसे हम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें।

महोदय, एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। उसे पढ़कर मुझे हिमालयी राज्यों की बहुत भयानक तस्वीर नजर आई। वह रिपोर्ट है "Himalayan Misconceptions and Distortions: What are the facts?" इस रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के संबंध में उन्होंने जो कहा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यह 21 जुलाई, 2003 को लंदन से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि-

> "On a related theme *The Times* of London (21 July 2003), reporting on an international meeting held at the University of Birmingham, noted that 'Himalayan glaciers could vanish within 40 years because of global warming…500 million people in countries like India could also be at increased risk of drought and starvation.' Syed Hasnain is

quoted as affirming that ‘the glaciers of the region (Central Indian Himalaya) could be gone by 2035’.

According to Barry (1992: 45) the average temperature decrease with height (environmental lapse rate) is about 6 degree C/km in the free atmosphere. The dry adiabatic lapse rate (DALR) is 9.8 degree C/km. If it is assumed that the equilibrium line altitude (comparable with the ‘snow line’) in the Central Himalaya is about 5,000 masl and it will need to rise above 7,000 metres if all the glaciers are to be eliminated, then the mean temperature increase needed to effect this change would be about 12-18 degree C.”

16.00 hrs.

"…Given the degree of global warming, summers in Kolkata would be a little uncomfortable."

इस प्रकार की जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, मैं यह समझता हूं कि सीधे-सीधे तौर से हमें आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लिए केन्द्र की तरफ से इस प्रकार की योजनाएं बनें, स्पेशल पैकेजेज़ उनको मिलें, तभी यह सब कुछ हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा वाटर लेविल बहुत नीचे चला गया है और वैज्ञानिकों की राय मैं कहना चाहता हूं कि शोध के मुताबिक जो उन्होंने कहा, दुनिया भर में उनकी जो आम राय थी, उनका कहने का मतलब यह है कि 31 प्रतिशत धरती में अगर पानी खड़ा रहे। वह पानी रीचार्ज के लिए धरती के अन्दर जाना चाहिए, तभी हिमनद वाली नदियों और जल स्रोतों से लगातार पानी हमें मिल सकता है।

16.01 hrs.

(Dr. Giraja Vyas *in the Chair*)

आज हम देख रहे हैं, खासकर इन हिमालयी राज्यों में कि हमारे जितने जल स्रोत थे, बावड़ियां थीं और जितने दूसरे चश्मे थे, वे पूरी तरह से सूख गये हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ी जल स्रोत सूखे हो गये हैं। इसका सीधा-सीधा सा कारण एक है कि आज हमारे यहां बहुत सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी हमारा स्पेस ढक गया है और उसमें पानी नहीं रिसता है। लगभग 13 प्रतिशत पानी आज धरती के अन्दर रिस रहा है, जबकि 31 प्रतिशत पानी रिसना चाहिए। इसलिए भी मैं समझता हूं कि आज जितने ज्यादा वन हम लगा सकेंगे, उनकी उतनी ज्यादा आवश्यकता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कश्यप साहब, समय हो गया है। आपकी बहुत बात हो गई।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे पहाड़ी राज्यों के लोग हैं, वे ईको फ्रेंडली ज्यादा होते हैं और जंगलों को वे अपने बच्चों की तरह से पालते हैं, परन्तु जब कानून इस प्रकार के बन जाते हैं, जिससे उनको उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं हो पाता है, तब इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आती है। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ वर्ष पहले हमारे उत्तराखंड के लोगों ने उस वक्त उस तरफ एक बहुत बड़ा भारी चिपको आन्दोलन चलाया था, वह सीधे-सीधे वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। मैं समझता हूं कि आम आदमी भी वनों की रक्षा करना चाहता है। हमारे ऋषि-मुनि भय और हम लोग भी आज जंगलों में जो वृक्ष होते हैं, उनको पूजते हैं तो क्यों नहीं, जो आदमी और जंगल का रिश्ता है, पेड़ का

रिश्ता है, उसे हमें ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। उस रिलेशन को डैवलप करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं अगर बनेंगी तो मैं समझता हूं कि वे हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगी।

जैसा मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि उन जंगलों को बचाया जाये, परन्तु जैसा मैंने कहा कि आगें जब लगती हैं तो उससे हमारा फ्लोरा और फौना बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारे वनों में इस प्रकार के जो अच्छे-अच्छे पशु-पक्षी थे, वे भी खत्म होते जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी अगर आपके सामने रिपोर्ट पढ़ दूं तो आप अपने आप ही समझ जाएंगी कि किस प्रकार की हालत आज हो रही है।

वनों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप, अवैध शिकार, बदलते मौसम और इन दिनों जंगलों की आग ने वन्य जीवों को संकट में डाल दिया है। वन्य जन्तुओं पर हिमालय की नमी समाप्त होने का भी असर पड़ा है। उनमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयी भालू, निचली हिमालयी घाटियों में रहने वाले गुलदार तथा पक्षियों में डफिया, मोनाल तथा पहाड़ी बटेर आदि मुख्य हैं। इसके साथ ही हिमालयी क्षेत्र में तस्करों की नजर वन ओषधियों पर भी पड़ी है, जो 3000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगती हैं और जिनसे परम्परागत दवाएं बनाई जाती हैं।

हिमालय के मौसम के बिगड़ने की सबसे बड़ी मार हिम तेंदुए पर पड़ी है। वन विभाग की सूचना के अनुसार 1984-85 में गढ़वाल व कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र में हिम बाघों की संख्या छह थी। इसके बाद हिम बाघ दिखना बन्द हो गये। 3600 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला मूल रूप से एशियाई प्रजाति का यह बाघ दो फुट लम्बा व 50 किलो वजन तक का होता है। भेड़, बकरी, भालू, थार, कस्तूरी व खरगोश इसका भोजन हैं। यूरोपीय क्षेत्र में हिमबाघ की खाल से बनने वाले फर के कोटों की कीमत करीब 20 लाख रूपए है। वहां जो वन्य प्राणी हैं, आज जंगल कम होने की वजह से या आग वगैरह लग जाने की वजह से उनकी खराब स्थिति हो रही है। हमारा वन्य प्राणी वहां समाप्त होता जा रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से आज मुझे पहली बार यहां बोलने का अवसर मिला, क्योंकि मैं पहली बार इस संसद का ही नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनकर आपके बीच आया हूं। आपने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया और सभी सीनियर सांसदों ने मेरी बात को सुना। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, पर जो मेरा इंटरनल मकसद है, वह शायद आप तक पहुंच गया होगा। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि जो मैंने प्रस्ताव आज मूव किया है, यह सब कुछ करने के लिए एक राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड गठित होना चाहिए। आज से कई वर्ष पहले, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, जिनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था, उसके बाद डा. वाई. एस. परमार, जो हिमाचल प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश

के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार धूमल जी, वह भी काफी चिंता कर रहे हैं। मैंने शुरूआत में भी उनके संदर्भ में कहा है। आज वे चाहे कार्बन क्रेडिट की बात कह रहे हों, पर्यावरण संरक्षण की बात कह रहे हों, हर जगह उन बातों को उठा रहे हैं।

महोदय, जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक हिमाचल प्रदेश में गए या पहाड़ी राज्यों में गए और जब-जब वहां पर मांग उठी, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह होना। परंतु वह क्यों नहीं हुआ? यह आज हाउस को जानना है कि जो इस प्रकार के पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं। वैसे पहाड़ी राज्यों के लिए जो नार्थ-ईस्ट का हमारा एरिया है, उसके लिए योजनाएं बनी हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं। आज रेलवे बजट पेश हुआ। रेल बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कश्यप जी, हम चाहते हैं कि सुषमा जी का भी संकल्प आ जाए। अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अंत में पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: Resolution moved:

" Having regard to the gergraphical conditions of Himalayan region, which cause landslides, cloudbursts, earthquakes, hailstorms and other natural calamitites resulting in huge loss of lives and property and also taking into consideration the high cost of construction of roads, buildings and other development works due to mountainous terrain and the socio-economic backwardness of the region, this House urges upon the Government to constitute a Board to be known as the 'National Board for the Development of Himalayan States' with full financial assistance of the Union Government for –

(i) alround and speedy development of the States comprising the Himalayan region;

(ii) monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States; and

(iii) suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region."

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : महोदया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का सुअवसर दिया। प्राइवेट मेंबर बिल, जिसे श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे तीन उत्तरी हिमालयन राज्य जिनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, उनके द्रुत विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन होना आवश्यक है, इसका मैं समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से हमारे नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके लिए जो डेवलपमेंट बोर्ड है, उसकी तर्ज पर इस बोर्ड का गठन हो। इस राष्ट्रीय बोर्ड में, संसद सदस्य इसके मेंबर हों। इसके जो सभापति हों, वह राज्य के मुख्यमंत्री क्रमवार हों। इसके साथ-साथ बोर्ड का जो संविधान है, वह क्या करेगा और किस प्रकार से कार्य करेगा, रिकमंडेशन करेगा, उन रिकमंडेशंस को केंद्र सरकार लागू करेगी। इस बोर्ड के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। मैं यह चाहूंगा कि हमारे हिमालयन राज्यों के अंदर विकास की गति धीमी हो गयी है क्योंकि वन संरक्षण अधिनयम हमारे विकास में बाधक बन गया है। इसका सरलीकरण होना चाहिए, जिससे हमारी सड़कें बन सकें, हिमालयन राज्यों के अंदर हैलीपैड बन सकें ताकि पर्यटक वहां पर पहुंच सकें। जो सुदूर के क्षेत्र हैं, जो चिकित्सा सुविधाओं से अछूते रह जाते हैं, वहां हैलीपैड की सर्विस होने से लोग चिकित्सा की सुविधा ले पाएंगे, ऐसा तब संभव हो सकेगा। ये सभी चीजें तभी संभव होंगी, जब वन संरक्षण अधिनियम का सरलीकरण होगा और हमारे यहां तेजी से सड़कें बनेंगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यहां भूकंप आते रहते हैं। महाकवि कालिदास जी ने कहा था कि हिमालय पृथ्वी का मेरूदण्ड है। आज हम देखते हैं कि यहां पर जो टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं, वे आपस में टकरा रही हैं और जो एशियन कांटीनेंटल शिफ्ट हो रहा है, उससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर समय-समय पर यहां भूकंप आते रहते है। यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, सीस्मिक जोन है। अतः हमें यहां देखना होगा कि यहां का जो भावी कंस्ट्रक्शन हो, भविष्य में जो लोग यहां मकान का निर्माण करें, उसमें स्टील का उपयोग करें। वहां आरसीसी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि भूकम्प आने पर लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके। अगर वहां रेल का विस्तार होगा, जैसे हम चाह रहे थे कि ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग और टनकपुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का विस्तार होता है तो उससे सरिया, सीमेंट, लोहा और ईंटें बड़ी सस्ती मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का तेजी से विकास हो, तो उसके लिए रेल का विस्तार होना बहुत आवश्यक है। रेल के विस्तार के लिए इसे नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में ट्रीट किया जाए जैसे पहले जम्मू कश्मीर में रेल लाइन नहीं थी तो रेल का विस्तार किया गया, बारामूला तक रेल लाइन बनाई गई और उसका सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया गया। जम्मू से रेल का विस्तार किया गया और

बारामूला से भी रेल का विस्तार किया गया और दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया गया। हिमालयन क्षेत्रों का विकास तभी होगा जब वहां रेल का विस्तार होगा। उसके लिए अगर हम रेल के प्रोजैक्ट्स को नेशनल प्रोजैक्ट्स के रूप में लेकर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा और बड़ी तेजी से विकास होगा।

मैं यह भी बताना चाहूंगा क्योंकि वहां टैक्टॉनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, हमारे पहाड़ों में पानी के स्रोत सूख गए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सारे स्रोत सूख गए हैं और वहां पेयजल की बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। आज लोग अपना जो जीवन-यापन कर रहे हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां एक व्यक्ति केवल पानी लाने में ही लगा रहता है, उसका काम अपने परिवार के लिए पानी लाने का होता है। ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि यदि वहां की पेयजल की समस्या को सुधारा नहीं जाएगा तो लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति के निपटारे के लिए हमें वृहद योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम सुदूर गांवों में लोगों को पानी उपलब्ध करवा सकें। वैसे गंगोत्री है और वहां से सारी नदियां निकल रही हैं, लेकिन आज पहाड़ों की स्थिति ऐसी बन गई है जैसे कबीर दास जी ने कहा था -- पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन-सुन आवे हासी। जो दुनिया को पानी पिलाता है, आज स्वयं पानी के लिए तरस रहा है। यही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की बन गई है। इसलिए वहां पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन होना बहुत आवश्यक है। मैं बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड में पानी की बड़ी विकट स्थिति बन गई है और वहां त्राहिमाम्-त्राहिमाम् मचा हुआ है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, बीरोंखाल ग्राम समूह पुनगर्ठन पम्पिंग पेयजल योजना तृतीय चरण का निर्माण होना आवश्यक है। उसमें बहुत सी पम्पिंग पेयजल योजनाएं हैं। भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग योजना, महादेव से बरसुण्ड देवता तक पूर्वी नयार नदी पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा-गुड़ियाना-सिन्दुड़ी पेयजल योजना, बडेरो ढैय्या (नागणी) पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना, को बीरोखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना बड़ेथ पेयजल योजना का क्रियान्वयन एवं गुराडमल्ला के लिए नई योजना तथा नानघाट पेयजल योजना आदि। इसी प्रकार चमोली जिले के अंदर गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना है। रूद्रप्रयाग जिले के अंदर पानी की बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है और वहां कुछ पेयजल योजनाओं का बनना बहुत आवश्यक है जो लम्बित पड़ी हुई हैं, जैसे तल्लानागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया-जवाड़ी (पश्चिमी भरदार) पेयजल योजना, तैला पेयजल योजना, पिल्लू-जंगही पेयजल योजना, अगस्त्यमुनि पेयजल योजना, बसुकेदार-डांगी-सोगना पेयजल योजना। इसी प्रकार टिहरी

जिले के अंदर भी पानी की विकट समस्या है। लक्षमोली-हडीम की धार पम्पिंग पेयजल योजना, मलेथा-कपरोली-अकरी-बारजुला पम्पिंग पेयजल योजना, पट्टी कड़ाकोट पश्चिम भाग एवं पट्टी मकरी बाराजुला हेतु कोटेश्वर-सिल्काखाल पेयजल पम्पिंग योजना, द्वितीय चरण पट्टी चौरस एवं कड़ाकोट पूर्वी भाग मेनेठ-सजवान कांडा पेयजल पम्पिंग योजना, देवप्रयाग नगर हेतु पेयजल पम्पिंग योजना, कोटेश्वर झण्डीधार तथा कोटेश्वर-पालकोट पेयजल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाएं, क्वीली-पालकोट पेयजल पम्पिंग योजना, सूरजकुण्ड-रानीताल पेयजल पम्पिंग योजना। नैनीताल के अंदर भी जो क्षेत्र पड़ता है वहां ढिकुली में क्रोबर हेंड टैंक का निर्माण एवं वितरण प्रणाली का पुनगर्ठन, भवानी खुल्म भवानीपुर , तड़ियाल मड़ियाल में 1 कि0मी0 लाइन कायन बांगाझाला पेयजल योजना। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी 19 अक्टूबर, 2006 में हरिद्वार पधारे थे, तो उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए पांच पम्पिंग योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धन अवमुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ये योजनाएं बन नहीं पाई हैं। इसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, मुण्डेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। जनपद टिहरी में घंटाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना और जनपद अल्मोड़ा में दोडम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना तथा सरयू वेलम ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और पूरा उत्तराखंड का पहाड़ आज पानी से प्यासा है।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर हमारे हिमालयन विकास के लिए इस विकास बोर्ड का गठन हो जिससे तेजी से विकास हो सके और लोगों को पानी उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने जीवन में यह विश्वास रखें कि भारत की भूमि के वे भी लाल हैं और इस देश के वे भी नागरिक हैं। उनको पानी उपलब्ध हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापति महोदया, बहुत लम्बे अर्से से राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। मेरे सहयोगी वीरेन्द्र कश्यप जी ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। आखिर आज राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड बनाने की बात क्यों की जा रही है? बहुत लम्बे समय से पहाड़ी राज्यों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो पर्वतीय राज्य होने के साथ-साथ हमारी दुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा हैं। अगर सड़क बनाने की बात की जाये, तो फॉरेस्ट एक्ट के कारण कोई भी छोटी सी सड़क बनाने के लिए हमें परमीशन लेने के लिए भी कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और जब सड़क निर्माण की बात आती है, तो जितना धन मैदानी इलाके में खर्च होता है, उससे कई गुना ज्यादा धन पहाड़ी राज्य की सड़कों पर खर्च होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र सरकारों का रवैया भी हिमालय क्षेत्रों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। जितना धन सड़कों, रेलमार्गों, हवाई पट्टियों के लिए मिलना चाहिए था, उतना कभी नहीं मिला। अगर सड़कों की बात की जाये, तो हिमाचल प्रदेश में बार-बार नैशनल हाईवेज मंजूर करवाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार से पर्याप्त धन नहीं मिला। वहीं पर आजादी के 62 वर्षों के बाद भी केवल 17 किलोमीटर की रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसमें भी इन पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नार्थ ईस्ट के इलाकों की हम बात करें, तो आज के रेल बजट में भी उनके हिस्से कुछ नहीं आया। इतने वर्षों से इन राज्यों की जो अनदेखी की जा रही है, तो क्या आज यह मांग बिल्कुल जायज नहीं है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये? क्या ये हमारे अधिकार नहीं हैं? क्या ये अधिकार हमें तभी मिलेंगे जब हम जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की तरह हथियार उठायेंगे। नार्थ ईस्ट में नेक्सलाइट की मूवमैट बढ़ी, टेरोरिज्म बढ़ा। अगर अपने अधिकारों को लेने के लिए हमारे नौजवानों को उस हद तक जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया जाये, जिससे पर्वतीय राज्यों को उनके अधिकार मिले। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो वहां डेढ़ लाख करोड़ रुपये की सम्पदा केवल वनों की है। हमने पेड़ काटने पर बैन लगा रखा है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। हम पानी के माध्यम से पनबिजली परियोजनाएं बनाते हैं ताकि बाकी राज्यों को बिजली दी जा सके। लेकिन बदले में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? बजट का गिना-चुना धन मुश्किल से हिमाचल प्रदेश जैसे बाकी पर्वतीय राज्यों को मिलता है।

अभी सतपाल महाराज जी ने कहा कि उनकी कई पानी की परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। पानी की परियोजनाओं के अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे रेलवे लाइन केवल 17 किलोमीटर है और

वह भी 62 वर्षों में है। क्या हमारा अधिकार नहीं कि हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी रेलवे लाइन पहुंचे?

क्या यह हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया सड़कें बनें, क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बनें, अच्छी फैशिलिटीज वहां दी जाएं? वहां पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे हम पीने के पानी की बात करें, अगर हमें पीने के पानी के लिए लाइन किसी गांव तक ले जानी हो तो उसे खड्डे में से ले जाना पड़ता है, किसी फॉरेस्ट के बीच से ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी परमीशन चाहिए। हमें हर काम के लिए, अगर फॉरेस्ट काटना है, वहां से कोई लाइन ले जानी हो तो उसके लिए परमीशन लेनी होती है। हमारी एक लाख करोड़ रूपए की वन सम्पदा हमारे किसी काम की नहीं है। आज ममता जी बार-बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कह रही थीं। हिमाचल प्रदेश भी अपनी वन सम्पदा में थोड़ी सी कम करके कई हजार करोड़ रूपए कमाकर अपने आधारभूत ढांचे को सुधार सकता है, लेकिन बाकी राज्यों को, मैदानी इलाकों को जो अच्छा पर्यावरण मिलता है, जो पानी की सुविधा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक हिमाचल प्रदेश से जाती है, जो बिजली हमारे राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों में जाती है, उसके बदले में हमें क्या मिलता है?

यदि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन की बात करें, बाकी प्रदेश हजारों करोड़ रूपए इंडस्ट्रीज के माध्यम से कमाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपने विकास के लिए भी केन्द्र सरकार के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है। आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। जब हम इंटरनेशल कांफ्रेंसेज में जाते हैं, तो हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि वहां जाकर बात करते हैं कि अमेरिका ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व कहा था कि वह अपनी कार्बन एमिशन्स को लगभग 20 प्रतिशत तक कम करेंगे, लेकिन इसके बजाय अमेरिका ने पिछले इतने वर्षों में इसको 17 प्रतिशत और बढ़ाया है। अगर हम अपने देश में देखें तो क्या बड़े राज्य कार्बन एमिशन को नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य उसको कम करने में नहीं लगे हैं? हमारी सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्री प्रेम कुमार धूमल जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के 16.5 लाख परिवारों को चार-चार सीएफएल बल्ब मुफ्त दिए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। एक छोटा सा प्रदेश 90 करोड़ रूपए खर्च करके पर्यावरण को बचाने में लगा है, हमारे लोग वन को काटकर अपने परिवार का पेट भरने की बजाय, प्रयास करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। हिमाचल प्रदेश के साथ ही अन्य पहाड़ी राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। मैं सभी की ओर से यहां पर मांग करना चाहूंगा कि हमारे हितों की अनदेखी न

की जाए वरना वह दिन दूर नहीं है जब वहां भी जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों जैसी बहुत बुरी स्थिति देखनी पड़े। उन राज्यों को आज हजारों करोड़ शायद इसलिए ज्यादा मिलते हैं कि वहां पर टेररिज्म है। हमारे युवाओं को लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में विकास तभी होगा अगर वहां पर हालात उन राज्यों जैसे होंगे। अगर जम्मू-कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खास तौर पर परियोजनाएं लाई गयीं, तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए ऐसी परियोजनाएं क्यों नहीं लाई गयीं? बाकी जो राज्य हैं, उनको भी एक साथ विकास मिलना चाहिए, इसलिए जब हम ट्रांस हिमालयन डेवलपमेंट अथारिटी की बात करते हैं, मैं उन सभी ग्यारह राज्यों की ओर से, हिमाचल प्रदेश की ओर से, मेरे सहयोगी श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन में उपस्थित मेरे सभी साथीगण इस प्रस्ताव को एकमत से पारित करेंगे और हम अपने जिन अधिकारों से लम्बे समय से वंचित हैं, हमें मिले। जिन पर्वतीय राज्यों से आपको अच्छी वायु, अच्छा पर्यावरण, पानी सब कुछ मिलता है, आप भी चाहेंगे कि आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें, तो इसमें हमें सभी राज्यों का सहयोग चाहिए। केवल एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी का इसमें सहयोग मिलेगा, पूरे सदन का सहयोग मिलेगा और आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश और बाकी राज्य अपनी ओर से पूरा सहयोग सभी क्षेत्रों में देते रहेंगे।

आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): माननीय सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्री कश्यप जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्र हित में कई ऐसे अवसर आते हैं, जब इस सदन में माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक आम राय बनाते हैं और हमने देखा है कि उस राय का केन्द्र सरकार ने भी सम्मान किया है। हमारी सम्मानित राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि नई सरकार का लक्ष्य और दृढ़ संकल्प है कि हम भारत के समस्त क्षेत्रों का समान रूप से विकास करेंगे, ताकि कहीं कोई असमानता न बढ़े। आज सदन में राष्ट्रीय हिमालयी विकास बोर्ड बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसकी बहुत आवश्यकता है। हम इस बात को गर्व से कहते हैं कि डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यों को काफी धन आबंटित किया और कई विशेष योजनाएं भी लागू कीं। इतना धन और इतनी योजनाएं पूर्व की सरकारों ने कभी आबंटित और लागू नहीं कीं। हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां भिन्न हैं और वहां की योजनाएं भी भिन्न हैं। जैसे पेयजल को ही ले लीजिए या प्राकृतिक आपदा को ले लीजिए। अगर मैदानी इलाके में बाढ़ आती है तो बाद में वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है, पानी रिसीट कर जाता है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पहाड़ों में अगर बाढ़ आती है तो जमीन कट जाती है। इसके अलावा जो मुआवजा दिया जाता है वह बहुत ही नोशनल होता है, नाममात्र का होता है। इसी तरह पेयजल को मामला है। सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन वहां के गांव के गांव पानी के अभाव से ग्रसित हैं। वहां लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए पम्पिंग योजनाएं चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के पास इतना धन नहीं है कि वह लिफ्ट करके पेयजल की समस्या का समाधान कर सकें।

14वीं लोक सभा में वर्ष 2008-2009 के आम बजट पर हो रही चर्चा के समय मैंने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था कि हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन करें। आज हमारे कई सदस्यों ने उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की है, ये सब बातें उस समय भी उटाई गई थीं। हमारे कई साथी आज भी यहां सदन में बैठे हैं, जो उस समय प्रधान मंत्री जी से मिले और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी मिले थे। मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि गम्भीरता से सरकार इस विषय पर निर्णय लेगी।

जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, इनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिली हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन आदि से हमारे इन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जहां भी असंतोष या आक्रोष होता है, वहां आतंकवाद के बीज पनपते हैं। हमारा हिमालयी क्षेत्र एक

बॉर्डर क्षेत्र है, अगर वहां पर आर्थिक पिछड़ापन बढ़ेगा तो लोगों में उदासीनता होगी। इसका फायदा हमारे पड़ौसी राज्य उठा सकते हैं, क्योंकि वे हमारे देश की एकता और अखण्डता को चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें इस बात का बल मिलेगा।

केन्द्र सरकार ने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट फंड बनाया है। जो अभी डेटा आया है, उसके अनुसार जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट का पैसा इन राज्यों को जा रहा है वह आधा भी खर्च नहीं हो रहा है । राज्यों को भी देखना है कि केन्द्र द्वारा दिए धन का उपयोग सीमांत जनपदों के विकास के लिए दिया गया वह क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है। मैं उत्तराखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 12 करोड़ रुपए उत्तराखंड को आबंटित किए गए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। इसलिए इसकी समीक्षा राज्य सरकारों के साथ करनी चाहिए । हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार पीसमील एफटर्स कर रही है।

नार्थ-ईस्ट के विकास के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। हम सब चाहते हैं कि नार्थ-ईस्ट का विकास हो। कश्मीर के लिए अलग से योजना है। अगर पूरे हिमालय राज्यों की पालिसी मेकिंग में कोआर्डिनेशन आना जरूरी है । पेयजल, पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हो सकता है। आज हमारे देश की जीडीपी में आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा आए। विदेशी मुद्रा लाने का एक बड़ा स्रोत पर्यटन बन सकता है। पर्यटन की पोटेंशियलिटी जितनी हिमालयी क्षेत्र में है, उतनी शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे यहां कई झीलें हैं, कई भोगियाल हैं, लेकिन इनके विकास के लिए राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। इसलिए पर्यटन की वहां जो अपार सम्भावना है, वह हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हिमालयी विकास प्राधिकरण बोर्ड जरूर बनना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी करें, क्योंकि कई राज्य इसमें आएंगे। योजना आयोग ने भी कई वर्ष पहले इस तरह का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था कि हिमालयी विकास प्राधिकरण का गठन करें। आने वाले समय में अगर यह प्राधिकरण बनता है तो निश्चित रूप से गांधी जी का जो सपना था कि घर-घर स्वराज पहुंचे, आजादी का, स्वतंत्रता का लाभ विकास के रूप में हर क्षेत्र में पहुंचे वह पर्वतीय राज्य में पहुंचेगा।

सम्माननीय सभापति जी, आज पर्वतीय राज्यों की औसत आय देश की औसत आय से बहुत कम है। इसे हमें होर्टिकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो-एनर्जी के जरिये से बढ़ाना चाहिए और इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमारी केन्द्र की सरकार ने विशेषकर उत्तराखंड और हिमालय-रीज़न के विकास के लिए विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है और विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज आने की वजह से आज उत्तराखंड में 30 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और हिमाचल को भी विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, लेकिन उस पैकेज की सीमा वर्ष 2010 में समाप्त होने वाली है। राज्य सरकारों ने

माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह और अनुरोध किया है कि यह जो विशेष औद्योगिक पैकेज है इसकी सीमा वर्ष 2013 तक बढ़ाई जाए, जैसा कि पहले से तय था। केन्द्र सरकार एक-दो राज्यों का ध्यान दे रही है लेकिन समान रूप से सारे राज्यों का ध्यान हो ताकि असमानता न रहे। सब मिलकर जब निर्णय लेंगे तभी विकास होगा। हिमालय का जो महत्व है वह पर्यावरण की वजह से भी है और हमारा सारा विकास वहां से जुड़ा हुआ है, सारी नदियां वहां से आ रही हैं।

फ्लड कंट्रोल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपने माइनिंग पर फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के तहत रिस्ट्रक्शन लगाई हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों से जब बड़े-बड़े पत्थर टूटकर आते हैं तो उससे रिवर का बैड बढ़ रहा है। जब रिवर का बैड बढ़ रहा है तो उसका पानी फ्लड के रूप में आस-पास के गांव और मैदानी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आपको सिलेक्टिव माइनिंग को नदियों में एलाऊ करना पड़ेगा। कई ऐसे नियम हैं जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र की प्लानिंग बिल्कुल भिन्न है।

हमारी जो कनैक्टिविटी है, वह बहुत खराब है। चाहे एयर-फील्ड्स हों, रोड्स हों, इन सब के लिए धन चाहिए और राज्य सरकारों के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है। अगर आप प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप में रास्ते खोलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास का रास्ता साफ हो सकता है। इस क्षेत्र का को-आर्डिनेटिव डैवलेपमेंट इसी बोर्ड के जरिये संभव हो पाएगा। मुझे आशा है कि इस सदन में जो चर्चा हो रही है सरकार इसे गंभीरता से लेगी और इस राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड का अवश्य गठन करेगी।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो राष्ट्रीय-स्तर के नेता हुए हैं इनकी चर्चा माननीय कश्यप जी ने भी की है। हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वे भारत सरकार के प्लानिंग और वित्त विभाग में मंत्री रहे हुए हैं, उनका भी ऐसा मत है। हिमाचल के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय परमार जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, असम के मुख्य मंत्री सबका ऐसा ही मत बना है, इसलिए इस पर कोई विवाद भी नहीं होगा। सब मिलकर इस बोर्ड का गठन करें और विशेष योजनाएं दें। डा. मनमोहन सिंह जी तथा माननीया सोनिया जी का जो एक सपना है कि भारत का हर क्षेत्र में विकास हो, वह सपना पूरा होगा। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि चुनाव का पर्व समाप्त हो चुका है और अब विकास का पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे समय में आदरणीय श्री वीरेन्द्र कश्यप जी जो प्रस्ताव लाए हैं निश्चित तौर पर यह पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आज इस प्रस्ताव के द्वारा हम राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों के साथ जो निरंतर अन्याय हो रहे हैं और अंदर ही अंदर एक आग सी सुलग रही है। जैसे हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि यह वक्त सभी के संभलने का है। कहीं ऐसा न हो कि अंदर ही अंदर जो एक ज्वाला धधक रही है, कल एक बड़े विस्फोट का रूप धारण न कर ले।

महोदया, इंसान के जीवनयापन के लिए सबसे जरूरी प्राण वायु है, उसके बाद जल जरूरी है और उसके बाद भोजन जरूरी है। जीवन में जब व्यक्ति बीमार होता है, तो उसके लिए औषधि भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि हिमालय सारी सृष्टि को ये सभी चीजें देता है। हिमालय न हो, तो शुद्ध प्राण वायु प्राप्त नहीं हो सकती है। शुद्ध प्राण वायु का आधार ही हिमालय के जंगल हैं, हिमालय के पहाड़ हैं। अगर हिमालय नहीं होगा, तो वहां बर्फ नहीं होगी, बर्फ नहीं होगी, तो वहां जल भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। जैसा हमारे अन्य साथियों ने कहा कि जल का उदगम स्थल ही हिमालय है चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सतलुज हो या अन्य बड़ी-बड़ी नदियां हों, सारी हिमालय से पैदा हो रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हिमालय सारे राष्ट्र को, सारे विश्व को बहुत कुछ दे रहा है, उस हिमालय की अनदेखी कई वर्षों से निरंतर हो रही है।

सतलुज नदी के पानी के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य में लड़ाई होती है, दूसरे राज्यों में भी नदियों के जल के लिए लड़ाई होती है। मैं सोचता हूं कि जो हिमालय इन सारी नदियों का असली मालिक है, वह शांत हो कर सारी स्थिति को देख रहा है, लेकिन वह कब तक देखेगा? हमारे भाई अनुराग ठाकुर, वीरेन्द्र कश्यप, सतपाल महाराज और बहुगुणा जी ने निश्चित तौर पर कहा है कि हम हिमालय के लोग, हम पहाड़ के लोग आबादी की दृष्टि से पूरे राष्ट्र का लगभग पांच प्रतिशत हैं। हम 11 राज्य हैं। आबादी के आंकड़ों के गणित के अनुसार हमारा दबाव किसी भी केंद्र की सरकार पर इतना न बनता हो, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जहां हिमालय आज पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है, वहीं मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हिमालय शूर वीरों को भी पैदा करता है। पिछले युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश को सेना के अंदर चार परमवीर चक्र में से दो परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम शांति से अपने साथ हो रहे अन्याय को वर्षों से झेल रहे हैं, तो कदापि यह न समझा जाए कि

हमारी सहनशीलता हमारी कमजोरी है। कदापि यह न समझा जाए कि हम बोलते नहीं हैं, तो हमारे अंदर अंगार नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर कोई भावना नहीं है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर समझाने की ताकत नहीं है। अगर हिमाचल जैसा छोटा सा राज्य दो परमवीर चक्र विजेताओं को पैदा कर सकता है, तो कल को ऐसी स्थितियां पैदा न हो जाएं, जिस कारण वहां के नौजवान को इससे आगे बढ़ कर सोचना पड़ जाए। आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपयों की वन सम्पदा के मालिक होते हुए भी बहुत कठिन परिस्थिति में महसूस करते हैं, जब विकास के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी योजनाओं के लिए बोलते हैं और उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदया, आप बहुत विदुषी हैं, आपने देखा है कि जब-जब भी अन्याय और अत्याचार की सीमा लांघ जाती है, तो उसके बाद कुछ न कुछ जरूर होता है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं। वर्ष 1982 में सीधे यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद केवल 26 साल की उम्र में वहां की जनता ने सबसे छोटी उम्र का एमएलए बनने का गौरव प्रदान किया था। कई वर्षों से मैं निरंतर हिमाचल की राजनीति का हिस्सा रहा हूं, लेकिन आज यह भावना हमारे अंदर पनपती जा रही है कि क्या हमने ही सारे राष्ट्र को, सारी दुनिया को अच्छा पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल देने की जिम्मेदारी उठा रखी है। क्या इसके बदले दूसरे राज्यों की, केंद्र की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आज हम डेढ़ लाख करोड़ रुपए की अगर चाहें तो वन सम्पदा को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं लेकिन हम यह नहीं करना चाहते। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पिछली सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने इस पहाड़ी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था जो वर्ष 2013 तक चलना था। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति की आग की भेंट हो गई। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हमें बदले में कुछ देना तो क्या था बल्कि डस्ट्रियल पैकेज को वर्ष 2007 तक कर दिया था। इसके छः साल कम कर दिए गए, महज इसलिए कि वहां अन्य दल की सरकार है, महज इसलिए कि छोटा राज्य है। मैं मुख्यमंत्री श्री धूमल जी को बधाई देना चाहूंगा कि वे भारत सरकार के पास आए, उन्होंने सारा मामला रखा और उनके अथक प्रयासों से इंडस्ट्रियल पैकेज की सीमा वर्ष 2010 हुई। लेकिन वर्ष 2013 तक क्यों नहीं किया गया? हमारा कुसूर क्या है? हमारा कुसूर यह है कि हमारी आबादी छोटी है, एमपीज़ संख्या में कम हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों के विकास की दृष्टि से आगे ले जाने लिए निश्चित तौर पर अलग मापदंड बनाने ही पड़ेंगे। इन्हें जितनी जल्दी बना लिया जाएगा वह देश की सुरक्षा को लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदय, भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो भारत के मुकुट के रूप में हिमालय खड़ा है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चीन से हमारे पहाड़ी राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारी आजादी बहुत लंबी नहीं हो गई है, बहुत मेच्योर नहीं हो गई है, अभी हम बचपन में जी रहे हैं। चाहे वर्ष 1948 का युद्ध हो, कबाइली युद्ध हो या वर्ष1962 का युद्ध हो, उस समय हिमालय को ही जख्मी होना पड़ा था। मैं समझता हूं और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, आज भी अगर भारत को खतरा होगा या कोई ललकार आएगी तो वह चीन की ओर से आएगी, केवल हिमालय का राज्य ही चट्टान बनकर खड़ा होगा और चीन से खतरे का लोहा लेगा। लेकिन अब हिमालय के राज्य में यह भावना पनप रही है कि हमारी आबादी कम है, संसद में सदस्यों की संख्या कम है इसलिए हमसे भेदभाव होता है। आप भेदभाव करते जाइए, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जैसा अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि क्या हम यह भावना नहीं जगा रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा और सुना कि हिमाचल प्रदेश को इसलिए रेलवे लाईन नहीं दी जाएगी क्योंकि हमारी संख्या कम है। क्या इस तरह से भेदभाव किया जाएगा? हम कई सालों से देख रहे हैं कि जिस भी राज्य से कोई केंद्रीय मंत्री आता है केवल अपने राज्य की ओर ही दृष्टि दौड़ाता है, केवल अपने राज्य को ही पैकेज देता है। यह भावना बलवती हो रही है। हिमालय के लोगों में और विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी को लेकर गलत भावना पैदा हो रही है। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लीजिए। आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल चुपचाप बैठा है, हिमालय शांति से बैठा है। आप क्या समझते हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को इसलिए विशेष पैकेज दिया जाता है कि वहां चंद लोग कश्मीर घाटी में खड़े हो जाते हैं, सनसनी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं। क्या यह सरकार आतंक की भाषा ही समझती है? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें मजबूर न किया जाए क्योंकि इस तरह आतंकवादियों की शह से दिन प्रतिदिन यह भावना बनती जा रही है कि वही राज्य विशेष पैकेज लेकर जाता है जो राज्य सारे राष्ट्र को संकट में डालता है।

सभापति महोदय, अगर कारगिल युद्ध के दौरान हिमालच प्रदेश वीर जवान पैदा कर सकता है, दो परमवीर चक्र विजेता पैदा कर सकता है और कल को जरूरत पड़ती है तो वह कुछ भी कर सकता है इसलिए हमारी मौन भाषा को गंभीरता से लिया जाए। आज हिंदुस्तान को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है तो मैं कहना चाहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी भी हिमालय के कारण है क्योंकि जड़ी-बूटियां हिमालय के अंदर हैं। जब लोगों को गरमी से तकलीफ होती है तब सारा देश हिमालय की पहाड़ों की तरफ दौड़ता है और जब आध्यात्मिक शांति की जरूरत होगी तब भी हिमालय की ओर ही दौड़ना पड़ेगा। हिमालय ऋषि-मुनियों की पावन स्थली है। मैं समझता हूं कि हिमालय को बचाना और विकास की दृष्टि से आगे

बढ़ाना बहुत जरूरी है। यह प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कश्यप जी लाये हैं, यह बहुत समय के अनुसार आया है। इसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और अन्य साथियों ने किया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल समयोचित प्रस्ताव आया है और मैं भारत के आदरणीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इन पहाड़ी राज्यों के लिए जल्दी से जल्दी इस बोर्ड का गठन कर लिया जाए। माननीय श्री बहुगुणा जी ने ठीक कहा कि इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री जी ही करें। हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारा यह भी सुझाव रहेगा कि हिमालय के जो 11 राज्य हैं और जो उनके चुने हुए एम.पीज. हैं, उन सबको उस बोर्ड में मैम्बर बनाया जाए, ताकि उनकी सारी भावनाओं को समझा जाए। मैं इस प्रस्ताव के जरिये हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक प्रस्ताव की मांग करता हूं।

सभापति महोदया, अंत में मैं कहना चाहता हूं चूंकि आप कविताएं और शेर-ओ-शायरी भी करती हैं, इसलिए चंद लाइने मैं इस प्रस्ताव में जोड़ना चाहता हूं। हिमालय को समझने की दृष्टि से देखें कि हिमालय शान्त है, पर उसे कमजोर मत समझियेगा। हिमालय चुप है, लेकिन इसे भीरू मत समझियेगा, डरपोक मत समझियेगा। हिमालय विशाल है, हिमालय के पास ताकत है, हिमालय के पास खजाना है, हिमालय तब प्रकट होता है, जब प्रलय हो जाती है, तब भी हिमालय के अंदर ही सृष्टि के द्वारा रचना होती है। इसलिए हिमालय की गंभीरता को समझते हुए मैं चंद लाइने कहना चाहूंगा। आजकल जो लहरें राजनीति में चल रही हैं, मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं -

"लहरों के रूप पर कभी कलंदर नहीं गिरता,
टूट भी जाए तारा तो जमीं पर नहीं गिरता,
यूं तो गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समन्दर में,
पर कभी कोई समन्दर दरिया में नहीं गिरता।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I must appreciate hon. Shri Virender Kashyap for taking an effort to pilot the Resolution concerning the Constitution of National Board for the Development of Himalayan States. In this Resolution, attention has been focused on (i) all-round and speedy development of the States comprising the Himalayan region; (ii) monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States; and (iii) suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region.

As you know, the Himalayas is an identity of our civilization. It has divided Indian sub-continent from Central Asia. The Himalayas is always inspired awe, beauty and grandeur of the nature. Once upon a time, Swami Vivekananda had referred to Himalayas as follows: "It is not a mere wall constructed by nature; it is ensouled by our divinity; and it is the protector of our country and our civilization." Naturally, the Himalaya is an identity of our culture and our civilization.

Today, noted hon. Members have already participated in this discussion. They have already made a good deal of important suggestions for the development of the Himalayan region. As you know, in our country, eleven States have been recognized as Special Category States. These eleven States, consist Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir including seven States of North-Eastern region and Sikkim. Special category status has been given to those eleven States with an objective of paying special attention for the development of the Himalayan region.

So, we cannot say that this Government or any other Government of India has never paid heed to the problems of the Himalayan region. However, we must say that we have not been able to achieve the desired results insofar as the Himalayan region is concerned. But it is a fact that it has been the constant and continued endeavour of the respective Governments to put special emphasis on the

Himalayan region in view of its sylvan asset, in view of its mineral assets and in view of its herbal assets apart from tourism potentialities.

Further more, all the important rivers of our country originate from this particular region. So, we all believe, whether we do belong to Himalayan region or not, that Himalayas is a region of great importance. Sutlej, Ganga, Yamuna, Satadhruv, Indus, all these rivers originate from that special region. Nowadays, not only people from all over the country but people from all over the world feel concerned over the retreating glaciers of the Himalayan region due to climate change and due to global warming.

Forty per cent of the world population is being provided water by the Himalayan glaciers. It is alarming to note that every decade the Himalayan region has been heating up to the tune of 0.3 degrees Celsius which may prove calamitous, which may cause great devastation to the human population of the entire Indian subcontinent.

Madam, the Himalayan region consists of the Tibetan Plateau, the Kingdom of Bhutan, Nepal, and in the Indian area of Western Himalayas and North-Eastern Region also. The Union Government every year has been providing a handsome fund for the development of the Himalayan region. As far as my knowledge goes, 90 per cent of these funds are being provided to the Special Category States of the Himalayan region as grant and ten per cent as loan. So, we ought to see whether the concerned Himalayan region State Governments are spending the Central funds in an optimal way or not. I think that it is also a matter of concern that the States are not utilising properly the funds being given by the Union Government.

Madam, the mighty Himalayas extend from the West to the East in a massive area for about 2,500 kilometres forming a distinct geographical divide, an area of about 12,000 square kilometres. It is an area where there is a huge potential of hydropower resources. The exploitable hydropower resources are estimated to be to the tune of 9,500 MW.

It can create a vast network of power generation. Not only that, in the wake of power generation, we can also provide employment to the vast multitude of unemployed youth of that region who were still living in uncertainty. Yes, we have a great number of proud fighters; we always salute brave people and brave soldier, who come from that region - not only Uttarakhand or Himachal Pradesh but also the entire North-Eastern Region including Darjeeling. There is no dearth of proud soldiers, brave soldiers of our country, who used to lay down their lives at the frontier region to defend the nation. We are all proud of them. I personally salute all those people.

It has been found that the Himalayan State consists of high percentage of rural population, that is 79 per cent, and it is growing at an annual rate of 2.4 per cent. High percentage of population below the poverty line is 31 per cent in the North-Eastern sector whereas the position in the Northern States like Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir is better. The high literacy rate is 69 per cent. The total unemployed force which is 15.08 lakh, is growing at the annual rate of two percent. There is a very low *per capita* consumption of power – 100 kw - in the North-Eastern sector and in the Northern sector as compared to national average. Low per capita income is Rs.23,000. Majority of the labour force in the region is engaged in primary sector, especially agriculture, horticulture and animal husbandry.

The area of major concern is that in that particular region, the land-man ratio is becoming hostile. In the course of the growth of population, land is not expanding. Therefore, land-man ratio has been deteriorating. In the entire region, two types of land use has been in vogue. One is reserve forest area, and the other, community forest area. So, we need to have a strategy to use the potentialities of the land in such a way so that the local population could derive livelihood and on the other hand pristine nature of the forest could be conserved. So, this type of strategy could be adopted and to generate the employment, I think, small scale and

small level hydropower scheme could be initiated there which might create a vast opportunity for employment and livelihood.

Further, I would propose to the Government to consider the Silviculture of that region. Silviculture was introduced in Switzerland and other European countries. Land and the Silvian asset of the region could be used for the growth of the economy and to protect and conserve the forest also. Madam, I would like to just refer that most of the population of that particular area depend upon agriculture. However, this area has been able to attract substantial investment in the industrial sector, aggregating Rs.2,44,910 million. You are well aware that the Union Government extend tax holiday and other sops to attract investment in that region. However, it is found that the hill States of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir could create 0.2 million new jobs between January 7, 2003 and June 30, 2006.

17.00 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

This has meant a very high investment of Rs.1.22 million for creating a single job opportunity in the conventional industrial sector. Going by this figure, it is reported that the investment required for providing employment to the unemployed force of 15,08,000 would be a whopping sum, and the issue of generation of new employment opportunities by the conventional approach would continue to defy solution.

Therefore, various innovations need to be explored. Only a constitution of a Board would not be a remedy for all ills, would not be a panacea for all economic ills or all underdevelopment of that particular region. However, I think, a Board could be constituted; a Board could be constituted to look after development, to look after the growth, to look after employment opportunities, to look after other exploitable potentials of that area. But this is not the remedy for all economic ills and all underdevelopment or unemployment in that area.

Already in the State of West Bengal, the Himalayan area is known after Darjeeling; it is in ferment now. The reason is that the State Government has not been able to create employment opportunities, other industrial facilities, etc. Since the British period, the particular hill station, Darjeeling, has been regarded by the Europeans as a sanatorium, as a holiday resort. But that particular area where the natural resources are in galore, it is rich in mineral, we can excavate or mine coal in that Darjeeling region, which is famous for orange, for cinchona or for tea, let alone tourism but the State Government has not been able to create more opportunities for local population. That is why, the people of Darjeeling are being misled by saying that only the creation of a State of Gorkhaland would solve the problem. What we need is economic growth; what we need is more employment opportunities; what we need is a comprehensive and a holistic approach in the entire Himalayan region so that our mineral-rich and cultural-rich region could be developed.

Sir, you are well aware that for the development of the entire North-Eastern Region, a separate Ministry was formed. Generous budgetary allocation had been given. But still, the concerned State Governments had not been able to implement and utilize the sum provided by the Government and so, the Government was forced to create a non-lapsable fund so that in future, this non-lapsable fund could be used for the development of that particular area, that is, the North-Eastern Region.

I am concluding, Sir, but the fact is that we all respect Himalayas and all of us want to protect Himalayas, its civilization, its population and other resources.

Over the ages, the Himalayas is being adored by the people of our country. I may again say that it is an identity of our culture and civilisation and that is why we all should exhaust all our resources to protect not only this region but also protect its people. Hence, the National Board could be created. I support the constitution of National Board for the Development of Himalayan Region.

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Respected Sir, I support this Resolution. You are fully aware of the Assam and the Northeast regions in the foothills of Himalaya, especially a large part of Assam in the foothills of Bhutan. The geographical area of Assam covers mountains and rivers. We are facing flash flood problem from hill tracks. Our two districts have been inundated by the flash floods from hill tracks. In the other parts of the country the source of water has dried up but we are surrounded by water. Due to wrong water management, we do not have drinking water. In this context, I would like to quote a phrase: "Water water everywhere water but not a single drop of water to drink". In Assam, we do not have proper water resource management and hence people there face regular flood problems. After Independence we have always requested that this problem should be included in the list of national calamitis. It is a serious problem and it needs a serious attention to solve this problem.

Sir, due to mountainous terrain, road and rail communications are still not developed in comparison to other States. Any region surrounded by the international border faces problem. We still remember the trouble faced by the Indian Army during the Chinese aggression in 1962. The then Prime Minister Pandit Nehru lost hopes of our States to kept it part of the country. Since there was no road communication, Indian Army could not move forward. The development of road, rail and other communication system requires coordination between different Himalayan States.

In view of this, I support this Resolution. National Board for the Development of Himalayan States should be formed from better coordination, development and Defence point of view.

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): सभापति महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प में श्री वीरेन्द्र कश्यप जी ने जो रेज़ोल्यूशन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। हिमालयन राज्यों के लिए नेशनल बोर्ड फोर डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स अथवा ट्रांस हिमालयन (फोरम) Forum बने। हम लोग काफी पहले से इसकी मांग करते आ रहे हैं।

महोदय, हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उसमें पर्वतीय एरिया आता है, भांवर और तराई का एरिया आता है। वहां जो दैवीय आपदाएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसकी उपलब्धता ट्रान्स हिमालयन फोरम अथवा नेशनल फोर डेवलपमेंट आफ हिमालयन स्टेट्स करवा सकता है।

माननीय वीरेन्द्र कश्यप जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा टोपिक यहां उठाया। हमारे यहां जब बादल फटता है तो वहां आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और गांव के गांव दब जाते हैं। उस समय वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हमारे यहां इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं - जैसे अर्थक्वेक, बादल का फटना और भू-स्खलन इन चीजों को देख हमारे वहां डेवलपमेंट के लिए जरूरत रहती है। हमारे पहाड़ों के लिए मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है। For tourism what we need is light structures and not heavy structures. For example, resorts are coming up in the mountainous areas. We need light structures. We must learn from Himachal Pradesh. I am from Nainital Constituency of Uttarakhand. We must learn from Himachal Pradesh about how to bring up light structures for tourism like log cabins, tents and pre-fabricated structures so that it does not break. It is much safer. Our hills can take light structures and not big concrete jungles that seem to be coming up. We have got to stop it somehow or the other. That is the main thing and because of the natural calamities, we have got to be very careful in dealing with this. We have got to have development; and development, as I said previously, is tourism. For tourism, we must have ropeways. The new found maintains of the Himalayas can stand the pressure of ropeways and helipads instead of having very big road constructions in the mountains. So, we have got to be very careful about how we go about our development. Our forests are our assets and our forests are what you call our livelihood in the hills. So, we must

maintain the forests while doing development. So, there has to be a balance between development of roads as well as cutting down of trees.

हमारे वहां जब भी सड़कें बनती हैं, आप यह समझिए कि प्लेन में जो सड़कें बनती हैं, उसमें और हमारे पहाड़ों में जो सड़कें बनती हैं, उनमें बहुत अंतर है। पहाड़ में जब भी हम सड़क बनाते हैं तो उसमें रिटेनिंग वॉल देनी पड़ती है, जिससे कि पहाड़ नीचे न खिसके। जहां कोई गांव आता है, वहां जो सड़क बन कर जाती है तो फिर हमें ब्रेस्ट वाल देनी पड़ती है, जिससे कि वहां जो ऊपर के हिस्से में घर हैं, वे डैमेज न हों, उनमें क्रेक्स न आएं। हमारे पहाड़ों में जो कास्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है, वह प्लेन के मुकाबले डेढ़ गुना से पांच गुना ज्यादा होती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसके लिए हमारे हिमालयन स्टेट्स को स्पेशल पैकेज दिया जाए। चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या डेवलपमेंट हो, बिना स्पेशल पैकेज के पहाड़ में काम नहीं चल सकता। हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, हमारे माननीय सांसद बहुगुणा जी ने भी कहा था कि सन् 2013 तक का पैकेज मिला था जो कि कम कर दिया गया, उसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सन् 2013 तक का इंडस्ट्रियल पैकेज हमें दिलवाया जाए। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहां मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत अंतर है, जो प्लेंस में होता है। हमारा जो फोरम बनता है, जो एडवायज़री कमेटी का काम करेगी, वह यह बताए कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, स्टेट्स में क्या-क्या समस्याएं हैं, यह अतिआवश्यक है।

मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं, इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी नैनीताल संसदीय क्षेत्र जो है, वहां पहाड़, भांवर और तराई भी है। वहां जब पहाड़ में बादल फटें या पहाड़ों में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो हमारे पर्वतीय स्टेट की स्थिति और प्लेंस में बहुत अंतर होता है।

सभापति महोदय, वहां से जब पानी का बहाव नीचे की ओर होता है, जब वह पानी नीचे आता है, भावर और तराई में, तो इतनी स्पीड से आता है कि वहां से भूमि का कटाव होना शुरू हो जाता है। भूमि कटाव होने से बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं और जान-माल का बहुत नुकसान होता है। लोग मरते भी हैं, भूमि भी कटती है, लोग भूमिहीन हो जाते हैं और गांव भी बह जाते हैं। इसमें बहुत अन्तर है। प्लेन्स में जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी भर जाता है और उससे बेहद नुकसान होता है, यह मैं जानता हूं, लेकिन वहां जमीन सुरक्षित रहती है। जब बाढ़ का पानी चला जाता है या सूख जाता है, तो जमीन वहीं मौजूद रहती है। उस पर जमीन का मालिक किसान काम कर सकता है। उसे जोत और बो सकता है। हमारे यहां यह अन्तर है कि जब बाढ़ आती है, तो वहां पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वहां की कृषि भूमि कट कर बह जाती है और लोग भूमिहीन हो जाते हैं। छोटा स्टेट है और वन अधिनियम लागू है। इसलिए

हम उन्हें दूसरी जगह एडजैस्ट भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, उन्हें एक स्पैशल पैकेज दिया जाए, विशेषरूप से दैवी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए।

महोदय, दैवी-आपदा से बचाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सिल्टेशन से जब नदी भर जाती है और बाढ़ आती है, तो पानी साइडों को काटकर निकल जाता है। इसलिए रिवर ड्रैजिंग की जाए और जे.बी.सी. मशीन द्वारा उस सिल्टेशन को हटा दिया जाए या नदियों को गहरा कर दिया जाए, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। यदि सरकार शुरू में पैसा लगा दे और नदी का कोर्स जिस तरह से पहले था, उस तरह से कर दे और इस प्रकार हर साल हम माइनर ड्रेजिंग करते रहें, तो हमारी सरकार का पैसा भी बच सकता है, हमारे किसानों की भूमि का कटाव भी रुक सकता है और इस प्रकार की रैगुलर रिवर ड्रेजिंग और कंट्रोल्ड खनन से सरकार का करोड़ों-अरबों रुपया बचेगा और भूमि भी बचेगी। किसानों की जब भूमि नहीं कटेगी, उनके घर नहीं बहेंगे, तो उन्हें भी फायदा होगा। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि हमारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, उन्हें देखकर हमें स्पैशल पैकेज दिया जाए। जब हमें स्पैशल पैकेज मिलेगा, तो यह समझिए कि हम अपनी स्टेट की रक्षा भी कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट के लोगों का बचाव के साथ-साथ विकास कार्य में गति मिल सकती है । इस प्रकार से हम फॉरैस्ट और एनवायरनमेंट का बचाव भी कर सकते हैं। जब वहां भूमि नहीं कटेगी, तो हमारे फॉरैस्ट भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी कृषि भूमि भी सुरक्षित रहेगी।

श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर) : चेयरमैन सर, मैं आपको और विशेष रूप से वीरेन्द्र कश्यप जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव समयोपयोगी है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को पूरे सदन को मिलकर पारित करना बहुत जरूरी है। बादल फटने के कारण वर्षा होने से बहुत सी जगह में एकदम इतनी जोर से पानी आता है कि जो भी हमारे घर, रास्ते, खेती की जमीन थी, उसे बहाकर ले जाता है। सिर्फ आधे घंटे में सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में ऐसा होता ही रहता है। हम लोगों के पहाड़ी एरिया में प्रायः ऐसा होता है। हमारे पहाड़ी इलाके में बादल फटने के कारण जो बाढ़ आती है, उसका असर प्लेन एरिया में भी बढ़ जाता है। महोदय, सी-इरोजन होने पर वहां के राज्यों की क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में रिवर इरोजन के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि रिवर-इरोजन होने पर राज्य की क्षतिपूर्ति हेतु धन मिलना चाहिए। हर नदी की उत्पत्ति पहाड़ों और जंगलों से होती है। जंगल देश के सभी लोगों को वायु और पेयजल उपलब्ध कराते हैं। अगर इनको ठीक प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जाए और वहां से पहाड़ या पेड़ कट जाए, तो इरोजन से जो डैबरीज होती हैं, वे प्लेन एरिया में पानी के बहाव के साथ आ जाती हैं। वहां का जैसा उदाहरण दिया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ब्रह्मपुत्र में इतनी डिबरी हो गई, रीवर बैड इतना ऊंचा आ गया है, जिसमें वहां अब बड़े-बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं। विदेशियों के टाइम में इन्हीं जहाजों से ब्रिटिश लोग वहां चाय बागान लगाने और चाय की खेती करने के लिए आये थे। अब हमारी ब्रह्मपुत्र रीवर में कोई बड़ा जहाज नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका रीवर बैड ऊंचा आ गया है। जितनी ऊंचाई में वर्षा होगी, उससे वर्षा के समय में डिबरी ब्रह्मपुत्र में आ जाती है और उसके आ जाने से इसका रीवर बैड ऊंचा हो गया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसी-किसी जगह में ब्रह्मपुत्र की 20-25 फुट दूरी तक लेंथ बढ़ी हुई है, उसका इतना डेल्टा हो गया है, इतनी डीप हो गई है कि नदी इधर-उधर घूमकर जा रही है और उससे सब लोग इधर-उधर जा रहे हैं। अगर इसको एक ही रास्ते में सीधा किया जाये तो खेती के लिए बहुत मिट्टी इससे निकलेगी और लोगों की परेशानी दूर होगी।

हर वर्ष ब्रह्मपुत्र से इतनी ज्यादा क्षति होती है, इतना ज्यादा जान-माल का नुकसान होता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं यह सोचता हूं कि यह सब करने से निश्चय ही हिमालय में हम लोगों का जो राष्ट्रीय हिमालय राज्य विकास बोर्ड बनने वाला है, यह बोर्ड बनने से हम लोगों का ऐसा बहुत कुछ है, जिसमें हम लोगों को बोलना है, मैं सोचता हूं कि यदि आप लोग इसमें हम लोगों को, पार्लियामेंट के मैम्बर्स को रखेंगे तो यह सब करने के लिए हम सब लोग साथ में रहकर सुझाव दे सकते हैं, इससे इसका उपाय निकाला जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, यह हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा वाटर बम भी है। अभी वहां इतने भारी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कभी एक इरोज़न में टूटने से हम लोगों के असम के आधे भाग को बहाकर ले जाएंगे। आप वहां उसे हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वे वाटर बम हो रहे हैं। जहां पानी डीपर हो गया है, वहां कभी ऐसा होगा कि असम के आधे भाग को बहाकर ले जायेगा। वहां पानी की इतनी हाइट होगी कि 20-30 फुट तक पानी आयेगा, जिसमें हमारे असम में ब्रह्मपुत्र में दोनों साइड में जितनी जगह है, उसको वाश आउट करके एक ही बार में ले जाने का भयानक डर है।

मैं इसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं। रंगनदी रीवर में जो हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट लगाया गया, इसमें जितना इरोज़न, जितनी क्षति हुई, इसका हमारी स्टेट गवर्नमेंट को और जिसकी प्राइवेट प्रोपर्टी गई है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी तरफ से उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। यह सब हिमालयी स्टेट की, हम लोगों की पहाड़ी स्टेट्स की जो समस्या है, यह हम सब लोग वहां रहने से बोल सकते हैं और हम लोग बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं।

कश्यप जी जो प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन मिलकर इसे पारित करेगा, ताकि इस पर अमल हो सके। हमारे सभी सदस्य मित्रों ने बोला है कि यह समयोपयोगी और बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, इसलिए इस पर अमल किया जाये और इसमें जो कुछ भी करना है, इसका टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, ताकि देश का लाभ हो सके।

मैं यही बोलकर, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं और मुझे सौभाग्य है कि मुझे उसी विषय पर बोलने के लिए भी मौका मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। मैं अल्मोड़ा से सांसद हूं और मैं सम्माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप जी के इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक अलग विकास बोर्ड बनना चाहिए।

मैंने बहुत से सदस्यों की सारी बातें सुनीं। दो-तीन बातें मैं भी कहना चाहता हूं। आज पूरे हिमालय को लेकर एक अलग हिमालय नीति बनाने की जरूरत है। हिमालय देश का मस्तक है। हिमालय इस देश की सभ्यता, संस्कृति का द्योतक है, लेकिन आज उस पर संकट है। यहां वन संरक्षण की बात कही गयी। बहुत से सदस्यों ने कहा कि आज फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण हिमालय के विकास कार्य रूक गए हैं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी का बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरूआत वहीं से की। जब हिमालय के अंदर एक आंदोलन चला था, जंगलों को बचाने का आंदोलन, जिसको दुनिया में लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं या वन आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज यूरोप, अमेरिका सहित पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कह रही है, उस समय पूरी दुनिया अपनी जीवनशैली के कारण इन जंगलों को बर्बाद करने में लगी हुयी थी। सिर्फ उसी हिमालय क्षेत्र की हमारी मां-बहनों ने, विद्यार्थियों ने एक आंदोलन चलाया था कि हिमालय को बचाना है, तो जंगलों को बचाना चाहिए। उस आंदोलन के दौरान सत्तापक्ष के दमन चक्र हमने सहे और एक मांग की कि हिमालय के जंगलों को बचाना चाहिए। तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री ने इस बात को सुना और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, जिससे जंगलों को बचाया जा सका। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, लेकिन कोई मांग नहीं करता कि थानों को बंद कर दिया जाए, बल्कि लोग मांग करते हैं कि कानून का और कड़ाई से अनुपालन किया जाए। लेकिन यहां जब-जब पर्वतीय क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को एक विलेन के रूप में चित्रित किया जाता है। राज्य सरकारों के जो विभिन्न विभाग हैं, डेवलपमेंट के विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, फारेस्ट विभाग है, जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर केंद्र तक कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। मैं जब विद्यार्थी था, तब हजारों ट्रक उस हिमालय से, नदियों से निकलते हुए मैंने देखे थे, सड़कों से निकलते हुए देखे थे। हिमालय में आज जो जंगल बचे हैं, हिमालय बचा है, हिमालय का पानी बचा है, तो वह उस जंगल आंदोलन की वजह से बचा है, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से बचा है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मैं समझता हूं कि इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हिमालय का फारेस्ट नहीं बचेगा, तो सिर्फ संकट हिमालय के

ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जो इस देश की सभ्यता-संस्कृति की मुख्य कड़ियां हैं, उन पर भी संकट आएगा।

मित्रों, आज हिमालय में तीन चीजें हैं - जल, जंगल और जमीन। ये तीन हिमालय की मूल आत्मायें हैं। जंगल को किसी तरह से हिमालय की बहनों और नौजवानों ने, जब पूरा देश और न कोई वैज्ञानिक और न ही दुनिया इस सवाल को उठा रही थी, तब अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली की महिलाओं ने, नौजवानों ने उन जंगलों के लिए सवाल उठाया। आज भी जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगलों को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। यह अलग बात है कि जंगलों पर लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट हैं, उनको सरकारें और विभाग रिकगनाइज नहीं कर रहा है। उनको वह राइट नहीं दे रहा है। फारेस्ट आंदोलन की एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसको हम हकोकू कहते हैं कि जंगल के लोगों के जो ट्रेडिशनल राइट थे, वे उनको दिए जाएं। वे राइट उस अनुपात में नहीं दिए जा रहे हैं। वन विभाग अपने डिपार्टमेंट का शिकंजा बनाए रख रहा है। जब पूरा उत्तराखंड जंगलों की आग से सुलग रहा था, उसी पौड़ी जिले के 8 ग्रामीण किसान जंगलों को बचाने के लिए गए और शहीद हो गए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देश की रक्षा के लिए सीमा पर जो जवान लड़ते हैं, उसी तरह से जंगलों को बचाने के लिए जो पौड़ी जिले के 8 किसान शहीद हुए, उनको भी उसी तरह राष्ट्रीय पुरस्कार और शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी शहादत को रिकगनाइज किया जाए। जब किसान, जंगल के लोग जंगलों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी शहादत को हम रिकगनाइज नहीं करेंगे, तो जंगल कैसे बचेंगे? आज फारेस्ट विभाग पाइन्स के जंगल लगा रहा है। जंगलों को बचाने के लिए वहां के लोगों की जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नियोजन कर सकती हैं। उन दोनों का समन्वय किया जाए कि किस तरह के जंगल हमें लगाने चाहिए, चारे के हों या किसी और तरह के फारेस्ट हों, जो वहां के लोगों से जुड़े हुए हों। अगर उस तरह की एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसमें वहां की ग्राम पंचायत, स्थानीय लोग और जंगल विज्ञान, जंगल बचाने के लिए एक-दूसरे की नॉलेज को शेयर करेंगे, उससे जंगल बढ़ेंगे।

दूसरा सवाल नदियों का है, पानी का है। मेरे संसदीय क्षेत्र से एक आंदोलन शुरू हुआ जो कोसी बचाओ आंदोलन की तरह आज पूरे उत्तराखंड के अंदर नदी बचाओ आंदोलन बन गया है।

आज इस सदन में यह बात आई कि पूरा हिमालय पानी से प्यासा है, गांवों के गांव प्यासे हैं। सामने से नदी निकल रही है और ऊपर खेत प्यासे हैं। हिमालय के खेत प्यासे हैं, हिमालय के लोग प्यासे हैं। लेकिन हमारी नजर हिमालय के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर हिमालय के खेतों के सिंचाई के संकट को दूर करने पर नहीं है, हमारी नजर उस पानी का उपयोग गैर खेती या दूसरे इरादों पर करने की है। मैं इस सदन के माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं। हमारे मित्र ने कहा कि हिमालय में तमाम हाइड्रो-पावर प्रोजैक्ट बन सकते हैं। हिमालय में चलने वाले इस तरह के तमाम प्रोजैक्ट्स चाहे टनलों के माध्यम से हों, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव के लोगों के साथ एक कम्पनी ने समझौता किया। 20 किलोमीटर टनल निकाल दी। उन्होंने कहा कि हम आपके लोगों को रोजगार देंगे, हम आपको पांच-पाच लाख रुपये मुआवजा देंगे। जिला प्रशासन के जरिए समझौता हुआ। आज जब उस गांव के लोगों ने उस समझौते को लागू करने की मांग की, तो जिला प्रशासन और उस कम्पनी ने उस गांव के लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए कि ये हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। बीस-बीस किलोमीटर टनल में नदियां चली गईं। यदि बीस किलोमीटर टनल में नदी जाएगी तो उस बीस किलोमीटर के अंदर आने वाले गांवों का क्या होगा, खेतों का क्या होगा, पेयजल का क्या होगा, इस बारे में सोचने की जरूरत है। आखिर हम उनके लिए क्यों नहीं सोचते। ऊर्जा राष्ट्र की जरूरत है। इस देश में बहुत वैज्ञानिक हैं। ऊर्जा के लिए दूसरे रिसोर्स का प्रयोग किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी या दूसरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। मेरे हिसाब से पानी का पहला उपयोग लोगों के पेयजल के लिए है। दूसरा हिमालय के खेतों का है। अगर हिमालय के खेतों को नहीं बचाया गया, वहां माइग्रेशन हो रहा है, इससे हिमालय में संकट हो जाएगा। तीसरा, हम सब कह रहे हैं कि हिमालय में पर्यटन उद्योग होगा। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, पर्यटन इंडस्ट्री पानी पर निर्भर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है।

जल, जंगल के अलावा हिमालय में एक संकट जमीन का है। पूरे क्षेत्र में विशेषकर जो खेती की जमीन है, वहां पर खड़िया और साफ्ट स्टोन की अनेक माइन्स लगा दी गयी हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राज्य का धर्म कमजोर की रक्षा करना है, राज्य का काम किसान की जमीन की रक्षा करने का है। मेरे संसदीय क्षेत्र विशेषकर बागेश्वर के अंदर राज्य सरकार द्वारा खड़िया खनन के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आज पूरी साफ्ट स्टोन इंडस्ट्री भू-माफियाओं द्वारा चल रही है। हमारे वहां लैंड का मेजरमैंट नाली के रूप में होता है। एक एकड़ में 20 नाली होती है। किसी के पास पांच नाली है तो किसी के पास दस नाली है। सब खड़िया माफियाओं के कब्जे में है। मैं उन क्षेत्रों में गया हूं। सरकारों ने मेमोरेंडम दे दिया है, प्रशासन कहता है कि दस मीटर से ज्यादा नहीं खोदा जायेगा,

लेकिन 20-20 मीटर खुद रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है कि माइन्स एक्ट का क्या हाल है? मेरा कहना है कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने साफ्ट स्टोन, लाइम स्टोन से देहरादून को बचाया था, आज हिमालय के उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बागेश्वर और पिथौड़ागढ़ में साफ्ट स्टोन की इंडस्ट्री है, गरीब किसान लालच में आ जाते हैं कि इस जमीन में क्या होगा, जब उन्हें दो हजार रुपये नहीं मिलते, लेकिन अचानक 20 हजार रुपये दिखते हैं, 50 हजार रुपये कैश दिखते हैं, ठेकेदार के लोग जाते हैं, प्रशासन के लोग जाते हैं, पैसे का लालच होता है और उसके बाद धमकी भी दी जाती है। मसल पावर और मनी पावर के संदर्भ में राज्य को आगे आना चाहिए।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है कि हिमालय डेवलपमैंट अथारिटी बननी चाहिए, यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ हिमालय के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत है, एक अलग नीति की भी जरूरत है। पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। वहां सड़कें नहीं हैं। हमारे वहां टनकपुर से जॉलजुड़ी सीमांत क्षेत्र का इलाका है। वहां आज तक मोटर रोड नहीं बनी है। बिजली के टनल के लिए हमारे पास 20 किलोमीटर की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में रेलवे के टनल क्यों नहीं जा सकते? ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि विज्ञान का उपयोग स्थानीय लोगों के हक में क्यों न हो? जब हम बिजली पैदा करने के लिए 20 किलोमीटर टेक्नोलॉजी की टनल बना सकते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में रेलवे के प्रौजेक्ट क्यों नहीं जा सकते। जितने भी इस तरह के प्रौजेक्ट हैं, जैसे रेल इंडस्ट्री है, टनकपुर से बागेश्वर है, रामनगर से चौखुटिया है। इन तमाम हिमालय के प्रौजेक्ट्स को नैशनल प्रौजेक्ट्स के रूप में आगे बढ़ाया जाये।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिमालय क्षेत्र में जो केन्द्रपोषित परियोजना चल रही है, उसकी मौनीटरिंग की सख्त आवश्यकता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमैंट फंड बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार करोड़ों रुपया दे रही है, लेकिन वह पैसा बिना यूज किये हुए वापिस आ रहा है।

मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सम्मानित सदन से अनुरोध करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार योग्य है इसलिए केन्द्र सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।

अगर इसका कांस्टीट्यूशन हो, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को, चूंकि हिमालयन स्टेटस का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को चेयर करना चाहिए और लोकसभा तथा तमाम राज्यों के सम्मानित सदस्यों या देश के अन्य सदस्यों को इसमें जगह मिलनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for this discussion is over now. If the House agrees, the time for the discussion on this Resolution may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It is a very important subject.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, I call the next hon. Member Shri Tathagata Satpathy to speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, Sir, I cannot but support the Private Member's Resolution on the National Board for the Development of the Himalayan States. It is a brilliant idea and I must congratulate the hon. Member of Parliament who has brought forward this Resolution. But, Sir, let us not limit this to making it like a bloated District Vigilance and Monitoring Committee kind of a set up.

As you know, the Himalayas are a very important geographical part of the whole globe, the whole world. They have a major role to play in the environmental balance not only for this sub-continent but also for the whole of Asia as such and thereby we can assume for the rest of the world too.

There are basically two types of rivers that we see in this sub-continent. One is the perennial rivers that flow twelve months a year, come rain, come sunshine and most of them originate from the Himalayas, from the glaciers. The other one is the peninsular type which is mostly rain-fed and we find that because of a lot of procrastination on the part of the Central Government, when it comes to the project to connect inter-linking rivers which we were hearing about in the late 1990s and the earlier 2000, nothing has actually been done in that aspect thereby we have deprived the people of this sub-continent of getting drinking water, water for irrigation. So, the large tracts of this country today, especially in 2009, are reeling under acute shortage of drinking water. It is so because there are no signs of the monsoon yet and our agriculturists have been very badly hit. So, let us not minimize the problem of safeguarding the Himalayas to only a few States or look at it with myopic eyes as if it is a rural development issue or something like that.

The Himalayas, with the environmental importance that they enjoy, have to be safeguarded. We all know that the glaciers are melting fast and they are melting so fast that it is said that by the year 2025, the Himalayan rivers, the so-called perennial rivers will start drying up and this will affect the whole of India, Pakistan and Bangladesh. A famine-like situation might continue for a very long time.

Therefore I would suggest that a human and environmentally balanced outlook at this zone is very necessary. It is not only a problem of the Northeast or Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir, but the Himalayas have to be looked at in a very holistic manner, in a very total manner. In this area, we can produce a lot of hydro electricity and that should be able to give energy to major parts of this country. Instead of doing that in a balanced way where strict environmental monitoring is maintained at all times, we are allowing this area to be plundered and looted. If we go to even hill stations like Shimla, Manali and Nainital, these towns have become ugly slums now. I remember, as a child when I used to go to Shimla and other hill stations, they had a lot of trees and greenery and they used to be genuinely cold. Now when you go there in the summer, even the mountains have started getting hot. That means, somewhere down the line, we have made a major mistake by which we have tinkered with the environment of these areas and have very badly damaged these areas. So, the Himalayas have to be protected while keeping in mind the environmental conditions of that area.

Sir, I had the pleasure, in the last Lok Sabha, to be invited to Tajikistan and the way the Chinese have moved into Kyrgyzstan, Tajikistan and those Central Asian countries is amazing. They are taking care of the environment very well and yet building up infrastructure there. In India, what we see is, if we want to build a road, the first casualties are the trees and the natural water bodies. We destroy our environment whereas on the other hand, in those areas, especially in Tajikistan, the Chinese have actually taken a lot of care to protect environment.

Therefore I would like to sum up my speech and say that while talking of the Himalayas, let us not have a narrow outlook on the issue. Let us also think of the greater interest of the whole Sub-Continent and of the complete area, starting from Kashmir right up to Brahmaputra in Assam and Arunachal Pradesh. We have to look at it in a total manner. In the last Lok Sabha we were discussing that Arunachal Pradesh alone has the capacity to produce 65,000 MW of hydro electric power if the resources are properly tapped. That means, we have enough

resources, but we have to maintain these resources with a sustainable outlook and take care of the environment while having a human face.

So I would like to wholeheartedly support the setting up of the Board that is being suggested in this Resolution. But the ambit of the Board should be much greater. It should not be limited only to become a rural development monitoring board; it should rather look at the environment, look at the interests of the people of those areas and give them infrastructure without destroying nature which is at its best in the Himalayas.

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

महोदय, जहां तक राष्ट्रीय पर्वतीय विकास बोर्ड के गठन की बात है, मैं उसका समर्थन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी प्रांत हैं, जो समतल होने के बाद भी अपनी दयनीय स्थिति पर विवश हैं। जहां से मैं आता हूं, बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण, भीषण बाढ़ और भीषण सुखाड़ के कारण विकास की दर बहुत पीछे है। लाख प्रयास के बाद भी वहां के आम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, जिससे हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि वहां की आम जनता जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वह उसे उपलब्ध कराई जाएं। जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें हमारे बिहार राज्य को भी समाहित करते हुए राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि पूरे राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

बिहार राज्य एक समतल राज्य होने के बाद भी वहां केन्द्रीय विद्यालय तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है। वे दूसरों के भवनों में चल रहे हैं। उनका अपना कोई छात्रावास नहीं है। इसी तरह वहां थाने तो हैं, लेकिन उनका अपना भवन नहीं है। वहां के अस्पतालों की हालत बहुत जर्जर है। हमारी मांग है कि एक राष्ट्रीय विकास बोर्ड का गठन हो और उसमें जितने भी पिछड़े राज्य हैं, सभी को शामिल किया जाए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity of placing a few points in the discussion on the Private Members' Resolution that has been brought by Shri Virender Kashyap.

I fully support the Resolution and would like to say a few words in so far as the mountains are concerned. This is regarding the Himalayas, and so therefore, we have to look at it in terms of a mountain paradigm. I think, the entire issue is the understanding of what had been developed or what should be the way the development has to happen in the mountains and that has to be first understood. It is completely different from what you do in the plains or any other part of the country because the formation of the mountains, the way the societies are developed in the mountains, the way the people in the mountain actually live, calls for a different way of look at development.

I think, this is the central issue on hand and if we actually get to this issue, then I am sure that we would be in a position to not only commit the resources that are required but also have a look at the entire development scenario with that view in mind. Now, many of the speakers before me have already articulated much of the views and the problems that have been obtained in the mountains or the people of the mountains. The view on the environmental factors, the view on water and water resources have also been articulated.

I will not get into that but what I would like to do is, because I come from Sikkim, I would like to make a mention out here that Sikkim is the first State to actually constitute a commission to look at the glacier retreat and possible solutions. Indeed one of the biggest glaciers, which is over 750 sq. kms. in size which is known as the Zemu Glacier, is already receding at an alarming rate. This only is an indication of the global warming pattern affecting the mountains.

The second thing that I would like to bring to the notice of the House is that the entire Himalayas are facing a similar situation. So, therefore, it calls for a national consensus on how we are going to tackle the entire issue of glaciers and the melting of glaciers and its consequent action on the water resources that are

going to be made available to the entire Himalayan belt. You already know that some of our dams have already registered alarming decreases in water and that is due to the fact that the snow melt this year has been absolutely very minimal. These are signs of time and I would exhort the Government to look at this particular issue with the utmost of care. The Government on its part in the Eleventh Five Year Plan had commissioned the first Workgroup on Mountains and that is a positive sign because there are already indications within the Government that the mountains are very important.

Therefore, I would like to state that it is high time that we looked at the entire Himalayan Belt as an absolute strategic resource. It is not only strategic in terms of our security; it is strategic in terms of our development; it is strategic in terms of the overall environment.

There is the other aspect. This entire border stretch is closed. It is a stretch of almost 4000 kilometres which is closed in terms of border trade. In 2006, Nathula was opened up for border trade with Tibet and China. Today, we know that whatever little bit of trade that is going on is not of a substantial amount. Trade and other such mercantile activities across the border can fetch a lot of livelihood to the people of the mountains. You will recall that in 1962, after the borders were closed, there were huge losses on both the sides of the border. There are plenty of people on this side who also have relatives on the other side of the border. So the social cost of that particular closure has indeed been very great. We have to look upon this also as one way of linking great civilisations.

The other thing that I would like to bring to your notice is that the river Yangtze at some point of time is going to be diverted within China. That is a great cause of concern for the Brahmaputra and the people of Assam in general.

I would also like to say that the livelihood scenario in the mountains has to be looked again though the paradigm of the mountains, and the mountains need to be focussed as a different development model rather than just looking at it as a general development model. It is very difficult to build roads in the mountains. We have to look at local resources. We have to deal with the problem of carbon load. Whenever we take foodstuff and other commodities up into the mountains, there is a huge carbon load. I think, we need to look at all these things including transportation, including the entire way which we develop.

So, what I would request is that this particular Resolution be expanded in terms of its scope. I completely agree with the previous speaker that the ambit of the Board needs to be expanded in full and in a very comprehensive manner we should look at development in the mountains. As I said, if this is understood, then the other resources that need to be committed would follow suit.

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I am very happy to have this opportunity to speak on the Private Members' Resolution. I come from Manipur representing Outer Manipur. Majority of that area is hilly. In this regard, I would like to share with you the problems faced by the States of the Himalayan Region. Particularly, there are natural calamities; there are economic problems; there are communication problems that we face. I would like to point out Manipur in particular. Other States of North East also face the same kind of problems. In Manipur we have a number of problems particularly in hilly areas. Development of this region is very difficult because of the geographical factor. For construction of a road – say one kilometer stretch – in a valley area, it may take Rs. 1 crore or Rs. 10 lakh. But in hilly area, it requires three times or ten times of that amount. Therefore, I would like to draw the attention of the Central Government to the matters particularly relating to the hilly areas.

The Himalayan Region States, particularly the hilly States, have no resources, and they solely depend on the Central Government for undertaking the developmental activities and other works. If the Central Government is not taking a bold step towards the Himalayan Region, then the people of the Himalayan Region will suffer.

As we know, India is one of the biggest democratic countries. The boundary States, particularly in the hilly region, are lagging behind the mainland in all respects. I would like to draw, once again, the attention of this august House and the Government of India to have a sympathetic attitude towards the boundary States. The constitution of the National Board for the development of Himalayan States is one of the remedial measures which should be taken up by the Government.

Lastly, I would like to say that this Region has not only economic and geographical problems but also some other social problems. The developmental works cannot be implemented properly because of social problems. Anti-social elements are there. Due to militant activities, we cannot take up the developmental activities properly. In this regard, I would like to draw the attention of the Ministry of Home Affairs also to control such militant activities so that the developmental works can be effectively implemented.

With these few words, let me conclude my speech.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I rise to participate in the discussion on the Resolution moved by my hon. Friend, Shri Virender Kashyap.

Actually, this type of a Board is a necessity for the regions which we always categorize as 'difficult area Regions'. The Himalayan Region, as we know, has got a lot of problems on its own. For example, when we talk of natural calamities, in Delhi we do not rather think in terms of having an earthquake even though it comes very seldom here but in the Himalayan Region, earthquakes come very often.

My friend has just now mentioned about certain problems of the State of Manipur. Manipur happens to be at the tail end of the Himalayan Ranges. Of course, we are far away from Jammu and Kashmir and other places. Even then, we still feel the tremor and whatever difficulties we have in Jammu and Kashmir and the other border States of the country.

While drawing the attention to formation of this particular Board, I would like to mention that we have a particular Ministry under the Government of India, that is, Development of North-Eastern Region (DONER), which is functioning as the constitutional body for the entire North-Eastern Region. While constituting this particular Board, we shall not go in terms of, what is called, overlapping the powers and functions of this Ministry. Sometimes it might happen that when we have a body looking after the entire North-Eastern Region – this North-Eastern Region comes under the Himalayan Ranges also – we have to look at that demarcation while considering this.

18.00 hrs.

MR CHAIRMAN : Hon. Member, you may continue your speech next time.

DR. THOKCHOM MEINYA : Thank you, very much. This time, I came unprepared also. So, next time, I would come well prepared and continue my speech.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Special Mentions and matters of urgent public importance.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Respected Chairman, Sir, in a parliamentary democracy, we have three wings, that is, the Legislature, the Executive and the Judiciary, which are all independent bodies. One wing cannot interfere into the affairs of the other wing because we have to maintain democracy. But last week, one hon. sitting Judge of the Madras High Court had said in the open court that a Union Minister had tried to influence him to grant bail in a criminal case, to father and a son, who are involved there. It has been very widely reported in all the national media also.

Sir, it is a very serious matter as it is a case of patent contempt of the Judiciary. This attempt of a Minister to interfere into the affairs of the Judiciary is unfair and unheard of.

Therefore, on behalf of my party the AIADMK and on my own behalf, I strongly condemn this attempt of a Minister. I feel that the whole House should condemn this in one voice and a clear message should go from this House. This act of a Union Minister warrants a very serious action by the Government. We demand that the hon. Prime Minister should make a statement in this House regarding this matter. He should take stern action by dropping the concerned Minister from the Union Council of Ministers. I would also urge upon the hon. Prime Minister to direct the hon. Law Minister to get a detailed report on this and to restudy the case against the concerned Minister under the Prevention of Corruption Act.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Sir, I would like to draw the attention of this House and of the Union Government that all the Governments that came to power at the Centre after Independence had theoretically advocated for narrowing down of regional disparities but in reality, the regional disparities including *per capita* income have widened. It is also a fact that the Special Category States have a low resource base, and they are not in a position to mobilize resources for their

developmental needs. Therefore, a special dispensation should be made for the Special Category States to enable them to narrow down the regional disparities and to catch up with the level of development in the rest of the country.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैंने दिनांक 8 जून को एयर इंडिया के बारे में अपना वक्तव्य रखा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 2 जुलाई को मैंने स्वयं सिविल एविएशन मंत्री जी से मुलाकात की और रिक्वेस्ट की और आज दोबारा यह मामला उठा रहा हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एयर इंडिया का व्यवहार ठीक नहीं है। चैन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर तक एयर फेयर की रेंज 17,000 से 24,000 रुपए है, यह हाइएस्ट इंडियन रूट्स में है। अगर कम्पेयर किया जाए तो दिल्ली-गुवाहटी, 3 घंटे 15 मिनट की एयर जर्नी का एयर फेयर 6500 है जबकि चैन्नई से पोर्टब्लेयर और कोलकाता से पोर्टब्लेयर, दो घंटे की एयर जर्नी का एयर फेयर 17,000 से 24,000 रुपए है। इससे मुश्किल हो रही है। द्वीप के जो लोग हैं उन्हें टिकट खरीदने में मुश्किल आ रही है, खास तौर से जो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की थी वह इससे सफर हो रही है। खासकर सिंगापुर, कोलम्बो रिटर्न जर्नी टिकट 13 हजार से 17 हजार रुपये का है। इस कारण से अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में एयर इंडिया के माध्यम से टूरिस्ट्स नहीं आ रहे हैं। टिकट्स होते हुए भी टिकट्स ब्लैक हो रहे हैं। वहां दो सैक्टर्स में ऐसा हो रहा है - कोलकाता-पोर्टब्लेयर, चेन्नई-पोर्टब्लेयर। मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं, 21 जून को मैं सफदरजंग में गया, वहां ...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप उनका नाम मत लीजिए।

श्री विष्णु पद राय : मैंने उनसे रिक्वैस्ट की थी कि हमारे कम्पेनियन चेन्नई से पोर्टब्लेयर आये, उन्होंने एस.एम.एस. किया, बात की, लेकिन कहा गया कि टिकट नहीं है। 21 जून और 22 जून दो दिन में चार-चार टिकट चेन्नई एयरपोर्ट से बेचे गये।

सभापति महोदय : इसमें से नाम निकाल दीजिए।

श्री विष्णु पद राय : अजीब बात है कि 22 तारीख की फ्लाइट में चार-चार सीटें 1सी, 1डी, 2एफ. और 10ई आईं, वहां टिकट होते हुए ब्लैक चल रहा है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के समय वहां वीकली दो-तीन स्ट्रेचर पेशेन्ट होते हैं, जैसे कोई कोमा में चला गया, किसी का सिर फट गया, उसे ट्रीटमैन्ट के लिए साउथ ग्रुप में जाना पड़ेगा। मैं 1999 में एम.पी. था,

---

* Not recorded

तब स्ट्रेचर पेशेन्ट्स के लिए 6 टिकट थे, जो एक टिकट कर दिया। उसकी कीमत 6 से 8 हजार रुपये कर दी। यूपीए सरकार आई, उसने दोबारा 6 टिकट कर दिए। लेकिन आज उसकी कीमत 90 हजार रुपये है। पेशेन्ट स्ट्रेचर में हैं, वह 90 हजार रुपये टिकट के देगा तो इलाज कहां से करेगा। उसे देखते हुए किंगफिशर ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में अपना लूटने का तरीका शुरू कर दिया। उन्होंने नौ टिकट कर दिये, जिसकी कीमत 1 लाख 82 हजार रुपये है।

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बताइये।

श्री विष्णु पद राय : मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से मांग करता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह का जो कोटा चेन्नई से पोर्टब्लेयर, कोलकाता-पोर्टब्लेयर उसे रिस्टोर करे और सस्ते दामों पर टिकट दे, जो दिल्ली, कोलकाता में चल रहा है, उसे देखते हुए हमारे यहां के टूरिज्म को बचाये और स्ट्रेचर पेशेन्ट के लिए सिंगल टिकट जो वाजपेयी सरकार ने किया था, वह अंडमान निकोबार के लिए करे।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अमरीका की एक बीयर कंपनी ने बीयर की एक ब्रांड की बोतल के ऊपर गणेश जी का चित्र छापा है, जिसकी वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए अमरीकन कंपनी की बीयर की बोतल के ऊपर हिंदुओं के आराध्य देव गणेश जी की जो तस्वीर छापी गई है, वह दुनिया भर में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हिंदुओं के आराध्य गणपति बाबा का चित्र बीयर की बोतल पर छापने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, इस ढंग से सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): This is a very serious matter which I am raising in this House during this late hour. The matter relates to Madras High Court where an hon. Judge has disclosed that a Union Minister had tried to influence him in granting anticipatory bail to two persons. This is a grave offence and it needs a thorough probe to ferret out the truth. As the Chief Justice of Supreme Court of India has left it to the Government to look into the matter, I urge upon the Government to state what step is being taken in this regard. The Prime Minister’s credentials are above board. But can he be unmindful of the fact that a slur on the Government cannot but be seen as a slur on its Minister?

MR. CHAIRMAN : Now, hon. Member, Shri R. Dhruvanarayana—Not present.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you hon. Chairman, Sir. I would like to raise a very important matter related to Justice Liberhan Commission's report. It is well known that a deliberate vandalism was brought upon the centuries old monument like the Babri Masjid. It was a direct blow on the secular character of our Indian Constitution. This sort of vandalism and destruction took place on 6th December, 1992. This sort of action merited exemplary punishment for all those involved in the frenzied attack and the conspiracy that preceded it.

But it is amazing that the report was submitted to the Government after 16 years, with 399 sittings and 48 extensions. It is not only that but I am referring to other matters in this context. In 1987 a massacre of innocent Muslims in Mallian and Hashimpura took place. The report came 20 years later.

My point is that this is not the only duty of the Government to set up the Commission but ….

MR. CHAIRMAN : Your demand is to lay the Report. Is it so?

SHRI PRABODH PANDA : It is not the only duty. Commissions are being set up one after another. But it is not desirable that all the reports will come out only depending on the wish of the hon. Justices.

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

SHRI PRABODH PANDA : I think that the Government should think over it for enacting a legislation in this context so that in the days to come, in the period to come, no such incident will happen and the Government will take immediate steps after this sort of vandalism and communal tensions happen.

MR. CHAIRMAN : Thank you. Now I invite Dr. G. Vivekanand to speak – not present.

Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 6th July, 2009 at 11 a.m.

18.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 6, 2009/Asadha 15, 1931 (Saka).